

**Motion for consideration of Finance (No. 2) Bill, 2024 moved by Smt. Nirmala Sitharaman (Inconclusive)**

**HON. CHAIRPERSON:** Now, item No. 13, Shrimati Nirmala Sitharaman.

**THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** I beg to move:\*

?That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2024-25, be taken into consideration.?

**HON. CHAIRPERSON:** Motion moved:

?That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2024-25, be taken into consideration.?

Now, Dr. Amar Singh.

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : मैडम, अभी माइक पूरी तरह चला नहीं है । ? (व्यवधान)

सभापति महोदया धन्यवाद । मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से फाइनेंस बिल पर बोल रहा हूँ । फाइनेंस बिल बेसिकली टैक्सेशन से संबंधित होता है कि कौन सा टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स छूटता है और क्या होता है ।

अगर हम यह बजट देखें और जो सरकार ने प्रपोज किया है, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा है कि सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, कॉमन आदमी से किसी न किसी टैक्स के माध्यम से एक-एक रुपया ले लिया जाए और इस मुल्क के जितने अमीर लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनको छूट दे दी जाए ।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे यह केंद्र सरकार कार्य कर रही है । अब इनकम टैक्स को ले लें । यदि इनकम टैक्स को देखें, चाहे टोटल अमाउंट देख लें, चाहे परसेंटेज देख लें, इनकम टैक्स वह टैक्स है, जो इंडीविजुअल्स पर लगता है । यह टोटल टैक्सेज़ का 19 परसेंट है और कॉरपोरेट टैक्स 17 परसेंट है । क्यों जी? इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया? कॉरपोरेट टैक्स की ग्रोथ आपके दस सालों में 2.3 परसेंट हुई है, 4.28 लाख करोड़ रुपए से 10.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है । जबकि, इनकम टैक्स में आप लोगों के 4.5 परसेंट पर-एनम टैक्सेज़ इनक्रीज़ हुए, in the same period from Rs. 2.5 lakh crore to Rs. 11.8 crore.

कॉरपोरेट टैक्स, as a percentage of GDP, 3.4 परसेंट से 3.1 परसेंट हो गया । इनकम टैक्स 2.1 परसेंट से 3.5 परसेंट हो गया । आप तो हर तरीके से इंडीविजुअल वाले टैक्स को ऊपर कर रहे हो और कॉरपोरेट टैक्स को नीचे ला रहे हो । ? (व्यवधान) आपकी सरकार किसके लिए काम कर रही है? ? (व्यवधान) वर्ल्ड इनइक्वैलिटी

लेब की रिपोर्ट है कि जो इंडिया के एक परसेंट अमीर हैं, उनके पास 22 परसेंट इनकम है और 40 परसेंट वैल्यू है। यह आपके पिछले दस सालों में हुआ है। आप देख लो कि आप यह क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

मैं इनकम टैक्स के कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया है? बहुत सारी चीजें जैसे डिडक्शन फीस सरचार्ज पर होती है, फलाना होती है। मैडम वित्त मंत्री बैठी हैं। पांच करोड़ रुपए से ऊपर वाली इनकम का सरचार्ज 37 परसेंट से 25 परसेंट कर दिया, बाकी तो किसी का कम नहीं किया? इसका मतलब जिनकी हायर इनकम है, उनका आप फायदा कर रहे हो।

जितनी एग्जम्पशंस थीं, 80(c) में जो डेढ़ लाख रुपए की एग्जम्पशन थी, जो पर-इंश्योरेंस और फलाना-फलाना करते थे, सारी खत्म कर दीं। 25,000 रुपए का फायदा दिया है कि नए टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए के बजाए 75,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स, इंप्लॉयमेंट वाला टैक्स, एचआरए पर, हाउस-लोन पर बहुत सारा, एक लाख, दो लाख रुपए का इंटरेस्ट-वेवर मिलता था, वह सारा भी खत्म कर दिया। आप लोगों ने जो इंप्लॉयज कॉन्ट्रिब्यूशन वाली डिडक्शन होती थी, वह भी खत्म कर दी। मेडिकल इंश्योरेंस वाला भी खत्म कर दिया है।

आपने कौन सी चीज छोड़ी है? एफडीआई, जो बाहर से आ रहा है, कारपोरेट ला रहा है, उसे आपने कम कर दिया है। हर चीज पर आप इस तरह से काम कर रहे हैं। किसी भी हालत में, अच्छा 80 साल की जिनकी उम्र है, उनके लिए बेसिक टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट पहले रिजीम में 5 लाख रुपये की होती थी, आपने वह लिमिट 3 लाख रुपये कर दी है। आपने बूढ़े लोगों को क्या राहत दी है? हम सभी लोगों को बूढ़ा होना है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी को एक सुझाव है। देखो 70 परसेंट आपके आईटीआर निल वाले होते हैं। हिन्दुस्तान की दो परसेंट पॉपुलेशन टैक्स दे रही है। 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को छोड़ दीजिए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उसी से पब्लिक कंजम्पशन बढ़ेगी, इस मुल्क में गरीबी कम होगी। आप मेरा यह सुझाव मान लीजिए।

अब हम आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास, सैलरीड वालों को इतने पर ही नहीं छोड़ा। आपने कैपिटल गेन टैक्स में दोनों तरफ उनको मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन पर भी उनको मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन साल भर का होता है। लांग टर्म गेन पर भी उनको मार दिया। आपने दोनों तरफ उनको मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन पर आपने 15 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट टैक्स कर दिया। लांग टर्म में तो बहुत ज्यादा नुकसान है। वह इंडेक्सेशन जो प्रॉपर्टी, गोल्ड, अदर एसेट्स पर था, वह सारी खत्म कर दी है। उस पर लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यह केंद्र सरकार किधर जा रही है? जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सैलरीड क्लास है, जो छोटा-मोटा काम करने वाला है और यही नहीं, आपने ऑप्शंस और फ्यूचर्स पर भी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। इस तरह से ये क्लासेज किधर जाएंगी? ये मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास के लोग किधर जाएंगे, जो बेचारे ऑप्शंस लेते हैं, फ्यूचर्स लेते हैं? इनका तो आपने हर जगह नुकसान किया है।

वित्त मंत्री जी, मेरा कहना है कि इन सारी चीजों पर आप री-थिंक कीजिए। इन सबसे सैलरीड क्लास, मिडिल क्लासेज का नुकसान हुआ है, रिच को आप फायदा कर रहे हैं। कारपोरेट टैक्स फॉरगॉन आपका अपना इन्फर्मेशन है। इसी बजट में वेरियस स्कीम्स में 1,09,333 करोड़ फॉरगॉन रेवेन्यू की वर्ष 2022-23 में फिगर दे रहे हैं। पिछले 5 साल में, मैं कम्पाउंड नहीं कर रहा हूँ, 1.7 लाख करोड़ फॉरगॉन रेवेन्यू है। आप रिलैक्सेशन इसलिए देते हो कि जॉब्स क्रिएट होंगी। बेरोजगारी की तो हिन्दुस्तान में इतनी बुरी हालत है, सीएमआईई पिछले साल कह रहा था कि 45 परसेंट अनएंप्लॉयमेंट है। अभी भी 8-9 परसेंट अनएंप्लॉयमेंट है। जो कारपोरेट को

देते हैं, हमारी आपसे विनती है कि कृपा करके हमें बताइए कि कारपोरेट्स का जो टैक्स छोड़ा है, उससे कितनी नौकरियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि यह वाला काम नहीं चलेगा कि आप छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ और कोई उसका हिसाब-किताब न लें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क की बेसिक प्रॉब्लम है। आपका तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि that 78.5 lakh jobs will have to be created in non-farm sector annually. आप कितनी जॉब्स पैदा कर रहे हैं? डीओपीटी की तरफ से तो अभी सूचना आयी थी कि 7.2 लाख नौकरियों के लिए 2.2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। आप बेरोजगारी का हिसाब-किताब लगा लीजिए कि वह कितनी है।

हमें इस बजट में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई रिलीफ चाहिए। नॉट ओनली दैट, मैडम क्रिसिल की रिपोर्ट है that household savings has come down to 18.4 per cent of GDP in 2023-24. यह डीकेडल लो है, हाउसहोल्ड सेविंग्स 20 परसेंट से कम कभी नहीं गई थी। Household financial liability is at an all-time high at 5.8 per cent. आप हमें बताइए कि ये दो चीजें क्या बताती हैं? ये यह बताती हैं कि डे-टू-डे एक्सपेंडिचर में मेरे हाउसहोल्ड को बहुत तकलीफ है और कंजमशन इसलिए इंक्रिज नहीं हो रही है, क्योंकि लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। आप हमें कुछ बात बताइए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि न अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ है, न हाउसहोल्ड कंजमशन पर कुछ है, किसी चीज पर कुछ नहीं है।

माननीय सभापति महोदया हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या बात है? इन्होंने बजट में इंप्लेशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। डब्ल्यू.पी.आई. 3.1 परसेंट, रिटेल 5.5 परसेंट और फूड इंप्लेशन तो करीब-करीब 10 परसेंट है। इसका क्या करना है? यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। आपने बताया ही नहीं कि फूड इंप्लेशन को कैसे कम करेंगे? मैडम जब जवाब देंगी, तो इस बारे में जरूर बताएं।

महोदया, अब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करना चाहूंगा। आज भी देश की 50 परसेंट पापुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 18.4 परसेंट इनकम जीडीपी का हिस्सा है। इसका मतलब 50 परसेंट पापुलेशन सिर्फ 18 परसेंट इनकम पर जिंदा हैं और इसी वजह से किसानों और लेबर को इतनी मुश्किलें हैं चाहे वे आत्महत्या कर रहे हैं या आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तकलीफ में है। आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि पिछले साल 4.7 परसेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में थी और वर्ष 2023-24 में 1.4 परसेंट है। सरकार के इतने सारे वायदे कहां गए? ग्रोथ कम होने से एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी परेशानियां हो रही हैं। आपका वायदा था कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे। उसका क्या हुआ? आपका सर्वे था कि वर्ष 2018-19 में किसानों की इनकम 10218 रुपये हर महीने थी। अब तक किसानों की हर महीने की इनकम 22 हजार या 25 हजार रुपये हो जानी चाहिए थी।

मैडम, आप कृपया हमें जरूर बताएं कि आज किसानों की प्रति माह कितनी इनकम है? नवम्बर, 2021 में किसानों के एजिटेशन के समय माननीय प्रधान मंत्री जी एक दिन रेडियो पर बोलते हैं कि किसान भाइयों, आप बार्डर से उठ जाएं। मैं आपको एमएसपी का हल करके दूंगा। हम इस बारे में पक्का हल करेंगे। यह नवम्बर, 2021 की बात है और आज आप देखें कि कितना समय हो गया है। उस वायदे का क्या हुआ? माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे कह रहे हैं कि मैं किसानों से चर्चा करूंगा। किसानों की मांग बहुत स्पष्ट है कि एमएसपी लॉ बनाकर दो। आप इस बात को कहते ही नहीं हैं। मंत्री जी, आप कहिए कि आप एमएसपी लॉ बनाएंगे। संसद सत्र चल रहा है। यह बहुत अच्छा मौका है, आप सदन में कह दीजिए कि एमएसपी लॉ बनाएंगे। मंत्री जी मुझे जानते हैं, आप मेरे बोलने के बाद बोल दीजिएगा।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप चेयर को सम्बोधित कीजिए ।

डॉ. अमर सिंह : महोदया, मैं माफी चाहता हूँ ।

महोदया, एक बहुत विचित्र स्थिति हमारे सामने है । वर्ष 2015 में ढोल धमाके के साथ ब्लैक मनी एक्ट बनाया । बहुत अच्छी बात है कि जो काला धन विदेशों में है, उसका एक-एक पैसा देश में वापस लेकर आएंगे । हालांकि बाद में कह दिया कि हमने ऐसे ही कहा था, वह बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ । आपने अब कहा कि बाहर कोई 20 लाख रुपये तक का ऐसेट बनाए, तो उसके लिए सूचना देने की जरूरत नहीं है । क्या यह कंट्राडिक्शन नहीं है? पहले आप कह रहे थे कि एक-एक पैसा वापस लेकर आएंगे लेकिन अब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपये तक के ऐसेट खरीदने पर जानकारी देने की जरूरत नहीं है ।

महोदया, अब मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ । मैं कई बार सदन में इस विषय पर बोल चुका हूँ । मैं उस पवित्र स्थान से आता हूँ जहां हमारे दसवें गुरु के दोनों छोटे साहबजादों को औरंगजेब के जमाने में जिंदा नींव में चिन दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम धर्म नहीं बदलेंगे ।

यह वर्ष 1705 की घटना है और अब इसके 318-319 साल हो गए हैं । पर, अभी भी 50 लाख से एक करोड़ लोग 25-26-27 दिसम्बर को हर साल सिजदा करने आते हैं । मैं बार-बार यह कहता हूँ कि जो रिलिजियस स्प्रिचुअल प्लेसेज़ हैं, उनको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में लीजिए और वहां इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट वाली फैसिलिटीज़ दीजिए । इतनी पवित्र जगह बहुत कम होंगी । हिन्दुस्तान के इतिहास में यह घटना प्रसिद्ध है । उस समय छोटे साहबजादों ? बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ? की उम्र 9 साल और 7 साल थी । पर, उन्होंने अपने धर्म नहीं बदले । मेरा यह कहना है कि वहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट की जगह दीजिए, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ दीजिए । ये सब वहां करने की जरूरत है ।

इसी तरीके से, मेरी कंस्टीट्युन्सी में कुछ एम.एस.एम.ई. क्लस्टर्स हैं । मैंने एक-दो बार मिल कर भी इसके बारे में बात की है । जी.एस.टी. से संबंधित उनकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं । उनकी प्रॉब्लम्स स्पेशल पैकेज की है । वहां मंडी गोबिंदगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है । उसे ?स्टील टाउन? कहते हैं । वहां खन्ना है, दोराहा है, साहनेवाल है । इन सारी जगहों पर एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्रीज़ हैं । लुधियाना के एम.पी. साहब पीछे बैठे हैं । वहां के लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं । वे एक बहुत छोटा-सा सजेशन देते हैं । जो स्टील इंडस्ट्री वाले हैं, वे स्कैप से, सेकेन्डरी सोर्स से स्टील बनाते हैं । इनके पास प्राइमरी सोर्स आयरन-ओर नहीं है । वे कहते हैं कि स्कैप पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. है । आप हमसे ले लीजिए, क्योंकि स्कैप वाला बेच कर गायब हो जाता है और फिर आप उसकी रिकवरी हमसे करते हैं, इसलिए आप हमसे सीधा ही उतना टैक्स ले लीजिए । आप उस चिंता में क्यों पड़ते हैं, ऐसा उनका कहना है ।

दूसरी बात, मैं यह मांगता आया हूँ कि मेरे यहां एक मेडिकल कॉलेज दीजिए, एक ट्रॉमा सेन्टर दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दीजिए । मैं ऐसी बहुत सारी मांग रखता हूँ, पर मेरी कोई मांग मानी नहीं गयी है ।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस फाइनेंस बिल में आपने जितने टैक्सेशन प्रोपोजल्स दिए हैं, इसमें अगर कोई भी प्रोपोजल कॉमन मैन के लिए हो, तो उसे आप अपने जवाब में बता दीजिएगा । ये सारी की सारी ?रिच? को सुविधा देने के लिए है, और गरीबों के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए इस बिल में कुछ नहीं है ।

मैडम, मैं इसका विरोध करता हूँ ।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद ।

महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के इतने ऐतिहासिक बजट के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज 6 अगस्त है । स्पीकर साहब ने हिरोशिमा और नागासाकी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी । दूसरी श्रद्धांजलि मैडम सुषमा स्वराज जी को है, जिनकी आज पुण्य तिथि है । जब मैं पहली बार यहां सांसद बन कर आया तो लीडर ऑफ ऑपोजीशन के नाते उन्होंने हमारे जैसे लोगों को बढ़ाने का काम किया और उसी कारण से आज मैं पार्टी के आदेश के अनुसार, प्रधान मंत्री जी के कारण इस फाइनेंस बिल पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदया, मैं सोचता था कि कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन हैं, या जो वक्तव्य देने वाले हैं, वे फाइनेंस बिल पर चर्चा करेंगे, वे देश की स्थिति के बारे में बताएंगे, हमारी सरकार ने क्या बुरा किया, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन जैसा कि कांग्रेस एक कन्फ्यूज्ड पार्टी है तो उस कन्फ्यूज्ड पार्टी की तरह ही कन्फ्यूज्ड वक्ता रहे ।? (व्यवधान) फाइनेंस बिल पर कांग्रेस पार्टी को उनका समय ?कट? करना पड़ा और अब दूसरे मेम्बर बोलने के लिए खड़े होंगे ।? (व्यवधान)

सभापति महोदया, आज स्थितियां कैसी हैं, मैं यह देख पा रहा था । मैं ?डिरेल? नहीं होना चाहता ।? (व्यवधान) आज पूरी दुनिया की स्थिति क्या है? अगर वर्ल्ड बैंक की, आई.एम.एफ. की, फोर्ब्स की, अमेरिका की, जिनकी नीतियों से कांग्रेस बहुत प्रभावित रही है, यदि उनकी रिपोर्ट्स को देखें तो पूरी दुनिया में 2.5 प्रतिशत से लेकर 2.7 प्रतिशत ही जी.डी.पी. बढ़ रही है । पूरी दुनिया कराह रही है । आप लंदन जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, आप वाशिंगटन जाइए, आप पूरे यूरोप जाइए, सारी दुकानें बंद होती नज़र आएंगी । बेराज़गारी की भयंकर सीमा है । इनफ्लेशन का रेट, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आठ पर्सेंट से कम इनफ्लेशन है । पूरी स्थिति खराब है । चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, फिसकल डेफिसिट हो, जिस भी पैमाने पर आप पूरी दुनिया को आँकने का काम करेंगे, आपको लगेगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी की नीतियां इस देश के लिए इतनी सक्सेसफुल हैं कि आज भी भारत पूरी दुनिया में आशा की किरण है और सात पर्सेंट से अधिक जीडीपी ग्रोथ है ।

सभापति महोदया, हम धर्म के मानने वाले लोग हैं । जो धर्म कहता है, उसी के आधार पर हम चलते हैं । हमारे धर्म में एक बड़ा श्लोक है कि :-

?कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी ।

सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी॥?

अर्थात् भगवान सभी कालों में, सभी भगवान में, सभी गरीबों में एक ऐसी ऊर्जा का संचरण करते हैं, जिसके कारण दुनिया में गरीब कैसे खत्म होंगे, भारत में गरीब कैसे खत्म होंगे, उनको अमीर कैसे बनाया जाएगा, इसी पॉलिसी के आधार पर भारत सरकार चलती है, इसी पॉलिसी के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है ।

सभापति महोदया, किसान बिल की बात हो रही है और उस दिन मैंने बजट पर माननीय एलओपी, जिनके लिए मैंने सोचा कि क्या संबोधन दिया जाए, तो मैंने ...\* सोचा है । ... \* की जो ज़बान होती है, उसको जो पढ़ाया-लिखाया जाता है, वही उसको बोलना है और इस बजट पर चर्चा करते-करते अमर सिंह साहब भी वही चर्चा कर गए । शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ कि यदि कोई ऐसा शब्द आया है, तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ आप बैठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप भी सुनिए कि यदि कोई सदस्य बोल रहा हो तो बैठे-बैठे कमेंट्स मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह जो भी शब्द आया है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदया, आज हम क्या कर रहे हैं? हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ा प्रयोजन है कि जो फॉरन फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट है, एफडीआई में जो कॉर्पोरेट आते हैं, हम इकोनॉमी में जा रहे हैं, आरएण्डडी में जा रहे हैं, नई-नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं । यदि वे कंपनियां हमारे देश में इनवेस्ट करना चाहेंगी, तो उनके टैक्स को हमने कम किया है । और वह टैक्स हमने कम क्यों किया? क्योंकि हमारा मुकाबला सिंगापुर से है । हमारा मुकाबला अबु धाबी, यूएई, आदि देशों से है, जहां कॉर्पोरेट टैक्स 20-22 पर्सेंट से ज्यादा नहीं है और कई जगहों पर तो टैक्स ही नहीं है । उस इंडस्ट्री को जब बैठना है, जब वह इंडस्ट्री आएगी, तो यहां के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, मेक इन इंडिया में जाएगा और जो वर्ष 2047 का एक संकल्प है कि हमको एक विकसित भारत बनाना है, जो वर्ष 2027 का एक संकल्प है, जो फॉर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2027 तक ऐसा संभव है कि भारत जिस इकोनॉमी के साथ बढ़ रहा है, हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे । उसमें यह जो राइडर है, जिस पद पर सभापति महोदया, उन्होंने बोलते हुए, जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, यह मैं आपको बताऊंगा । वे क्या कहते हैं? वे महाभारत को गलत कोट करते हैं । वे रामायण को गलत कोट करते हैं । वे शिव को गलत कोट करते हैं । उसके बाद वे कहते हैं । ? (व्यवधान)

वह कहते हैं कि हम अराजकता फैलाएंगे, तुमको जो करना है, करो । अनुराग सिंह ठाकुर जी ने उस दिन जो बात कही, मैं उससे कंप्लीट सहमत नहीं हूँ । मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से इस सदन में माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्यों, इसीलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने उनके ऊपर जाति का आरोप लगाया, लेकिन जाति तो है ही नहीं । आप यह समझें, वह कहते हैं कि जो मैं हूँ, वही दिखता हूँ । मैं जो दिखता हूँ, वह मैं नहीं हूँ, तो वह साधू है । इस देश में कहा गया है कि जाति न पूछो साधू की । साधू की जाति नहीं पूछना है । जब साधू की जाति नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी कि उनसे जाति पूछ लिया ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन से जवाब पूछना चाहता हूँ । आप यह बताइए कि इस देश में कई एक ऐसे लोग हैं, जिनको धर्म में आस्था नहीं है, कई एक ऐसे लोग हैं, जिनको जाति में आस्था नहीं है तो वह किस तरह से जातिगत जनगणना करेंगे? जिस पद पर राम सुभग सिंह, चरण सिंह,

जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के बड़े-बड़े लोग रहे, जिस जगह पर शरद पवार जैसे लोग रहे, वाई.बी.चव्हाण जैसे लोग रहे, उस जगह की गरिमा का आप इस में बजट में अराजकता फैला कर, इस बजट का नकारात्मक पहलू दिखा कर हरैसमेंट कर रहे हैं। आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इसी बजट में जाता है, यही टैक्स है। इसी टैक्स के आधार पर जाता है।

सभापति महोदया, आज मैं बहुत कुछ चीज लेकर आया हूँ। मैं वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1990 तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूँ। यदि आप कहेंगे तो मैं ले कर दूंगा। उस दिन वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेहरू ने यह कह दिया, राजीव गांधी ने आलोक मेहता को इंटरव्यू दे दिया। इसे तो इंडिविजुअल कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी का वह अलग से विषय था। राजीव गांधी जी का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं था या नेहरू जी का पार्टी से लेना-देना नहीं था। ये बार-बार कह रहे हैं कि कई एक चीजें हमने कांग्रेस के न्याय-पत्र से लिया है। यदि कांग्रेस के न्याय-पत्र से लिया तो यह पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है, वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1990 तक का मैंने पूरा असेसमेंट किया। इसमें आपको आश्चर्य होगा कि पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1989 में और वर्ष 1991 में, इन सभी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। आप ओबीसी की बात करते हो, मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस ने किसी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज तक किसी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। बिहार में दरोगा राय जी को छोड़ कर किसी एक भी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। जब भी ओबीसी की बात आई, यदि दरोगा राय जी ने रिजर्वेशन दिया तो उनको आपने अलग किया। वर्ष 1977 में जब चरण सिंह रिजर्वेशन देना चाहते थे तो आपने उनकी सरकार गिरा दी। आपने वर्ष 1989 में वी.पी. सिंह जी की सरकार गिरा कर चंद्रशेखर जी की सरकार बना दी। जब गुजराल साहब ओबीसी की जनगणना कराना चाहते थे, तो आपने वर्ष 1997 में उनकी सरकार गिरा दी।? (व्यवधान) आप ओबीसी रिजर्वेशन के पिच पर खेल रहे हो। आज इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, चायवाला है, बैकवर्ड है। यदि वह ओबीसी सुरक्षा की बात करते हैं, वह ओबीसी सरकार की बात करते हैं, तो आप ओबीसी-ओबीसी करते हैं। इसीलिए, ओबीसी के बारे में कांग्रेस का कोई मुंह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कृष्ण की तरह जो एजेंडा सेट किया है, आप उसके चारों तरफ बिल-बिला रहे हो। अपोजिशन की सारी पोलिटिकल पार्टीज कौरव की तरह प्रधानमंत्री की एजेंडे पर ओबीसी-ओबीसी चिल्ला रही हैं। यदि आप में ताकत है, तो वर्ष 2011 में जो ओबीसी रिजर्वेशन कराया गया, वह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। यदि आप में ताकत है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, पिछले दो सालों से सरकार है। वहां सोशियो-इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो गया है, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाया? आपने इसलिए नहीं करवाया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो ऐसे धर्म हैं, जो जाति की बात नहीं करते हैं। उसमें 86 जाति क्रिश्चियन्स की और 56 जाति मुसलमानों की हैं।

आप उनको बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से मुसलमानों और क्रिश्चियन्स को ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहते हैं, इसलिए आपकी हैसियत नहीं है। आप इसीलिए जातिगत जनगणना की बात करते हो। यदि हिम्मत है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो कर्नाटक में वह ओबीसी रिजर्वेशन करके दिखाये तो मैं मानूंगा कि आप हाउस में जो बात करते हो, उसे मानते भी हो।? (व्यवधान)

मैं कांग्रेस का बहुत सम्मान करता हूँ, गांधी फैमिली का, यह है भी। मान लीजिए कि भारत का बटवारा हो, नेहरू जी की देन है, तिब्बत से यदि हम जूझ रहे हैं, नेहरू जी की देन है। यदि चाइना हमारे पास तक आ गया, नेहरू जी की देन है।? (व्यवधान) एस्मा वर्ष 1968 में आ गया। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सरकारी अधिकारी आंदोलन करना चाहते थे, तो आप एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट ले आए, इमरजेंसी आप लेकर आए, ऑपरेशन

ब्लू स्टार आप लेकर आए, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स आपने भेज दी, टू जी, थ्री जी, फोर जी सब आपने किया, इसलिए मैं आपकी गांधी फैमिली का बड़ा सम्मान करता हूँ। बजट में जो आपने बोला, वह मेरे लिए बड़ा अच्छा है।? (व्यवधान)

सभापति महोदया, इस बजट में हमने एंजेल टैक्स खत्म किया, 56(2)? (व्यवधान) वर्ष 2012 में?\* साहब ने एंजेल टैक्स लगाया 56(2)। इसका कारण था। होता क्या था कि?\* जी के बीच इतनी लड़ाई थी कि वित्त मंत्री के आफिस और घर में बगिंग हो रही थी।? (व्यवधान)

**SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT):** Madam, he cannot take names of Members who are not Members of this House. ? (*Interruptions*) One is a former President of India who is no longer with us. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, वित्त विधेयक पर चर्चा करें।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : ज्यादा बढ़िया बनने के चक्कर में उन्होंने एंजेल टैक्स लगा दिया।? (व्यवधान)

**SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT):** He is talking about a deceased former President of India. ? (*Interruptions*) This is the kind of respect that the BJP has. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे : एंजेल टैक्स क्या है? माननीय प्रधान मंत्री जी स्टैंड अप की बात करते हैं, स्टार्ट अप की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। माननीय तोता महाराज, लिप्स ऑफ पैरट, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये गुस्सा जाएंगे। हमने देखा कि कहां से बजट आता है, कॉर्पोरेशन का कितना टैक्स आता है, इंकम टैक्स कितना आता है, जीएसटी कितना आता है, हमारी देनदारी क्या है, उधार क्या है, यह पूरे फाइनेंस बिल का टैक्स स्ट्रक्चर है। उसमें 8 पर्सेंट के आसपास ऐसा पैसा है, जो डिफेंस को जाता है। आज तक डिफेंस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इस हाउस में नहीं हुई कि हम इस टैक्स से सेस लेते हैं, सरचार्ज लेते हैं तो डिफेंस में पैसे देते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सारे अपोजीशन के लोग अग्निवीर स्कीम के ऊपर लगातार बजट में बोलते रहे। चूंकि एंजेल टैक्स लगाया है, युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको रोजगार दिया जाए। इसको एबॉलिश किया है, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लड़के रोजगार में आएंगे।

मैं इसकी तह पर गया तो पता लगा कि यह कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1962 में जब चीन ने भारत को हरा दिया और लगा कि फोर्स की कमी है तो भारत में वर्ष 1962-63 में नेहरू जी शॉर्ट सर्विस कमीशन लाए। ऐसा नहीं है कि केवल फौज के लिए अभी 5 साल की अग्निवीर स्कीम आई है। इसके पहले भी इस देश में वर्ष 1962 में शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में मैंने पार्लियामेंट की सारी डिबेट को पढ़ा। मैं आपको बताऊं कि जो अफसर जॉइन करते हैं, उनकी नौकरी 5 साल से 10 साल होती है और अब वह 14 साल हो गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोक सभा में या राज्य सभा में या सदन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं किया कि यह शॉर्ट सर्विस कमीशन बना, जबकि सर्विस तो एक ही है। आर्मी में भी जो अफसर ग्रेड के लोग हैं, उसमें एक ग्रेड ऐसा है, जो परमानेंट चलता है, जबकि दूसरा ग्रेड ऐसा है, जो शार्ट सर्विस कमीशन में 10 सालों के लिए चलता है।



किसी पॉलीटिकल पार्टी ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन आज हो रहा है, करे कोई भरे कोई । वर्ष 1992-93 में ऐस्टिमेंट कमेटी की रिपोर्ट है, यहां रिपोर्टें आती हैं, बनती हैं, चली जाती हैं । आपको आश्चर्य होगा, वर्ष 1966 की एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसे सदन और देश को जानने की जरूरत है । यह रिपोर्ट लेकर आया हूं, कोई भारत सरकार का कागज लेकर नहीं आया हूं । वर्ष 1966 में इंदिरा जी ने आर्मी की रिक्रूटमेंट पर सिलिंग लगा दी, कमेटी ऑफ ऐस्टिमेंट को कांग्रेस पार्टी के मनोरंजन भक्त हेड कर रहे थे । वर्ष 1966 में सिलिंग लग गई, सीलिंग लगने के बाद आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे यहां इतनी ही आर्मी रहेगी, इतनी ही नेवी रहेगी, इतनी ही एयर फोर्स रहेगी ।

आप सीलिंग लगा दो, आप हमको कहो कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा, यदि आप फोर्स को बढ़ाना चाहो? सीलिंग के बाद उसी कमेटी की रिपोर्ट है, वर्ष 1975 और 1989 में दो कमेटीज और बनायी गई । आर्मी को यंग कैसे रखा जाए । एक छोटा सा उदाहरण है, शार्ट सर्विस कमीशन जब बनाया गया था, उस शार्ट सर्विस कमीशन में भी यूपीएससी, राज्य सभी जगह रिजर्वेशन दिया गया था । उसका प्रभाव यह था कि इस देश के होम सेक्रेटरी वी.के.दुग्गल हुए, वह भी शार्ट सर्विस कमिशन से आए और उसके बाद वह आईएएस बने । इन्होंने मैनपॉवर के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद कहा कि आपको पांच और सात साल के लिए, यह वर्ष 1975 की बात है, ध्यान रखिए । वर्ष 1975 से लेकर आज तक 2019-20 लगभग 40-45 साल तक जो रिपोर्ट है, वह गड्डे में रही, मैनपॉवर की कमी रही है, न आर्मी में आदमी रहा, न नेवी में आदमी रहा, न अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ । आज यदि आर्मी के कहने पर वह रिपोर्ट इम्प्लिमेंट हो रही है तो आप युवाओं को देश के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हो या हमारे यहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से अराजकता हो रही है, जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ सारे लड़के रोड पर आ रहे हैं, आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? यह दूसरा सवाल है । बच्चों पर एंजल टैक्स हटाकर, कॉरपोरेट टैक्स 18 परसेंट करके हम बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं । तीसरा, इम्पोर्टेड पाइंट है । मैंने बहुत सुना, ए 1 , ए 2 , मैं भी नाम नहीं लेना चाहता । हमारे ऊपर आरोप है कि हम दो कॉरपोरेट्स की मदद करते हैं । माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी की डीबीटी स्कीम के पहले, भारत में 1952 से भी एक डीबीटी स्कीम है । लाइसेंस परमिट कोटा राज का डीबीटी स्कीम, डी से?\* बी से ?\* और टी से ?\* यही तीन ऐसे लोग थे ।, उसमें ? को भी जोड़ लीजिए, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक, इन्हीं लोगों को करना था, कार वह बनाएंगे, अखबार वह चलाएंगे, सीमेंट वह बनाएंगे, स्टील बनाएंगे ।

जब हमारी सरकार आयी तो ट्रांसपेरेंसी से काम लिया गया । 32-33 लाख करोड़ रुपये टैक्स आता है, पांच सौ कंपनियां, जिनको ये गाली देने की बात करते हैं । भारत में सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर जब यह सरकार चलती है, तो आपके बिजनेसमैन, आप रोटी खाने जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, शादी में जाओ बहुत बढ़िया है, उनसे गिफ्ट लो बहुत बढ़िया है, आपको चुनाव में पैसा दें बहुत बढ़िया है, लेकिन जब गाली देने की बात आए, ऐसा निकृष्ट विपक्ष ही नहीं देखा । जो लेते भी है, खाते भी हैं, गाली भी देते हैं ।

#### **14.00 hrs.**

हमारे लिए तो जैसे आम गरीब इम्पोर्टेड हैं वैसे ही अमीर भी इम्पोर्टेड हैं । ? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : माननीय सभापति जी, मैं एंजल टैक्स की बात कर रहा हूं, कॉरपोरेट टैक्स की बात कर रहा हूं । ? (व्यवधान) आप एंजल टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को कैसे डिरेल कर रहे हैं? ? (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि

आप जिस डबल ?ए? कंपनी के बारे में कह रहे हैं, चार लाख करोड़ रुपये इस देश की किट्टी में दे रही है और उसके कारण यह देश चल रहा है । ? (व्यवधान) क्या आप चाहते हैं कि यह कंपनी बंद हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि वह बैंक बंद हो जाए? आप चंदा भी खाओ, आप उनकी शादी में भी जाओ और फिर उसके बाद गाली भी देते रहो, क्योंकि वे डिफेंड करने वाले नहीं हैं । ? (व्यवधान) अब आप ये काम करो । ? (व्यवधान) इस देश का कौन ऐसा पोलिटिशियन है जो अंबानी की शादी में नहीं गया? ? (व्यवधान) कौन ऐसा आदमी है? ? (व्यवधान) इनकी पार्टी की महासचिव ?\* क्या वह शादी में नहीं गई?? (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं? ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : कोई नहीं गया । ? (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी गए हैं और आप बोल रहे हैं कि कौन गया है? ? (व्यवधान) आप उनका नाम लेंगे । ? (व्यवधान) वह सदन के सदस्य नहीं हैं और दोबारा नाम लिया गया है । ? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, आप महासचिव कहिए । ? (व्यवधान) आप कहिए कि ?\* शादी में गई, इतना मान लीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बजट पर अपनी बात कम्पलीट कीजिए ।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदया, हमने फाइनेंस बिल में एक बड़ा अच्छा पार्ट आता है, पीएमएलए । इस सदन में जितने लोग बोलते हैं, इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, ईडी के बारे में बोलते हैं और सीबीआई के बारे में बोलते हैं । खैर, सीबीआई तो अलग संस्था है । इनकम टैक्स और ईडी महत्वपूर्ण हैं और फाइनेंस बिल में ईडी के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं । मैं जब ?\* की लिप सर्विस की बात कहता हूँ तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ?\* कहते हैं ।

महोदया, यह सदन के जानने लायक चीजें हैं, वर्ष 1988 में राजीव गांधी साहब बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट लाए और वर्ष 1988 से वर्ष 2017 तक 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए । आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा? किसको नहीं पकड़ा । कौन जेल गया? कहां ब्लैकमनी है? कहां व्हाइट मनी है? क्या आपने कभी अपने गिरेबान में झांका है? आपकी सरकार वर्ष 1991 से वर्ष 1996 और वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक रही तो फिर आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम सरकार में नहीं रहे । आप वर्ष 1988 में बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट लाए लेकिन इसे लागू नहीं कर पाए । आप किसका साथ दे रहे थे? ? (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं आपको बताऊं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है । वर्ष 2012 में दिसम्बर महीने में बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में संशोधन हुआ । मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ था और उस तरफ माननीय चिदंबरम साहब थे । वह बहुत फेमस वित्त मंत्री थे । मैंने उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो अपने जीवन में देखा ही नहीं । मैंने कहा कि आप जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, एक दिन यदि वाइफ हसबैंड में लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा । यह जितना स्ट्रिजेंट है, आप जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ । उस जमाने में मेरा सीट नंबर 545 था । मैं अंतिम बोलने वाला सदस्य था, मैं 545 नंबर सीट पर था । जब मैं बोलकर बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है ।

भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी-लिखी पार्टी है। मेरी अपेक्षा यह थी कि पीएमएलए कानून पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख, बुद्धू और दकियानूसी आदमी को, जिसे पीएमएलए पता ही नहीं है, उसे खड़ा कर दिया। ? (व्यवधान) यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसके एफटीएफ में चिदंबरम साहब का जो वर्ष 2012 का स्टेटमेंट है, उसी को क्वोट करते हुए यह रिपोर्ट आई है। जब रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होय। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स क्वोट पर हमारी फाइनेंस कमेटी, जिसमें यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे और मैं उसका मेंबर था, 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स क्वोट को हम लोग बदल दें। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेकर आ गए। ? (व्यवधान) बिना एक पैसा खर्च करते हुए यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपये दे दिए और आपने यंग इंडिया, नैशनल हेराल्ड खरीद लिया। 750 करोड़ रुपये की सम्पत्ति बिना किसी पैसे के आपको मिल गई, ? (व्यवधान) तो क्या राहुल साहब, जो चिदंबरम साहब का कानून, उसमें आप जेल नहीं जाएंगे? ? (व्यवधान)

**SHRI GAURAV GOGOI:** The matter is *sub judice*. The Member cannot raise a matter which is *sub judice*. ? (Interruptions)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर क्वोट कर रहा हूँ, इसीलिए आप सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हैं। यह आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार, माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ऊपर केवल वह उसको इम्प्लीमेंट करती है। हमने अपनी एजेंसी को फ्री छूट दे रखी है। जो भी भ्रष्टाचारी है, वह जेल जाएगा। वह किसी कीमत पर नहीं छूटेगा।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया कम्प्लीट करिए।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदया, इस देश के हालात बहुत अच्छे हैं। हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की कल्पना में हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी से यक्ष-युधिष्ठिर वार्ता में उस दिन बोलते हुए माननीय राहुल जी ने कहा कि छः महारथी थे। ? (व्यवधान) छः महारथी नहीं थे, नौ महारथी थे, जो अभिमन्यु से लड़ रहे थे और सात महारथी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बैठे थे और दो महारथी ऐसे थे, चक्रव्यूह के बार चार पांडवों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे अंदर न जाने पाएं। उसमें भीम, सात्विक, नकुल और सहदेव थे। ? (व्यवधान) उस दरवाजे की रक्षा जयद्रथ कर रहे थे कि वे उसमें नहीं जा पाएं। महाभारत के दूसरे प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा। एक प्रश्न था कि कः पंडित और दूसरा है, को मूर्खः, तीसरा है कः मत्सरः। मैं मूर्ख पर नहीं जाऊंगा, केवल दो ही चीजों पर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है ये अपने पर ले लें, लीडर ऑफ अपोजीशन पर ले लें कि उनको मूर्ख कह दिया। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। पंडित वह है, जो विद्वता की बात करता है। ...\* केवल और केवल डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट, जो हमारे रामायण, महाभारत, गीता का है, वही करते रहते हैं, इसलिए उनको सोचने की बात है कि वह पंडित हैं या नहीं।

महोदया, जो मत्सर है, मत्सर के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जिसको ईर्ष्या, द्वेष, जलन हो, किसी के आगे बढ़ने पर परेशानी हो, उसे मत्सर कहा जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, वह यक्ष-युधिष्ठिर वार्ता का मत्सर है। भारत इतना ग़ो क्यों कर रहा है? भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्यों जा रहा है? भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी वर्ष 2027 में क्यों हो जाएगा? इस कारण से युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ, जातिगत रिजर्वेशन के आधार पर, जिस रिजर्वेशन के आधार पर आज बांग्लादेश जैसा देश जल रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, श्रीलंका खत्म हो रहा है। लीडर ऑफ द अपोजीशन के नाते जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है और जिम्मेवारी कैसे होगी?

सभापति महोदया, जिम्मेवारी नहीं होने के पीछे रीजन हैं। रीजन यह है कि मैं तीन किताबें अभी पढ़कर आया हूँ, वे तीनों किताबें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक किताब अशोक मित्रा ने लिखा है- A Prattler's Tale. अशोक मित्रा साहब बंगाल के सबसे लांगेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इंदिरा जी के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। दूसरी किताब नटर सिंह की है, जो कहता है? One Life is Not Enough और तीसरी किताब संजय बारू की है -The Accidental Prime Minister. ये तीन किताबें हैं और तीनों आदमी, संयोग से अशोक मित्रा साहब को छोड़ दीजिए तो दो आदमी अभी भी हैं।? (व्यवधान) किसी को कांग्रेस ने आज तक कंट्राडिक्ट नहीं किया। तीनों किताबें क्या कहती हैं? अमेरिका तय करता था कि इस देश का वित्त मंत्री कौन होगा। संजय बारू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सरकार नहीं चलाते थे, सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सोनिया गांधी जी चलाती थीं।? (व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह संजय बारू की किताब है। मैं तो केवल किताब को कोट कर रहा हूँ।? (व्यवधान)

महोदया, मैं सीआईए की कुछ डी-क्लासिफाइड फाइल्स लेकर आया हूँ। ये सीआईए की डी-क्लासिफाइड फाइल्स हैं। ये फाइल्स कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे। वे पैसा लेते थे और पैसा लेकर देश की पॉलिसी बनाते थे। देश का कैसे नुकसान हो, वही काम करते थे।? (व्यवधान) ये डी-क्लासिफाइड फाइल्स कहती हैं। अगर आप तीनों किताबों को देखेंगी, चाहे वह अशोक मित्रा की हो, संजय बारू की हो या नटर सिंह की हो, यह कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है।? (व्यवधान) ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वह हम होने नहीं देंगे।? (व्यवधान) ये देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे लोग हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि?

?जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।

अन्तिम संकल्प दोहराता हूँ,

याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा।?

इस देश को बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी तो हम कुर्बानी देंगे। हम वित्त मंत्री जी के इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हैं और पूरे सदन से यह आग्रह करते हैं कि इस बिल को पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।? (व्यवधान)

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2024 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ आंवला लोक सभा की महान जनता का, जिसने अपना आशीर्वाद देकर हमें आपके बीच में भेजा है।

महोदया, यहां बड़ी लंबी-लंबी बातें करने वाले लोग हैं। आज एक बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि वर्ष 2047 में विकसित भारत? बनेगा। लोक सभा चुनाव के पहले सरकार ने एक विकसित भारत यात्रा निकाली थी। वह यात्रा चुनाव प्रचार की दृष्टि से निकाली गई थी। हमारे लोक सभा क्षेत्र में जब विकसित यात्रा पहुंची तो तत्कालीन सांसद महोदय जी एक माताजी को एक मकान की चाबी देते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। जब उस माताजी से पूछा गया कि माताजी आपको आवास मिला है, इसके लिए किसी ने आपसे कुछ लिया तो नहीं? पूरी दुनिया ने वह वीडियो देखा, उस माताजी ने कहा था कि तीस हजार रुपये देकर आवास मिला है।

माननीय सभापति महोदया, आज किसानों की हालत बहुत खराब है। उस पर सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। जहां एक तरफ बात होती है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मुझे लग रहा है कि जो बजट आया है, उसमें किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश का किसान इतना दुखी और परेशान है कि वह अपनी फसल लगाने के लिए रात-रात भर जागता है। जब तीन डिग्री तापमान होता है, तब वह अपनी मेढ़ पर खड़ा रहता है। उसके बाद भी फसल नहीं बचती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाया जाएगा, लेकिन वे आज उसको भूल गए हैं।

आज उत्तर प्रदेश में किसानों को कतई बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे-ऐसे गांव हैं, जहां 15 से 20 दिनों तक सप्लाई नहीं हो रही है, धान की रोपाई नहीं हो रही है। उसके बारे में कोई चिंता नहीं की जा रही है। हमारे नौजवान साथी भी दुखी हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है। ये युवा पीढ़ी गांवों में रह रही है। उनके लिए न तो अच्छे कॉलेज हैं, न ही अच्छे स्कूल हैं और न ही खेल के मैदान हैं। शाम को युवा तीन घंटे कैसे खेले, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। युवा या तो शराब पीने लगता है या यू-ट्यूब में मस्त हो जाता है। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए।

केवल कहने से विकसित भारत नहीं बनने वाला है। अगर विकसित भारत बनाना है, तो रेलवे को सुधारिए। रेलवे की हालत बड़ी खस्ता है। मैं समझता हूँ कि बगैर गांवों का विकास किए विकसित भारत की कल्पना करना केवल और केवल दिखावा-छलावा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा से पहले जो सरकारें थीं, हमारे नेता जी ने? लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना? शुरू की थी।?लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना? के माध्यम से गांवों का विकास हो रहा था। ये डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग हैं, लेकिन 10 साल में एक भी गांव का विकास नहीं किया है। जब ये वर्ष 2014 में आए थे, तब इन्होंने कहा था कि सांसद गांव को गोद लेंगे। जो गांव गोद लिए गए, उन गांवों में कोई भी विकास नहीं हुआ है। उन गांवों की हालत पहले से ज्यादा बदतर हो गई है। आज ऐसे हालातों पर सर्वे किए बगैर, गांवों के विकास की योजना बनाए बगैर, केवल यहां से कह देना कि विकसित भारत बनाएंगे, ये केवल देश को गुमराह करने वाला जुमला है।

माननीय सभापति महोदया, जब वर्ष 2014 में ये लोग सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा है। आज उस काले धन पर बात नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका मिला है, लेकिन उसके बाद भी सरकार सुधार की तरफ नहीं बढ़ रही है। यहां पर जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, गरीब की बात केवल भाषणों में होती है। गरीब का कल्याण कैसे हो, ये सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने 39 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है, यानी हमारे देश में लगभग 120 करोड़ लोग गरीब थे। अगर 140 करोड़ में से 120 करोड़ लोग गरीब हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सरकार का दावा है।

महोदया, मैं तो आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार को जमीनी हकीकत पर आना चाहिए, जमीन पर आना चाहिए और जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए इस सदन के माध्यम से कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे इस देश का भला हो सके, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं आंवला लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ। वहां अस्पतालों का बुरा हाल है। हमारे यहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। वहां लोग परेशान हैं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, सबने लूट मचा रखी है।

आज इस वित्त विधेयक में कैसे हमारा किसान मजबूत हो, उसके लिए मेरा एक सुझाव है। देश के अंदर अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के बाद हम उसको काट नहीं सकते हैं। अगर सरकार औद्योगिक क्षेत्र में लकड़ी के इस्तेमाल और रिहायशी क्षेत्र में लकड़ी के इस्तेमाल के पेड़ों को लगाने की योजना बनाए तो यहां से कानून बनना चाहिए कि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपको पेड़ काटने की भी अनुमति दी जाएगी। अगर किसानों की इनकम को बढ़ाना है, किसान को आगे बढ़ाना है तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाए बगैर हमारे देश का किसान समृद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर आधारित है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर अन्नदाता ही सबसे ज्यादा दुखी होगा, परेशान होगा तो मुझे लग रहा है कि यहां पर बैठने वाले लोगों को भी कोई माफ नहीं करेगा।

महोदया, हमारे यहां सरकार की तरफ से ?वन नेशन, वन इलेक्शन? का हो-हल्ला मचाया जा रहा था। उस पर अभी कुछ काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं यह मांग करता हूँ कि इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी? अगर इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाए तो शायद लोगों का कल्याण हो जाए, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। गरीब का बच्चा कब पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ?एक देश, एक स्वास्थ्य? व्यवस्था लागू कर दी जाए तो इस देश का कल्याण हो सकता है। ? (व्यवधान) माननीय सभापति जी, हम लोगों की पार्टी का समय अलॉट हुआ है, लेकिन अभी चार मिनट भी नहीं हुए हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री नीरज मौर्य : माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त विधेयक को पढ़ रहा था। इसमें आम जनता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इनकम टैक्स का है। जब वर्ष 2019 में मोदी जी की सरकार बनी और तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली साहब थे तो उन्होंने कहा था कि हम इनकम टैक्स एक्ट को बदलेंगे। पूरे देश के लोगों से सुझाव मांगे गए थे और पूरे देश के लोगों से इस पर चर्चा की गई थी। अब जब जेटली जी नहीं रहे तो उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह एक्ट जटिल है, क्योंकि इसमें बार-बार संशोधन हुए हैं। यह एक्ट इतना जटिल हो गया है कि जो लोग टैक्स देते हैं, वह इसमें उलझ जाते हैं। वित्त मंत्री जी ने भी स्वयं अपने बजटीय भाषण में कहा है और इस स्थिति को स्वीकार भी किया तो वित्त मंत्री की असफलता इसमें साबित होती है।

सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम छः महीने के अंदर इस एक्ट को रिव्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए किसी कार्य योजना के बारे में कुछ भी विस्तार से नहीं बताया गया है। इसलिए इस पर गंभीरता के साथ योजना बनाकर, सदन को विश्वास में लेकर, सदन में यह बात रखी जाए, जिससे आम टैक्स पेयर को कुछ राहत मिले। अभी इनकम टैक्स का संशोधन आया है, उसमें सरकार ने कहा है कि बचत स्कीम्स के माध्यम से, चाहे उसमें एलआईसी हो, चाहे पीपीएफ हो या अन्य कोई टैक्स रिबेट वाली स्कीम्स हों, उनसे जो लोग छूट लेते थे, उसको भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। जो हमारे सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके अंदर एक बचत की भावना थी कि हम टैक्स में छूट पाएंगे, इसलिए कुछ बचत कर लें, लेकिन उसका भी इस नई टैक्स

प्रणाली में नुकसान हुआ है, इसलिए इस पर दोबारा विचार करना चाहिए । ? (व्यवधान) आप मुझे दो मिनट बोलने के लिए और दे दीजिए । जो 30 परसेंट का टैक्स स्लैब है, वह बहुत ज्यादा है । कॉर्पोरेट से 25 परसेंट टैक्स लिया जाता है और जो एम्प्लॉई है, जो काम कर रहा है, जिसकी आमदनी कम है, उससे 30 परसेंट लिया जा रहा है । इस टैक्स स्लैब को भी ठीक करने की आवश्यकता है । सेक्शन 115 बीए में 15 परसेंट टैक्स की रियायत दी जाती है, इसको कम किया जाए जिससे मैनुफेक्चरिंग के क्षेत्र में बढ़ावा मिले । कम्पनी से, कॉर्पोरेट से जो 25 परसेंट का टैक्स लिया जाता है, यही टैक्स पार्टनरशिप कम्पनीज़ पर भी लगाना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदया, जो बातें यहां से होती हैं, उनको कैसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर भी यहां से कोई न कोई कमेटी बननी चाहिए । हमारे क्षेत्र में बिशारतगंज रेलवे स्टेशन है । मैं वहां ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं । वहां लोग पटरी फांद कर जाते हैं और कई बार वहां दुर्घटनाएं हो जाती हैं । यहीं, बिशारतगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग 6 ए, रमपुरा-अलीगंज में ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय सदस्य ।

श्री नीरज मौर्य : महोदया, मुझे दस मिनट का समय बोलने के लिए मिला है ।

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं ।

श्री नीरज मौर्य : अंडरपास बनाने की आवश्यकता है । कोरोना काल में हमारे यहां से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जिसको बंद कर दिया गया था । उसको पुनः चालू करने की मैं मांग करता हूं । हमारे यहां फरीदपुर से बुखारा रेलवे क्रॉसिंग, जहां अत्यंत जाम रहता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वहां भी ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं । अंत में मैं अदम गोंडवी साहब की चार लाइनों को कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा-

?तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है । उधर जम्मूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो इधर परदे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है । लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में तुम्हारी मेज़ चांदी की तुम्हारे जाम सोने के यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रक्काबी है ।?

मैं आपका आभार प्रकट करते हुए उम्मीद करता हूं कि मोदी जी का सैद्धांतिक रूप से एक साल का ही कार्यकाल बचा है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय श्रीमती महुआ मोइत्रा जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है ।

? (व्यवधान)

श्री नीरज मौर्य : महोदया, मुझे बोलने के लिए दस मिनट का समय मिला है और अभी मेरे दस मिनट नहीं हुए हैं ।

माननीय सभापति : आप दस मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री नीरज मौर्य : माननीय मोदी जी का सैद्धांतिक रूप से माननीय मोदी जी का एक साल का कार्यकाल है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने नियम बनाया है कि 75 साल के बाद न तो चुनाव लड़ना है और न ही मंत्रिमंडल में रहना है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा जी ।

? (व्यवधान)

**SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR):** Hon. Chairperson, Madam and my respected colleagues, I stand here today on behalf of my party, the All-India Trinamool Congress, to speak on the Finance Bill.

Madam, I have to say, I am deeply pained. At the very outset. I must point something out. When we speak on the President's Address, the hon. Prime Minister leaves the Chamber. Today, when we are speaking on the Finance Bill, the hon. Finance Minister leaves the Chamber. We, Members of the Opposition, are deeply pained by this. We hope that the Government will take notice of our pain and be present in the House each time when we speak on the relevant issues.

Theodore Roosevelt, the 26<sup>th</sup> President of the United States, had said: "In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing." The hon. Finance Minister has made a mockery of the people of India in this Union Budget by doing absolutely nothing.

Whatever little changes are there are regressive and ill-thought-out. This is an illusory Budget where the Government knows fully well the mandate of 2024. This Coalition Government means that the people did not want the "business-as-usual" approach. People wanted a course correction. What have you done? You have not listened to the mandate. "Vinash Kale Viprit Buddhi"? you have done the exact opposite. You have kept the same Cabinet; you have kept the same Finance Minister who has given the same shoddy Budget.

Who is this Budget for? The middle-class make up 31 per cent of India and the poor make up between 60 and 65 per cent of India. I will demonstrate how this Budget systematically strangles the poor and the middle-class. This is a "Kursi Bachao Budget", a "Save-the-Chair Budget" for this Government, and even that, it does not do very well.

Broadly, there are two types of taxes, that are, Direct Taxes and Indirect Taxes. Direct Taxes are known as progressive taxes. Why are they progressive? If we talk



about income tax, property tax, and investment tax on the capital gains, these are done in a way that the richer you are, the more tax you pay. So, they are kind of fairer.? (*Interruptions*) Indirect Taxes are regressive because everyone from the richest billionaire to the poorest labourer is paying the exact same tax. So, if we talk about GST, the duties on petrol and the duties on diesel are all indirect taxes. When we strive for a fair and equitable economy, we must have the balance of Direct Taxes and Indirect Taxes right. The US and the Europe broadly collect about 60 per cent through the Direct Taxes and 40 per cent through the Indirect Taxes. Some Scandinavian States with welfare models collect 70 per cent through the Direct Taxes and 30 per cent from the Indirect Taxes. In India, it is the exact opposite. About 65 per cent of tax collection comes from the Indirect Taxes where the billionaires pay the same as the poorest labourers, and only 35 per cent comes from the Direct Taxes. Even within the Direct Tax bracket, for the first time in our country's history, the salaried professionals and the middle class are sharing a greater tax burden than that of the rich corporates. The middle-class is contributing 55 per cent of the Direct Income Taxes under this Government, up from 38 per cent under the UPA. The richest corporates in India today contribute only 45 per cent of the Direct Taxes. Not only is the middle-class being taxed, but now with this Budget, the savings of the middle class have also been taxed with removal of indexation and with a rise in the short-term capital gains. The investors, who have made more than 11 per cent returns ? we have done the calculation ? that is about the threshold rate, if you have made more than 11 per cent returns, the higher returns, then this new tax regime in which the removal of indexation has happened, is good for you.

Now if we talk about the people like our parents, pensioners, salaried middle-class, risk-averse people, who invested in gold, in property, in debt mutual funds, the removal of indexation has harmed them disproportionately. So, the middle-class has lost out. The Debt mutual fund holders will end up paying more than 40 per cent more tax because the indexation is being changed from 20 per cent to 12 per cent for the investments made before April 1<sup>st</sup>, 2023.

So, this is effectively penalizing those who have made low profits. People think real estate has made enormous profits. If you look at the RBI's Housing Index for the past 10 years, the average rise in property prices has been between 4.5 per cent and 5 per cent. So, if the middle class has invested in property, that is below 11 per cent return, and thus, the indexation is going to harm you.

The current GST regime is irrational and iniquitous. There is an 18 per cent GST levied on life insurance and medical insurance products. The hon. M.O.S., Finance, on Monday, told this House that the Government has collected Rs. 8,263 crores as GST on health insurance for the fiscal year 2023-2024 alone. This is blood money. Our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee ji wrote a letter to the hon. Finance Minister in the Centre, pointing out that this is a completely anti-people tax. What is life insurance? What is health insurance? It is protecting people, protecting against life's uncertainties ? against accident, against injury, against ill health, against death. What are you doing? You are imposing GST, which the poorest and the middle-class person has to pay, at the same rate that a billionaire pays. So, the people are deterred from taking out new policies and continuing existing insurance. This should be removed at the earliest.

Let me now move on to what affects more than 70 per cent of the Indian citizens ? the social sector allocations. The general trend over the past decade in every Budget in the last 10 years, of which our hon. Finance Minister has presented seven, has been in nominal terms that you have allocated more money to the social sector. But if you account food inflation, and you look at real allocations, which is inflation adjusted, the allocations have seen reductions of over 25 per cent in the past 10 years.

I am going to look at real allocations that is adjusted for inflation for some major schemes in the past 10 years. The allocation to Sarva Shiksha Abhiyan is minus 18 per cent, the allocation to Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan is minus 9 per cent, the allocation to Integrated Child Development Scheme (ICDS), which affects every child as it is a school scheme, is minus 34 per cent, the allocation to Mission Anganwadi is minus 5 per cent, the allocation to PM POSHAN scheme is minus 45 per cent, the allocation to Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana (PMGSY), those of us who have rural areas, has been reduced minus 47 per cent in real terms, the allocation to the National Social Assistance Program is minus 20 per cent, and the allocation to the combined expenditure on five social schemes, the top five social schemes as a percentage of GDP, has declined from a peak of 0.93 per cent. So, from almost one per cent of GDP in 2009-10, do you know where is it today in 2023-24? It is at 0.36 per cent. It is only one-third of what it was in 2009-10. Do you know where is the MAGREGA budget today? The MANREGA budget during COVID-19, when the Centre was asking all the States to give employment to the labourers as they were going back, was 0.6 per cent of the GDP. Today it is just 0.26 per cent.

The specific Budget figures for 2024-25 are shameful. Let us look at the specific figures. The allocation for Samarth scheme, which is maternity entitlement and the crash scheme, has been reduced by Rs.70 crore compared to the Budget Estimates of last year. The budget for the National Social Assistance Program ? again those of us from the rural areas know how important is this ? is unchanged from last year, and is at Rs.9652 crores. The National Social Assistance Program is what gives social security pensions to the elderly, to single women and to the disabled. It is same as last year. There is no adjustment for inflation.

The Central contribution to social security pensions has been unchanged since 2014. It was Rs.200 in 2014; it is still Rs.200 per person today. The price of the cutlets in the Parliament canteen in the last 10 years has been adjusted for inflation with the Government's approval. The price of the cutlets in the Parliament canteen has more than doubled. But when it comes to giving social security for the poorest of the poor, it is still Rs.200 in the last 10 years. There is no change.

Under this year's Budget allocation, there is no room for higher salaries for Anganwadi workers. Their salaries have been unchanged since 2018. There is no room for higher honorarium for Mid Day Meal cooks. You have to understand that a lot of the women in villages depend on only Anganwadi sectors and Mid Day Meal sectors for any source of employment. There has been no higher allocation for supplementary nutrition given to the children.

The National Food Security Act (NFSA) mandates coverage of 67 per cent of the population through the Public Distribution System (PDS). The Prime Minister has very proudly proclaimed that this is a food surplus country. Then, why have we not increased the population covered under rations? Since 2011, you have not had a census. Since you have not had a census, you have not increased the number of people being covered under rations.

Also, there is one very important question. Why is the Central Government blatantly defying the direction of the Supreme Court? We went to the Supreme Court on the migrant workers' case. The Supreme Court gave a direct order to the Central Government that the Central Government has to give rations to eight crore migrant workers of the unorganized sector, who have been left out of the food security net. The last hearing was on 16<sup>th</sup> July 2024. The Court again said that you have to please give money to the States which have issued additional ration cards. But there is no room in the Budget for this. There is no allocation.

In this rush to protect its own chair, the Government is making a very dangerous mistake that it is not giving enough to protect our borders. Military experts have repeatedly warned us that India's military capability has to be modernized because we are fighting on two-fronts. One is against China where we need a dissuasive deterrent, and the other is against Pakistan, where we need an offensive deterrent. The budgetary allocation for Defence in this Budget is Rs.6.22 lakh crore. There is a marginal decrease of Rs.2000 crore compared to the Revised Estimates. This year's budget allocation for Defence is 1.9 per cent of the GDP.

This is the lowest since 1960. Despite many economic constraints, the past Governments had always given close to three per cent of GDP, which is a universal norm, for defence. Over the last decade, ever since this Government has been in power, it has been hovering around two per cent. We have been unable as a Government to compel China to restore *status quo ante* April 2020 on the Line of Actual Control. We have been unable to deter Pakistan. In the last two months alone, over 50 security personnel and about 10 civilian pilgrims have been killed in Jammu. The capital expenditure on military equipment is Rs. 1.75 lakh crore. On paper, this shows that it is almost a ten per cent increase. What we have not taken into consideration is that this increase was largely due to Russia's inability to supply contracted weapons to us because of the Ukraine war. If we take into account the inflation and the rising dollar rate, it is almost flat.

The gap between the projections made by the Armed Forces and the actual allocations is 17 to 23 per cent. That is the gap. आप कुर्सी बचाने में मस्त हैं, आप देश को भी देखिये । We need to allocate 2.5 to 3 per cent of GDP to defence. This is something that the country needs to look at.

The hon. Finance Minister started off her speech by talking about the focus on *annadata* or farmers. How much has this Government done for the farmers? The *Economic Survey* of 2024 says 42.3 per cent of Indians depend on agriculture, that is, 600 million or 60 crore people. I looked at the *Economy Survey* presented on 22<sup>nd</sup> July very carefully. What did the headline say? The headline says 'Agricultural sector has registered an annual average growth rate of 4.18 per cent in the last five years?', but then I needed to read and read and read, and in the fine print was written that last year, it was only 1.4 per cent. Anyway, when you compare the growth rate of 4.18 per cent over the last five years to inflation, it is nothing, but when you compare last year's growth rate of only 1.4 per cent, what is it saying to 60 crores of our people who depend on farming?

Productivity and Resilience in Agriculture was one of the first themes. It was priority number one, according to the Finance Minister's Budget. She had made nine priorities. This was priority number one. But the provision for agriculture and allied sectors is only Rs. 1,52,000 crores whereas the provision for one Bullet Train from Ahmedabad to Mumbai is Rs. 1,08,000 crores. I would request everybody to please look at the comparison.

The Finance Minister said that the priority number two is 'Employment and Skilling'. This Government has got the worst track record of creating jobs. India has more jobs in the informal sector, not in the formal sector. The Budget is talking of an internship programme with the top 500 companies. This is a joke. The top 500 companies employ 70 lakh people in total. That is one per cent of the total workforce. Our workforce is about 57 crores. You are expecting companies, which employ 70 lakh people, to give employment to one crore interns. Please let us know how this is going to happen. I am really curious to know this. The real problem is somewhere else. The real problem is that 10.3 crore youths have basically become so dejected that they have given up looking for jobs. The Finance Minister mentions skilling loans and education loans. The skilling loans would be given to 25,000 people and the education loans would be given to one lakh people. The country has 140 crore people. What are we doing?

The priority number three, according to the Finance Minister, is 'Inclusive Human Resource Development and Social Justice'. In this section, the Budget says that they will support construction of expressways in Bihar. What you are not saying is that you will make expressways which will charge very high tolls. So, you are recovering the money; you are not doing anyone a favour. You are charging back-breaking tolls. You might give another bridge which might collapse! You will setup another power plant which, like in Jharkhand, may also be outsourced to a favourite businessman. It can be given a nice, juicy PPA and sell more imported coal.

Secondly, to Andhra Pradesh, there are no grants, but only loans, that too from multilateral agencies. So, basically dollar loans will be given to Andhra Pradesh, which the future generations will have to pay back with interest.

There was also another sweeping statement that grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasam and North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. I looked into the entire Demands for Grants with a toothcomb, with a microscope and I also looked at the Expenditure Budget also. Nothing was

provided anywhere. I do not see the intelligent people of Andhra Pradesh being fooled by this.

The priority number four is Manufacturing and Services. The Finance Minister has devoted an entire section on how MSMEs are a priority. I believe her, and it should be a priority, but I am very confused because most medium and small enterprises are either proprietorships or partnerships. Madam, can you please explain why proprietorships and partnerships are taxed at higher rate than companies are? This makes no sense. Is the 'A' team the only businesses who are sending truck loads and tempo loads. MSMEs are not sending them. Is that the problem?

Also, the Government needs to get rid of the bizarre Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code because it is killing companies that are in trouble. It does not allow promoters to propose a resolution plan.

As long as we have this Code, the promoters cannot propose a Resolution Plan. We need to get rid of this.

Priority 5 in the Finance Minister's speech is 'Urban Development'. The Prime Minister had said every citizen will get a house by 2022. We are now in 2024 and we are still making allocations for three crores more houses. Can you please tell us how many more houses we need and when it is going to be done? Let us get this over with.

Priority 6 is 'Energy Security'. The less I speak about this, the better it is. Energy security is security for best friends. It is created by allowing best friends to import low-grade quality coal, marking it up as high-grade quality coal and selling it to the State Development Corporations at the cost of the country's environment and at the cost of the health of our citizens.

Priority 7, the Finance Minister said, was 'Infrastructure'. She announced in a true style of *shagun* that she is gifting the nation Rs. 1,11,111 crores. This is flat on last year. Sadly, most of this money will go towards crony capitalists. You make roads that have potholes; you will have airports that leak; and you will have bridges that fall out; and the taxpayer will pay for this. The Budget speaks of private sector participation but remember one thing. They bid out six airports to one company for a fee to be paid to the Government. Then they created a policy that allows the

regulator to keep increasing the User Development Fee. So, actually, it is the flying public of India that are paying for this.

Priority 8 is ?Innovation, Research and Development?. These are just grand words. The Finance Minister seems to have forgotten that most of the entrepreneurs register their product and software IPs in foreign countries like the US since the IP registration system for patents is a complete failure in our country. Unless you fix patent registrations, this is not going to happen.

The last priority she talks about is ?Next Generation Reforms?. This is also another *jumla*. She says: ?I propose to earmark a significant part of the 50-year interest free loan for competitive federalism.? So, this is doublespeak. They will keep this money in their pocket. If Nitish ji and Chandrababu ji see through their *jumla* and they make a big fuss, they will have some additional funds to keep them happy and to keep the Government going.

Finally, I have to mention one interesting fact. I hope that the Treasury Benches will have the patience to hear me out. I wholly agree with the Finance Minister on one thing. The budgets for the CBI and the ED have been reduced this year and I was wondering why. Is it because the voters did not like the fact that you were using the CBI and the ED to go after the Opposition and file fake affidavits? Or, is it because you have outsourced the CBI and the ED completely to a businessman in Ahmedabad who is controlling the whole thing? Why have you reduced it? The former Maharashtra Home Minister highlighted how the BJP leaders and the agencies have threatened him to file a fake affidavit. In the case of Sandeshkali in West Bengal, the women have confirmed on video that the BJP leaders forced them to file fake statements. Similarly, I am told in my matter, ...\* on October 16, 2023 got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. Actually, it was ...\* who filed the fake affidavit and forced him to sign it. Even today, every mid-level official in ... office calls mid-level officials in the CBI and says: ?161 स्टेटमेंट्स चेंज कराइए । सर को बुलाइए । मैडम के अर्गेंट में स्टेटमेंट लीजिए ।? I am telling the CBI via you, Madam, please take 161 statements once and for all. Do not keep calling back people at ...\* behest to change 161 statements to implicate me. It is going to get you nowhere. Let us reduce the CBI and the ED budget to zero. Let Mr. Adani pay the full amount of Rs. 1,500 crores. Let us outsource it completely to him. It will be the end of the story. In short, this *kursi bachao* budget is a desperate attempt by the Government to stick its head in

the sand and act like the mandate of 2024 never happened. But the coming days are going to prove the instability of this Government and the inefficacy of its economic policy. We wait for that day.

Thank you very much, Madam.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Madam Chairperson, the hon. Member has made a specific allegation against the Government and a particular business house. She has been tortured like anything. The matter may be referred to the Committee of Privileges. The Committee of Privileges has to take *suo moto* action on this.

It is a very serious allegation. ? (*Interruptions*) A Member of Parliament is being tortured by a business house, and still it is doing it. ? (*Interruptions*) This has to be looked into by the Privilege Committee. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदया, ये जिस केस के बारे में ज़िक्र कर रही हैं, वह लोकपाल पर मेरा केस है । ? (व्यवधान) वह मेरा केस है, मैंने कंप्लेंट की है । ? (व्यवधान) मेरी कंप्लेंट पर वह केस है । ? (व्यवधान) वह मामला सब-ज्यूडिस है । ? (व्यवधान) उसको सीबीआई और ईडी इनवेस्टिगेट कर रही हैं । ? (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA (NILGIRIS):** No. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे : इसीलिए, इस सदन में ? (व्यवधान) क्या नो, नो, नो? ? (व्यवधान) यह मेरा केस है, लोकपाल पर मैंने कंप्लेंट की हुई है । ? (व्यवधान) यह केस मेरे ऊपर है । ? (व्यवधान) मैं यहां बैठा हुआ हूं । ? (व्यवधान) यह कुछ भी हो रहा है, तो दर्शन हीरानंदानी को यदि हिम्मत है, जिसके बारे में ये बात कर रही हैं । ? (व्यवधान) उसको हिंदुस्तान में आकर, सीबीआई उसको बुला रही है, वह आ क्यों नहीं रहा है? ? (व्यवधान)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Madam, when I was on my legs, I was not provided the mike. ? (*Interruptions*)

**DR. NISHIKANT DUBEY:** It is my case. ? (*Interruptions*) So, I have every right to speak. ? (*Interruptions*)

**SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR):** \*Hon Speaker Sir, Vanakkam. I thank Hon Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin and Hon Udhayanidhi Stalin, and the voters of the Perambalur parliamentary constituency for making the voice of this ordinary person to be heard in this august House. I express my foremost thanks to the people of this country who have stressed that those who are in power should work in a coordinated way. \*



Madam, I would like to start with something that is very fundamental to the Constitution of this country. It says, India, that is Bharat is a Union of States. But today, after 10 years, in fact in the 11<sup>th</sup> year, we are in the position of asking, 'what is the state of the Union?? We still do not know what is the state of the Union. So, India, that is Bharat, is actually a Union of States where the States make up this country, and what the Finance Minister has done is to ask us the question, 'what is this state of this Union??

Now, as my colleague has pointed out, we are missing on the collective wisdom of this House when the senior Members of the Treasury Benches are actually missing in action. When the Opposition wants to draw the attention to the various schemes, the trouble and the problems of the people, we still, through you, Madam, insist that the senior Members be present when important Bills like the Finance Bill is being discussed. ? (*Interruptions*)

What is this Budget about? It is actually primarily about misplaced priorities. The State with its resources is not being provided enough support so that they can carry on the people's work. I will go point by point, Madam.

A lot has been talked about job creation, and the hon. Finance Minister has been forthcoming with providing training for youngsters. What she has failed to address is that the majority of the youth is not in the formal sector. The total EPFO paying customers is only 3.05 crore whereas the total workforce is above 45 crore people. What is being spoken about in the Budget is less than five per cent of the actual workforce, and the amount of EPF that the formal companies are paying is actually much lesser than that. So, Madam Finance Minister's statement about providing training actually does not cause any impact at all on the youth who is actually looking forward to training. So, I guess that the Government should take note of the informal economy and the need for training there.

There are three important segments that constitute the everyday life of the populace, namely fertiliser, food and education. Based on last year's numbers, the total allocation on fertiliser has been reduced by 13.5 per cent; food by minus 3.1 per cent; and education by minus 2.2 per cent. The Government has many reasons to reduce, but what I fail to understand is this. These three segments are the basic for any life to be lived upon in this country and on this planet. Now, when you reduce the allocation of the basic input that goes into life, then how does the Government expect the country to grow? How does the Government expect the

country to have food on the plate of a common man and then work to pay taxes, which again is the next big topic?

How can they pay with all the basic things reduced? I think the Government should take proper care while allocating the resources.

I am going to talk about a very important segment which is education. The hon. Finance Minister and the hon. Education Minister have been talking about the resource allocation, the NEET issue and that the Central Government is actually taking care of the people. What I fail to understand are two important things. What the Opposition is talking is the outcome. What the Treasury Benches are talking about is the output. Let me explain it with an example. The Central Government says that they have brought about transparency and they have brought about equality in education. They might talk about the process only. They have got the exam. They have got the QR code and let the students in. There are a lot of harassment issues before the students make it to the exam. All that is the output. But we are talking about the outcome. What does the outcome talk about? The outcome talks about a fair chance a common man in this country gets to make it to the medical exam and serve the people of this country. They are not talking about outcome at all. They are only talking about the output. The process is great. We are not talking about the process. The process is unfair. The point from the Opposition is that the Government should not try to justify the unfair system saying that the Government follows the procedure. The procedure may be wrong. Please listen to the Opposition.

A number of people in my constituency is missing Anita, a student who should have been here with me as a doctor in Tamil Nadu. We are missing her because of the bad policies of this Government. So, please take note and please get the outcome right. Forget about the output. Please get the outcome right.

I will also give you an analogy. So, the hon. Members here have asked about national the highways, which is really good for the country. You are building the national highways all across the country. Now, we have very good highways across India. You have opened a new highway. That is the output. What is the outcome? Now, if you have 50 accidents or 50 deaths in a year, that is the outcome. So, what we are saying is that we need to avoid deaths. There is no use building a four-lane highway so that people die faster. What you are trying to do in the NEET Exam is actually pushing the inequality in the name of the process. Please open your eyes. There are people who are really suffering. There is a lot of inequality in the system.

Before it gets out of hands, please open your eyes and give a fair chance to each one of the individuals who really need it.

Now, there is a lot of talk about the middle class. A very important point for the Treasury Benches and the Ruling party to note is that three per cent of the vote of the middle-class has shifted from the BJP to the INDIA Alliance. You would know that the hon. Finance Minister actually again misplaced a priority in actually addressing the middle-class. What have you done to the middle-class? The middle-class earns money. They are the salaried people. They are hardworking people. They put their resources in three very important things. You have gold; you have real estate; and you have stocks. The Government has been pushing saying that they are going to increase the width and the depth of the market. What they have done is basically taking away all possible deductions that every common man before paying taxes calculates very vigorously. What have you done? Section 80(d), which provides for deductions across for the salaried classes, actually remained flat. As my colleague pointed out, based on inflation, it is actually minus now. By remaining flat, your deduction has reduced, but you are actually paying more taxes. So, the middle class is actually being punished for being honest. I think the misplaced priority on taxation must actually be addressed by the Treasury Benches.

Now, one of the things that I am really puzzled about is when the hon. Finance Minister talks about the cess. Not all of the hon. Members would know, but I would want everyone to be educated on cess. There is separation of power with regard to indirect taxes and direct taxes. The resource allocation to the State is being made by eminent institutions like the NITI Aayog. Does that cess go only to the Central Government, and the Union Government decide which States to get what? The amount of cess has increased in the last 10 years, 10 times. It is not one per cent or two per cent. It is 10 times. What does this 10 times mean? You are actually taking away the resources of the States. You think it is fair for the States to come and ask for the cess amount? I do not think they even ask. So, the Government should take note that they are providing direct taxation, indirect taxation and something else totally different.

### **15.00 hrs**

Madam, I am also speaking for the hon. Finance Minister because her maternal side is from my Constituency. I am actually speaking for her also. So, I need the two extra minutes to get to her. I hope she were here.

Now, I come to the important things about the State - what they have done to the State, and what this Budget has done is basically kill the golden goose. Tamil Nadu, with its impressive manufacturing strength, a large tax base and honest, hard working people, is being short-changed in this Budget. We are contributing, and for every rupee we get only 29 paise. We are very proud of the one rupee that we contribute. But what we ask is to give us a fair share so that we can actually contribute more. We are not complaining about not receiving less, but we are saying you are not giving us a fair share.

Very importantly, I will talk about relief and rehabilitation. You have seen in the last year that there are so many States that are being affected by natural calamities and Cyclone Michaung which affected Chennai, and the heavy rainfall which affected Thoothukudi and the other districts by a record rainfall. What had we asked? The same IAS officers who have been passed by the UPSC, have recommended for a package of Rs. 37,000 crores, and what we got is Rs. 450 crores. It is not even one day's interest, not even according to anybody's standards. So, I think it has been very, very unfair on the part of the Central Government.

The most important thing, Metro Rail project, was actually inaugurated by the Union Home Minister Amit Shah Ji on 21<sup>st</sup> November, 2020 in Chennai. The State Government has allocated Rs. 16,000 crores from its own resources. The Budget that was passed for this under this Budget was supposed to be given to Tamil Nadu which is still not given. What again we are asking is for our fair share. We are not complaining about not receiving money.

So, the general takeaway from this Budget is this. Do not punish the States that are contributing. Second, you are actually giving loan to the States that were actually your allies.

Last but not least, the Government has come up with a new East Policy. The new East is Odisha, you have Bihar and Andhra. I do not know what kind of East that is. But as far as I know, the East also covers the State of Tamil Nadu. I will also join the bandwagon. All we are asking for is a fair share from the Central Government. On the maternal side of the Finance Minister also, I am saying this. It is also your Constituency. Madam, through you, I tell the Finance Minister to actually do fairness for the Dravidian State that educated you, that put you into this place, that actually forms a big portion of the decisions you make. So, please be fair to the State of Tamil Nadu.

With these words, I conclude. Madam, thank you for the opportunity given to me.

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET):** Madam, thank you for allowing me to speak on the Finance Bill, 2024.

Madam, I cannot speak on this before thanking the tax payers who have been coming out in big numbers. The number has increased from 6.7 crore to almost 7.28 crore this year. Even the earnings from income tax have increased by almost 32 per cent. So, this shows the confidence that the income tax payers are having on the Government, importantly NDA. But we have to keep in mind the process that has been implemented for the last four years. A faceless assessment has been implemented. There are numerous issues that have been raised about it. Of course, this is useful for a lot of tax payers, but recently, a lot of people are complaining that too many sections are being invoked. For example, if someone has given Rs. 10 crores as penalty, if that person has to go for re-assessment, he has to pay 20 per cent to actually go for it. Because of this, tax payers are actually bearing the burnt. I wish and I hope the Finance Ministry will take this matter into account, so that we will make it easy for the tax payers to actually come into the fold.

Also, there is a rise in the gross revenue by almost 14 per cent. I have to thank the Finance Ministry for reducing the corporate tax from 40 per cent to 35 per cent. We have made numerous representations to the Finance Minister regarding the Angel Tax that was levied. It is a boon that the Finance Ministry has removed this. This will help start-ups, and the whole eco-system will develop in the few years to come. But the one word that has to be removed from the history of the Finance Ministry is with respect to the retrospective tax which we keep hearing from time to time.

Yesterday also, I was reading somewhere with regard to the mineral development and mineral industry which has come forward saying that the industry cannot function if you go in for retrospective tax. A few years back also, on some other industry, there was another retrospective tax. I think, the Finance Minister has to sit with them. Even the rice exporters also have come to me and said that the retrospective tax has been applied on them. If you keep doing this just to earn some money from the businesses that are doing very well, this will not encourage the businesses to flourish. So, I think and I hope that the Finance Minister will take this into account and take this retrospective tax out of the dictionary.

Coming to the capital expenditure, there has been almost 17 per cent increase. This Government has been doing it for the last five or six years and Capex has been

the main go to area whereby the development in the country is happening. Every year, the capital expenditure has been increasing. This year, almost Rs.11 lakh crore has been put in place for capital expenditure. But the problem is this. Last year, out of Rs.10 lakh crore that had been earmarked for capital expenditure, only Rs.9.48 lakh crore have been spent. So, almost Rs. 52,000 crores were not even spent on capital expenditure. So, I would request the Finance Ministry to actually look into it. Having a capital expenditure allocation of Rs.11 lakh crore or Rs.11.5 lakh crore is one thing, but actually spending it on the ground is a different thing. So, I hope that the Finance Minister will look into it.

A lot of Members have raised a point with regard to the reduction in Long Term Capital Gains Tax from 20 per cent to 12 per cent. They also mentioned about the indexation. A lot of Members mentioned about it. There is also a lot of talk outside. So, I hope and expect that the Finance Minister will look into it. This is because this is taxpayers' hard-earned money. Also, the middle-class people are being affected by this. So, I think, there should be a relook at this indexation because the middle-class people think that real estate is one thing that they can safely invest in. We feel that it should be protected. I hope that the Finance Minister will listen to this.

My colleague Sushri Mahua Moitra has mentioned very agitatedly that she does not know wherefrom the funds are coming to Andhra Pradesh because she did not see any special allocation that was made. Correct me if I am wrong, but I think that it has been mentioned by the Department of Economic Affairs wherein Rs. 62,000 crores, the entire amount, has been earmarked for capital expenditure and also for the new schemes that have been announced. So, I hope and I wish that the Purvodaya Scheme which has been announced for Andhra Pradesh and all the other Eastern States that my friend, my colleague has mentioned, this amount of Rs. 62,000 crores will be given to us. The majority will be given to Andhra Pradesh.

My next point is with regard to Clauses from 88 to 99 which deal with the Vivad Se Vishwas Scheme, this has been a scheme which has been in effect for the last four years. This is used by a lot of taxpayers as well as a lot of industry people. This has been a successful scheme. But the problem right now that we should revisit is this. I have been reading the clauses but nowhere in the clauses there is a mention of timeline. I am looking for them because almost 5.4 lakh income tax appeals are pending at the Commissionerate level. We can only address this when we have a timeline defined in those clauses. I hope that the Finance Minister will look into this and try to address this issue.

Coming to health care, we have done amazingly well in the last 10 years or so. Numerous medical colleges and AIIMS have been developed. Also, the number of post-graduate seats have been increased. But there is 18 per cent GST on health insurance policies. If you look at the percentage of people having life insurance, 75 per cent of them are having life insurance. Only 25 per cent of them are having health or medical insurance. There are uneven numbers that are here. It should be the opposite way. More people should have health insurance or medical insurance and less people should have life insurance or the number should be equal, at least. But somehow it is skewed in one direction. It can be addressed only if GST can be reduced so that more people can have access to medical insurance and health insurance.

Coming to the point with regard to agriculture, in agriculture we have come up with numerous schemes in the Central Government. Every year, the Central Government is giving Rs.6000 to every farmer under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. The Soil Health Cards have been given.

Insurance has also been given. Various other schemes have also been given by the Central Government. There is a definite effort from the Central Government to improve the conditions of the farmers and also, to double the farmers' income. But we need to review the 12 per cent GST on agriculture equipment, 18 per cent GST on tractors and machines for processing and milling, and 15 per cent GST on pesticides. I think, instead of having these many numbers of percentages, and these many brackets of GST numbers, I hope and wish that the Finance Minister will come with a lesser number like how the Government has it for fertilizers, which is five per cent. I hope all the others will also come into the same bracket so that the farmers will get the benefit.

Madam Chairperson, now, I come to the textile industry, which is one of the backbones of my district. A lot of textile parks are there. A lot of textile industries are there. A lot of yarns are there. But the problem that they have -- and I request the Finance Minister to look into this -- is with regard to the 11 per cent import duty, which is levied on cotton that is imported. Yes, we have to protect the farmers. And the Cotton Corporation of India is buying cotton from the farmers at a good price. Yes, we appreciate that. Protecting the farmers is one thing but protecting the industry is also our duty. The only way that we can protect the industry is actually giving it enough raw material so that it can produce good quality products, and it can become competent when it exports to other countries.

They have to compete with countries like Bangladesh and Vietnam. They can only be competitive when these raw materials, which are needed for these cotton mills, are provided at a reasonable price. Not only that, they can become much more competitive if the import duty of 11 per cent is decreased.

Now, I come to handlooms. Again, it is a huge employment-generated sector across the country, and also, we take pride in the handlooms. The hon. Prime Minister keeps on talking about handlooms and handicrafts every year. With regard to handlooms, there is a growth of five to seven per cent in the last five years. But the problem is with regard to the National Handloom Development Programme. Every year, the Estimates and Revised Estimates have been decreasing. In 2021-22, the Estimates were Rs. 485 crores; now, the Estimates have been reduced to Rs. 200 crores. In 2021, the Revised Estimates were Rs. 344 crores; and in 2023, it has been reduced to Rs. 156 crores. Handlooms is one of the backbones of our country and we take pride about it. Therefore, I wish the Finance Minister looked into this matter. ? (*Interruptions*) I am the only Member from my Party who will speak. ? (*Interruptions*) Madam, we have enough time.

Now, I come to the SEZs Act in the textile industry. There is one friend of mine Shri C.M. Ramesh, in whose constituency, there is a company called ?Brandix?, which employs almost 30,000 women. From this industry, exports are happening at a breathtaking pace. The industry is very much quality-oriented. They are manufacturing the products and they are exporting the products to other countries, and they are ready to pay tax to sell in India. But there is no provision for them to sell in India. If i-phone can be manufactured by Foxconn in India, and it can be exported as well as sold in India, why can that not have the same provision? I request the Ministry to look into this.

Now, I come to aquaculture. This is one of the major industries in Andhra Pradesh. Almost 70 per cent of the aqua exports happen from Andhra Pradesh. There are so many new schemes which have been implemented. Aqua farmers and processors have been pushed and nudged to do well. Aqua processors have been doing very well. The MoFPI is coming up with new schemes. The PLI scheme has also come up. The aqua processors are using such schemes to a large extent. In our country, capacity with regard to aqua processing is very high. But the problem is with regard to the farmers. They are doing less production. There is a scheme called Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. The problem is that the Budget Estimates were Rs. 2000 crore in 2023-24, but the Revised Estimates were Rs. 1500 crore.



More so, the Revised Estimates of Rs. 1500 crore have actually gone to the Government. The Government has taken that amount and has spent on fishing harbours and other things. The Ministry has to understand that 90 per cent of the production and processing is done by the private players. The Government has not much of a role to play in this. But somehow, the Government is accessing all these funds. So, I hope the scheme will be rephased or reworked in such a way that the private players, who are in the process of exporting and who are in the process of production of aquaculture, can take the benefit of this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So, I hope the Ministry will look into it.

Now, I will come to the last point. A white paper has been released in Andhra Pradesh with regard to the Andhra Pradesh financial situation. I am sure we will print it and distribute to all the Members in this House and also in the Rajya Sabha. So, I hope you will go through it and I hope you will understand the financial position of Andhra Pradesh. I will just briefly put on record the financial position. Please give me one minute.

The expenses as of this year are Rs. 1.64 lakh crore and the revenue is Rs. 1.45 lakh crore. That means we are deficit by almost Rs. 19,000 crores in this financial year. The State debt has increased from Rs. 3.35 lakh crore to Rs. 3.75 lakh crore in 2019 and now it has reached Rs. 9.74 lakh crore in 2024. The growth rate has decreased from 13.5 per cent to 10.5 per cent now.

Agriculture sector has gone down from 16 per cent to 10 per cent. The Capex used to be around Rs. 60,000 crores from 2014 to 2019, as per the white paper. It has gone down to Rs. 24,000 crores from 2019 to 2024. So, there is a decrease of capex and there is a decrease of sectoral growth in agriculture and also in all other sectors. There is a decrease in overall sectoral growth. Per capita debt has almost doubled from Rs. 74,000 per head to almost Rs. 1,44,000 in Andhra Pradesh. Inflation has also risen from 4.5 per cent to 6.2 per cent. So, on one side, we are having a huge debt and revenue deficit every year and on the other side, whatever we have borrowed in the last five years, we have not infused it into the capital expenditure. This has brought the State to its knees. We are ready to work with the Central Government. We are ready to actually again stand up and again try to rebuild the State, Madam.

So, I would request the Finance Ministry to look into it so that they can actually restructure the loans that are taken by the State of Andhra Pradesh and that would help us to run with the other States as well.

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 पर चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदया, यह प्रस्ताव मुख्य रूप से आम बजट वर्ष 2024-25 के अनुसार आयकर दरों में संशोधन के लिए लाया गया है । साथ ही प्रत्यक्ष कर की धारा 2 के साथ अप्रत्यक्ष कर की सीमा शुल्क की धाराओं में संशोधन, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में संशोधन कर विवादों के समाधान को और सरलीकरण बनाने का संशोधन, सीमा शुल्क टेरिफ में बदलाव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धाराओं में संशोधन, केन्द्रीय माल और सेवा कर जीएसटी की धाराओं में संशोधन, बेनामी संपत्ति अधिनियम की धाराओं में संशोधन, काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 का संशोधन आदि प्रस्ताव पर संशोधन होने जा रहा है, जो आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक होगा ।

सभापति महोदया, अब से आम नागरिकों को 75000 रुपये का स्टैन्डर्ड डिडक्शन मिलेगा । सेक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में भी बदलाव का प्रस्ताव है ।

सभापति महोदया, लोगों को मकान खरीदने और बेचने में भी अब आगे टैक्स देनदारी के बदलाव से काफी फायदा होगा । 30 लाख युवाओं को पीएफ में एक महीने का कंट्रीब्यूशन देकर सरकार रोजगार के अवसर को भी बढ़ाने का काम कर रही है । इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । खासकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि यह एक आकर्षक योजना है ।

महोदया, करदाताओं को ब्याज सहित मांगे गये कर का भुगतान करके कम किए गये जुर्माने का लाभ उठाने के लिए वर्तमान समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किए जाने का प्रस्ताव है ।,

महोदया, उक्त संशोधनों से अब अधिनियमन में सरलीकरण करने का सरकार का जो लक्ष्य है, उसे पूरा किया जा रहा है । ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस की कल्पना सरकार में हो रही है । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

अंत में, हमारे जितने भी माननीय सांसद हैं, इनमें कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं । महंगाई बढ़ रही है और खर्च बढ़ रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों को महंगाई भत्ता देने का संशोधन लाया जाए और हम लोगों पर कृपा की जाए । धन्यवाद ।

**SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** Thank you Madam. I rise to speak on this Finance Bill on behalf of my Party, NCP(SP). In the entire discussion, a lot of my colleagues have already mentioned that in 2023-24, the income tax paid by the middle class is far more than the corporate tax.

When UPA was in power, corporate tax was much higher than what the common citizens and the middle class of India paid. Today, it is exactly flipped. Corporate tax has gone down and the middle class is paying much more taxes. So, I would like the hon. Finance Minister to justify why they are taking more taxes from the middle class and the poor people of this country.

I appreciate her efforts. I remember her statement. In 2019, she had mentioned, ?I am reducing the corporate tax so that more investments come into this country.? I

am not talking about the intention of this Government. But what is the outcome? Can you quantify and justify the reduction of this corporate tax? No investments have come in. As a matter of fact, a news item of today says that the rupee has fallen and has become 84.09 against a dollar and the foreign portfolio investors have pulled down about 1.20 billion dollars.

Shri Dubey from the Treasury Benches was talking very highly about the Government and its policies. He also said how the world is doing badly and how well India is doing. I have very less knowledge in finance in comparison to him. But with full humility, I would like to tell him that India is no more an insulated economy. What happens globally will happen in India, if not today. One of the biggest growth engines of any economy is exports. India is not doing well in exports.

Atmanirbhar Bharat is a very good statement. I am the biggest example of Atmanirbhar Bharat. I do not use anything which is imported from any part of the world. But I would like to put it on record that this whole jingoism sounds very good in speeches only. I think we need to think beyond politics. I think we should stop being a prisoner of past and history and start living the present moment because I do not think I will be alive in 2047.

But we need to handle the economy well because the rupee has fallen to 80.49, which is very, very alarming. So, I am telling this Government to wake up and smell the coffee. There is a bloodbath in domestic markets. Today, Sensex and Nifty have tanked nearly 3 per cent, which, I think, is a substantial amount.

I would like to even highlight one or two alarming points. Yesterday, in the discussion on Demands for Grants, hon. Shri Nadda ji was very, very honest and I appreciate what he said in his speech. He reached out to Opposition parties yesterday. I must appreciate his humility. He said that Rs. 3,000 crores were left with the Health Department. यह इनका स्टेटमेंट है । मैडम, कल शायद आप भी हाउस में थीं । उन्होंने कहा कि यह पैसा खर्च नहीं हो रहा है । आप मेरी मदद करिए । I think Prof. Saugata Ray was here. I was also in the House.

भूपेन्द्र जी, शायद कल आप भी यहां थे । तब मैंने पूछा था कि आप बताइए कि कौन सा पैसा रह गया है? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट रह गया है । ये एक हजार करोड़ रुपये हमें दीजिए । हम अपने स्टेट में यूज कर देंगे । If the Health Minister of India says that money is not getting spent, it is very alarming to us. Then what is this Budget doing for this country?

I think there was a question on Rashtriya Vayoshri Yojana in today's Question Hour. My district is number one. वयोश्री योजना में पूना डिस्ट्रिक्ट इस देश में फर्स्ट नंबर पर आया है। हमने जो प्रॉमिस किया है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। जब भी मैं मंत्री जी से मिलती हूं, वीरेन्द्र सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे मान-सम्मान देते हैं और बोलते हैं कि सुप्रिया मेरे पास बजट नहीं है। So, on the one side, the Health Minister is saying that he has extra money and on the other side, the Ministry of Social Justice, about which Government is saying that it is doing work for the poor, does not have money for the commitment they have made to us in a policy. Then, who do we turn to?

किस गरीब को पैसा जा रहा है, सोशल जस्टिस और हेल्थ मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नहीं है, I will ask the hon. Finance Minister whether यह बजट है या इस देश में गरीब आदमी का मजाक बनाकर रखा है? They really need to clarify on this.

My next point is regarding the Bima Karmachari Sangathan. It is a very, very important point. As a matter of fact, we all even agitated today for it. The All-India Insurance Employees Association is the oldest and the biggest trade union of public sector insurance in this country. I think, my colleague Mahuaji also spoke about it. We demand the withdrawal of GST on life and medical insurance premium. We had income tax relief under 80C and 80D. We do not want any reduction. In fact, we want withdrawal because it is very, very important for the common man of India. I think, Mahua ji had extensively spoken on it so I will not repeat that point. It has to be tax free on maturity which was done. I do not know why this government is taxing it. There should be reintroduction of deduction under Section 80G in income tax when it comes to health insurance.

**15.26 hrs** (Hon. Speaker *in the Chair*)

I remember, there was a talk that this Government wants to sell the public sector insurance companies like LIC but, now, they are not talking about it. So, I am grateful to the Government. But, companies like National Insurance, New India Assurance, Oriental Insurance, and United India Insurance are demanding a merger. If they are all merged, they will be far more effective. एक तरफ आप एन्श्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे तो गरीब आदमी को कैसे एन्श्योरेंस मिलेगा? This is another contradiction of this government. So, I request this government to consider this.

My colleague Arun Nehruji spoke extensively about cooperative federalism. I think, Nishikantji talked about Sushmaji very fondly. Sushmaji and Arunji were two people, we all looked up to when we first came to the Parliament. Cooperative

federalism was something which Sushmaji and Arunji had always talked about. As a Finance Minister, he used to talk about it. I would like to seek a clarification from the hon. Finance Minister when it comes to cooperative federalism. The Government brought GST and we are very happy with it. But, we are unhappy with the way it is implemented. I want to ask what is the share of the states. According to the Finance Commission, the States should get 41 per cent but, be it 2021-22, 2022-23, or 2023-24, it has never reached that percentage. Where is all this money going? Why is it not going to the States?

As far as cess is concerned, my colleague Arun Nehruji talked about the cess. Now, there is Krishi Kalyan Cess, Swachh Bharat Cess, Education Cess, and Health Cess which is 9 percent. Plus, there is Oil Cess which we discussed at length yesterday. There is a windfall tax. There is an income tax, and there is a customs duty. There is so much money coming to the Central Government. Why is this money not going to the States? It is very interesting that my colleague Krishna was talking just now about the States getting money, the way his state is doing, and what is the White Paper. Now, this is applicable in most States.

I compliment the hon. Prime Minister when, during the campaign, he used to talk about *revadis*. Now, every Government, which he is a part of, is giving *revadis* Pan-India. Now, I would like to seek a clarification from this Government. My colleague Krishna has raised the issue of Andhra Pradesh. If you go to Chapter ? III, Article 293, of the Constitution, it is about borrowing by the States. I would like to seek a clarification in this respect. It is Article 292, Part-3, which says:

?(3) A State may not without the consent of the Government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the State by the Government of India or by its predecessor Government, or in respect of which a guarantee has been given by the Government of India or by its predecessor Government.

(4) A consent under clause (3) may be granted subject to such conditions, if any, as the Government of India may think fit to impose.?

Now, in the case of Andhra Pradesh, which was your ally for five years, how did you allow the State to go through this? The same is the case with Maharashtra. So, I seek a clarification. You give as many *revadis* as you want. अभी तीन-चार राज्यों में इलेक्शन्स होने हैं, हरियाणा में भी है, रेवड़ियां तो बंटेंगी । I have no problem with those *revadis*. गरीब को कुछ देना है तो जरूर दे दीजिए । But, it should not be at the cost of misleading the nation and

misleading the State for the next 25 years. आपका सारा सपना वर्ष 2047 का होता है । We will come to power but, unfortunately, be stuck with their bad dealings. We do not want this inheritance tax from this Government. So, we really need to know. The Government keeps talking about one thing.

इसे अटल जी तो लाए थे । The FRBM Act was not brought by us. मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि 70 साल में कुछ नहीं किया । हर सरकार कुछ तो अच्छा करती है । ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कुछ अच्छा नहीं करती । Even if we have worked in different ideologies, I would say that Atal ji was the tallest leader of this nation. The FRBM Act was brought by him, and we followed it meticulously. Now, how much of the FRBM Act has been implemented in the Central Government is what I want to ask this Government and seek a clarification on this.

A lot has been said about the GST. I would talk about the GST mismanagement. What is happening in Infosys is something I am very curious about. हर रोज पेपर में आ रहा है, पता नहीं कितने हजार-करोड़, इसमें कितने शून्य हैं, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा कच्चा है । इनफोसिस को 30,000 करोड़ रुपये या 3,000 रुपये करोड़, पता नहीं कितना? एक बार न्यूज आई कि वह विद्रा कर रहे हैं, आज फिर से न्यूज आई है । Is this not a mismanagement of GST? Infosys is such a big international company, doing such a good service. I do not know whether taxing them is right or wrong. But is this the GST management? This is not management but a mismanagement. How can you keep changing the GST numbers all the time?

I have a delegation after delegation coming to meet me saying that the MCA website does not work. Even, people who do not fit in that tax bracket, because they do not file papers on time, are taxed. जो टैक्स ब्रेकट में नहीं है, because they could not file the documents because of the website issue, they are also being taxed. आप वैबसाइट सुधारिए, जिस आदमी का काम डिलोड में है, उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो आम आदमी है, जिस पर आप इतना टैक्स लगा रहे हैं, उसको दिक्कत आ रही है । So, this entire MCA website needs to be improved. ? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : टैक्स देना है या नहीं देना है? ? (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले : टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है । देश के बहुत आदमी ईमानदार हैं, टैक्स भरना चाहते हैं, लेकिन टैक्स भरेंगे लेकिन सर्विस भी चाहते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यह सदन के बाहर ही पूछ लेना ।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, another issue which Shri Krishna also mentioned about is this. किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं। The input tax is so high. What was the idea of the GST? The idea was, 'One Nation, One Tax'. It is 5 per cent, 12 per cent, 18 per cent and so on. Then, you say कृषि प्रधान देश है, लेकिन आप किसान पर ही टैक्स लगा रहे हैं। I am not reading the whole list which my colleague Shri Krishna read. But if we talk about tractors, irrigation equipment and sprinklers, सबके लिए 12, 18 और 5 परसेंट है। My demand is that anything that concerns agriculture should have zero tax on it. अगर आप मिनरल्स पर जीरो कर सकते हैं तो किसान के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? मिनरल्स का टैक्स आपने जीरो किया है। देश का ही टैक्स नहीं, जो बाहर से मिनरल्स आएंगे, उनके लिए भी जीरो टैक्स किया है। किसके लिए किया है? I am not a mineral expert. मैं इनकी तरह आरोप नहीं कर रही, मैं झूठे आरोप नहीं लगा सकती। आप बताएं कि मिनरल्स पर जीरो टैक्स लगा रहे हैं, इम्पोर्ट पर जीरो टैक्स लगा रहे हैं तो एग्रीकल्चर पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? अन्नदाता सुखी भवे, देश में जो किसान हैं, उन पर 18 परसेंट टैक्स लगाएंगे और मिनरल्स पर जीरो लगाएंगे। Which country are they coming from? I am not a mineral expert. लेकिन पढ़ने से समझ में आता है कि शायद चाइना है। ऐसा पेपर में आया है, मुझे नहीं पता। मिनरल्स के बारे में सरकार जवाब दे। गोल्ड पर किया है, अच्छी बात है, और कम करिए ताकि जो गलत काम गोल्ड में हो रहे हैं, बंद हो जाएं। आप गोल्ड पर भी कम करिए। But the Government must justify why agriculture is taxed so highly, and the import of minerals have zero tax on it. This is an answer they owe to the nation and to the farmer of this country. जीरो टैक्स करने की क्या जरूरत है। आप किसे प्लीज़ कर रहे हैं?

**HON. SPEAKER:** Hon. Member, please conclude.

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, the other thing is about the research.

Sir, we have to discuss about agri-research. रिसर्च कितना करनी है, यह सरकार जानती है। How much of the Budget have they allocated for agricultural research is what the Government should tell us. There is the Indian Agricultural Research Institute which has got Rs. 710 crores out of which Rs. 540 crore goes only in salary and Rs. 90 crores in Administration. How much money is left for research? You would be very shocked to find out that the Customs Duty on chemicals has been increased. So, there are people from all the labs and IITs who need chemicals for research, and are in trouble. A delegation of students came to meet me. They are not the students of private colleges.

नहीं तो ये बोल देंगे कि ये तो प्राइवेट कॉलेज है। यह प्राइवेट कॉलेज का सवाल नहीं है। देश में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके रिसर्च लैब्स दिक्कत में हैं because of the customs duties on chemicals. This has to be reduced. अगर आप मिनरल्स का कम कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए तो कम करिए। मिनरल्स का पता नहीं किसके लिए किया है?

Sir, everybody has discussed about the increase in the Capital Gains Tax. So, I would not go into it. But I still want to ask this Government, if you have reduced the tax for foreign companies, then why is the Indian farmer getting affected? किसान के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन के लिए बहुत-कुछ करेंगे । But they are not coming into the country. They are leaving the country. This is what the data is saying. Even today?s morning data speaks of it. आज सुबह का डेटा है । So, this is something this Government has to clarify.

Sir, there is a lot of confusion on indexation. In the first discussion on the Budget, I did not speak on the indexation because the hon. Finance Minister gave a clarification in a Press release. But even after the clarification, there is no clarity on indexation. You cannot tax a person who had bought any old house. Why is this 12 per cent?

Sir, if you had bought a house in 2002 for Rs.1 crore and you sold it for Rs.5 crores, Rs.34 lakhs is the tax of indexation. If you only go by five to 12 per cent as the Government has made it now, it is Rs.50 lakhs. It is completely unfair. So, in terms of the indexation, the Government has taken a semi u-turn, not a full-turn. So, this indexation must be brought back. It is in the larger interest of the nation and the poor hard-working people of this country.

Sir, EPS-95 is a very important issue. Just today?s morning, a Congress Member of Parliament from Kolhapur Constituency raised this issue in the Zero Hour. ईपीएस 95 के लिए हाउस में जो-जो सांसद मिले, चाहे उधर के हों, चाहे इधर के हों, each one of us has met some senior citizens. You will be surprised to know that in 2023-24, only the interest earned on pension corpus is Rs. 51,000 crores and the money given is Rs. 14,000 crores. This was the commitment given by Shri Prakash Javadekar ji. I do not want to name Arun ji because he is no more. उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई थीं, and Shri Prakash Javadekar ji had committed in a Press Conference that अगर हमारी सरकार, जो पहले मोदी सरकार थी, आज एनडीए सरकार है, यह जब आएगी तो हम ईपीएस 95 का पैसा देंगे । But you have not given the money. I urge the Government to release money under EPS-95.

Sir, one last point that I want to highlight is about the ransomware attack. This is a very serious issue because this whole Bill is about taxation. It is unfortunate that the Treasury Benches spoke everything but taxation. It is unfortunate that they have ignored taxation completely. But I would like to raise this important issue that the TCS and the State Bank of India had been hit with a ransomware attack last week. This has affected many banks and hurt the common man. So, I would urge the hon. Finance Minister to address this technical issue as this is very, very



important. The cyber attacks are increasing. She must do something about this to salvage it.

Sir, the last point is that the hon. Treasury Benches talked a lot about the ED and the CBI. मैं तो उसको आइस बोलती हूँ । आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी । That is what ?ICE? stands for. They were talking about it, and they were taking this high morality ground. With full humility and data, I want to tell the hon. Members from the Treasury Benches that आइस केवल अपोजीशन वालों पर चलता है । आइस वाले जब यहां से वहां जाते हैं, तो वाशिंग मशीन से निकलकर पूरा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का केस साफ हो जाता है । I can give you the data, and I can table that on the floor of this House. ....  
(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, इनको पूरा बोल लेने दीजिए ।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, I am happy to yield on this. ....(Interruptions)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, इनको बोल लेने दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप मौका क्यों देंगे? आप थोड़े आदेश दे सकते हैं । सुप्रिया जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए ।

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, I am happy to yield on the issue of Income-Tax, CBI and ED. ....(Interruptions)

Sir, the BJP was in the Government which talked about high morality. न खाऊंगा, न खाने दूंगा । बड़ी अच्छी बात थी । मैं भी प्रभावित थी, क्योंकि इस देश से अगर करप्शन जा रहा होगा, तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र और देश में नहीं हुआ, क्योंकि यह इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का आइस है । एक स्टोरी महाराष्ट्र में चलती थी, जिसको बोलते थे, डर्टी डजन, जिसका मतलब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, जो सांसद रहे थे, वे आरोप लगाते थे कि एनसीपी-नैशनल कांग्रेस पार्टी यानी नैचुरली करप्ट पार्टी उसको कहते थे ।

जो ओरिजनल है, वह क्लेम करती है, वही है । अगर ओरिजनल नैचुरली करप्ट पार्टी ओरिजनल है, तो अभी उनकी तरफ है । So, I seek a clarification from the hon. Finance Minister that she should give us a line and tell us that इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी नैचुरली करप्ट पार्टी ओरिजनल, बड़ा क्लेम करती है, उनकी है तो ये बता दें कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का क्या हुआ और डर्टी डजन का क्या हुआ?

डॉ. निशिकान्त दुबे : स्पीकर सर, मैंने पिछली बार बोलते हुए यह कहा था कि यह मोदी जी की सरकार है, ये अपनों को भी नहीं छोड़ती है । ? (व्यवधान) इसी सदन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ? थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ । उनसे 80 करोड़ रुपये भारत सरकार ने लिये । यह मोदी जी की सरकार है । यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चोरी करेंगे, तो उनके ऊपर भी इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई होगी । जो

राहुल गांधी जी के ऊपर है, वह चिदम्बरम साहब का पीएमएलए एक्ट है, जिसके कारण उनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके।

? (व्यवधान)

**SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):** Sir, every time the hon. Chair allowed Shri Nishikant Dubey to speak, whenever he spoke in the House?

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको भी बोलने की अनुमति दी है।

? (व्यवधान)

**SHRI K. C. VENUGOPAL:** He spoke ...\* only. Last time, he spoke about ...\* ji.

माननीय अध्यक्ष : यह आपके माननीय सदस्य ने कहा।

? (व्यवधान)

**SHRI K. C. VENUGOPAL:** Sir, please give me one minute.

...\* ji is not a Member of this House. He told in this House that ...\* ji attended the Ambani's marriage, which is totally wrong. Every time, he is telling this *galat baat*. You are allowing that. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ओके। No.

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : प्री-वेडिंग में?\* जी गई हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ओके।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप कन्क्लूड कीजिए।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, I would like, on behalf of my colleague, to put it on record that she is not a part of this House, but at a personal level, she is a woman and nobody should talk about, first, a lady who is not a part of this House and, second, she has not attended it. And, there is nothing wrong in attending even if somebody did.

माननीय अध्यक्ष: मैं इस विषय को देख लूंगा ।

? (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले : उसमें कोई चोरी नहीं है । जिस शादी में प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने में । ? (व्यवधान) Sir, it is not fair to bring somebody's wedding in it. ? (Interruptions) Sir, it is not fair. She is not a Member of this House. ? (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: बैठे-बैठे बोलने वालों की बात रिकॉर्ड में नहीं जाती है ।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, she did not attend. Let us go by the facts. There is nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in it? But let us not do a fake narrative.

माननीय अध्यक्ष: ओके ।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, the problem with the BJP is that they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? ? (Interruptions) जब आप लोगों को झूठ-झूठ अरेस्ट करते हैं, तो कभी सोचा है कि उसकी बीबी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोचते हैं? They are doing this only to be in power, for their selfish needs.

माननीय अध्यक्ष: आप उस डिबेट पर मत जाइए । आप फाइनेंस बिल पर बोलिए ।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** Sir, they should be fair. I remember Amit Shah ji's statement and I would like to quote it.

माननीय अध्यक्ष: नो । आप फाइनेंस बिल पर बोलिए ।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SULE:** I would like to quote Amit Shah ji's statement. He says ? जब आप एक ऊंगली सामने दिखाते हैं तो तीन ऊंगलियां खुद की तरफ होती हैं ।? With full humility, I would say to the BJP, quoting Amit Shah ji only, that जब एक ऊंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो तीन ऊंगली आपकी तरफ है ।

That is all I say. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठे-बैठे इस सदन में अन-ऑफिशियल डिबेट बंद कर दीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने सबके लिए बोला है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाता है ।

माननीय विदेश मंत्री जी ।

? (Interruptions) ?\*

**15.49 hrs**

**FINANCE (NO.2) BILL, 2024 ? Contd.**

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक, 2024 जो कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी से संबंधित है, कैसे सरकार अपने बजट को फाइनेंसिंग करती है, आज मुझे उससे संबंधित विषय पर बोलने का अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

हम इस फाइनेंस बिल के बारे में अपना भी आकलन देना चाहते हैं और कई बातों पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं । अभी मुझसे पहले के वक्ता ने चर्चा के दौरान सही कहा कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज़ देश के गरीब पर, किसान पर, आम आदमी पर ज्यादा बोझ डाल रही हैं और कोऑपरेट और देश के अमीरों पर कम बोझ डाल रही है ।

सरकार की ऐसी नीति दिखाई दे रही है, जिसमें आम आदमी के लिए जीरो नीति है । सरकार की दो नीतियां हैं । पहली नीति आम आदमी के लिए है, वह है - जीरो बजट, जीरो बचत और टैक्स की पूरी चपत । खास नागरिकों के लिए सरकार की नीति है - टैक्स में राहत और कमाई खटाखट ।

**15.50 hrs**

(Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

मैडम, मैं यह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ । किसी भी अर्थव्यवस्था में दो तरह के टैक्स होते हैं । एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है । डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स हैं । इन

डायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्लैब के साथ होता है, जिसमें जितनी कमाई है, उस पर लगाकर सरकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक संतुलन ला सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, और एक्साइज टैक्सेस हैं, जो पूरे देश पर बराबर लगते हैं और गरीब आदमी पर ज्यादा हो जाता है। कोई मेडिसिन है, पेरसिटामोल है या क्रोसिन की गोली है, अगर देश का सबसे गरीब व्यक्ति उस गोली को खरीदेगा तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, जितने टैक्स पर देश का सबसे अमीर व्यक्ति उसे गोली को खरीदेगा। टैक्सेस का संतुलन देश के आर्थिक संतुलन से जुड़ी हुई बात रहती है।

मैडम, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम इस वर्ष स्टेट और सेंट्रल के दोनों टैक्सेस को ऐड करके देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में देश का लगभग एक तिहाई कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से हो रहा है और दो तिहाई इनडायरेक्ट टैक्स से हो रहा है, जो टैक्स देश के गरीब, किसान और आम आदमी से ज्यादा लिया जा रहा है। अगर हम इसकी तुलना दुनिया के बाकी देशों से करें तो ज्यादातर एडवांस्ड इकोनामी, ओईसीडी कंट्रीज़, एशियाई देशों में लगभग दो तिहाई देश के टैक्स का कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस से रहता है और एक तिहाई इनडायरेक्ट टैक्सेस रहता है, जो गरीब आदमी से लिया जाता है। अगर हम यूपीए के समय से तुलना करें तो यूपीए के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी संतुलन आया था। यह लगभग आधा-आधा था। यूपीए के समय डायरेक्ट टैक्सेस से 43 प्रतिशत हमारी सरकार लिया करती थी और 57 इनडायरेक्ट टैक्सेस से लिया करती थी। सरकार ने इस संतुलन को विपरीत दिशा में ले जाने का काम किया है। आज डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से कम कलेक्शन हो रहा है और उसमें भी कॉर्पोरेट के टैक्सेस में सरकार ने सबसे ज्यादा राहत देने का काम किया है। पहली मर्तबा देश में कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स से कलेक्शन हो रहा है। अगले वर्ष तक पहली मर्तबा जीएसटी कलेक्शन भी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे कम कलेक्शन हुआ है तथा पिछले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन में गिरावट आई है। वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में एक राहत दी गई थी। उस राहत में कॉर्पोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत तक कम किया गया था। उस समय आपकी नीयत क्या रही, मैं उस पर प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन जब आपने बड़े उद्योगपति घरानों, कॉर्पोरेट्स को यह राहत दी तो आपने कहा था कि आप यह राहत इसलिए दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश हो, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े तथा इन्वेस्टमेंट हो। इस वजह से पिछले पांच सालों में 8.7 लाख करोड़ रुपये की राहत देश के कॉर्पोरेट्स को देने का काम आपकी सरकार ने किया है, लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत यह हुई कि निवेश बढ़ने के बजाय, इन पांच वर्षों में निवेश लुढ़क गया। कॉर्पोरेट टैक्स में टैक्स कट आपने उनकी मार्जिन को बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, आपने निवेश बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन निवेश लुढ़क गया।

मैडम, आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी निजी निवेश दर देश में 20 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर, 2025 में जो निवेश दर आई, वह बीस साल में वर्ष 2004 के मुकाबले की निवेश दर देश की अर्थव्यवस्था में आई है। आज एफडीआई भी 16 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर है। इस वर्ष हमारी जीडीपी की 1.1 प्रतिशत एफडीआई मिली। मंत्री जी कह रही थीं और मैं सुन रहा था कि एफडीआई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कम हुई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। दुनिया के बाकी देशों में एफडीआई में गिरावट नहीं आई। हिंदुस्तान एफडीआई रिसिप्ट्स में आठवें नंबर पर होता था। एफडीआई में हमारा देश एक ही वर्ष में गिरकर 15 वें नंबर पर आ गया। एफडीआई में तो रिकॉर्ड गिरावट आई है, लेकिन उसके साथ-साथ आउटफ्लो में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एक ओर केवल 27 बिलियन डॉलर की इस साल एफडीआई है और दूसरी ओर 14 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो गया है। आपने कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स कट किया कि कॉर्पोरेट्स निवेश करेंगे, जॉब क्रिएशन होगा, लेकिन निवेश दर बीस सालों

में सबसे निचले स्तर पर आ गई है, एफडीआई 16 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। निवेश नहीं हुआ है, इसलिए आज देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है।

आप जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए हैं, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट के हाथ में पैसा दो, वे निवेश करेंगे। लेकिन यह पॉलिसी दुनिया में गलत साबित हो चुकी है। अगर कॉर्पोरेट के हाथ में पैसा होगा तो वे वहां निवेश करेंगे, जहां डिमांड स्ट्रॉंग है। आपने डिमांड को स्ट्रॉंग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। डिमांड को अगर आप देखें तो रूरल सेक्टर में डिमांड फ्लैट है। आज कृषि सेक्टर में हमारी डिमांड फ्लैट है। जब तक इकोनॉमी में डिमांड नहीं आएगी, तब तक कॉर्पोरेट्स हमारी इकोनॉमी में निवेश नहीं करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, जो थियोरी फेल हो चुकी है, उसको हिन्दुस्तान में सफल करने के लिए आपने दस साल लगा दिए। एक बार आप हिन्दुस्तान के आम आदमी के हाथ में पैसा देकर देखें। आप डिमांड साइड इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाएं। किसान और गरीब को कोई राहत नहीं मिली है, आप उनको भी राहत देकर देखें। आप एमएसपी की लीगल गारंटी देकर देखें। आप मनरेगा में चार सौ रुपये की वैज करके देखें। आप हमारे देश के आम आदमी के हाथ में पैसा देकर देखें। उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट्स की इन्वेस्टमेंट तब हमारे देश में सही रूप में हो पाएगी।

महोदया, इतना ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने के बाद भी निवेश नहीं हो रहा है, इसका एक कारण और भी है और वह मोनोपोलीज़। हमारे देश में क्रोनी, क्रोनिएज़म और क्रोनी मोनोपोलीज़ क्रिएट हो रही हैं। हमारे देश के पांच बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने देश में आज लगभग 40 सेक्टरों में सरकार की सहायता से अपनी मोनोपोलीज़ बनाने का काम किया है। सीमेंट, पोर्ट डिफेंस, टेलिकॉम सेक्टरों में और अब तो न्यूक्लियर सेक्टर की भी बात आ रही है कि कुछ कॉर्पोरेट घराने इन सेक्टरों में अपनी मोनोपोलीज़ क्रिएट कर रहे हैं। सरकारी एजेंसीज़ के माध्यम से लीगल और पीनल एनवायरमेंट ऐसा बनाया जा रहा है। जब मोनोपोलीज़ क्रिएट हो जाती हैं तो मोनोपोलीज़ सेक्टर में दूसरा निवेश नहीं होता है। हमारी सरकार से यह मांग है कि यह जो असंतुलन बना है, जिसमें गरीब आदमी से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और कॉर्पोरेट्स को जो राहत दी जा रही है, इसको सरकार सुधारने का काम करे।

महोदया, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हमारी सरकार ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये एक्साइज़ ड्यूटी से टैक्स लेने का काम किया था। यह यूपीए सरकार के आखिर वर्ष में है। मगर 1 लाख 42 हजार करोड़ रुपये वापस सब्सिडी के रूप में देने का काम भी किया था। उस समय मात्र 30 हजार करोड़ रुपये की कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से उस समय सरकार को हुई थी। आपकी सरकार में इस वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से कमाई 4 लाख 32 हजार करोड़ रुपये है और सब्सिडी मात्र 11 हजार करोड़ रुपये दी गयी है। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से आपने 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई देश की आम जनता से की है। हमारी सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जहां 30 हजार करोड़ रुपये की करती थी, वहीं आप 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की कर रहे हैं। हमारे समय में पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 9 रुपये थी, आज 20 रुपये है। डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी 3 रुपये थी, लेकिन आज 15 रुपये है। आज पेट्रोल-डीज़ल से आप कमाई कर रहे हैं। वर्ष 2014 में टोल के माध्यम से कुल कलैक्शन तीन हजार करोड़ रुपये थी, लेकिन आज 65 हजार करोड़ रुपये है। हर वस्तु पर जीएसटी लगाकर सारे कर का बोझ आप आम आदमी और किसान पर डालने का काम कर रहे हैं। हम इस नीति का विरोध करना चाहते हैं। हम यही मांग करते हैं कि पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ में राहत दी जाए। केपिटल गैन्स टैक्स के इंडेक्सेशन को आपने वापस लिया है, उसको फिर से बहाल किया जाए। लाइफ

इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में जीएसटी को विदूढ़ किया जाए । ये सारी मांगें मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ ।

इसके साथ-साथ मैं हरियाणा के विषय में एक महत्वपूर्ण बात सदन में रखना चाहता हूँ । माननीय खट्टर साहब भी बैठे हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं । सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार अगर किया गया है तो वह हरियाणा प्रदेश के साथ किया गया है । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे? जैसे कि अभी बताया जा रहा था कि हर प्रदेश केन्द्रीय टैक्स कलैक्शन में भागीदारी करता है । कितना केन्द्र एक प्रदेश से लेती है और कितना उस प्रदेश को वापस देती है । हरियाणा से जीएसटी कलैक्शन पूरे देश का 7.10 प्रतिशत होता है । लेकिन हरियाणा को केन्द्र की तरफ से मात्र 1.009 प्रतिशत राशि वापस मिल रही है यानी एक प्रतिशत के करीब ।

यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केन्द्र सरकार हरियाणा से सात रुपये ले रही है और केवल एक रुपया वापस दे रही है । अगर प्रतिशत में बात करें तो यह 15 प्रतिशत है । केन्द्र सरकार हरियाणा से 100 रुपये ले रही है और 15 रुपये वापस दे रही है । अगर पूरे देश में सबसे कम फंड किसी एक प्रदेश को दिया जा रहा है तो वह हरियाणा को दिया जा रहा है । हम मानते हैं कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में थोड़ा कम है, लेकिन दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है, जिसको कम फंड दिया जा रहा है । महाराष्ट्र में यह 29 प्रतिशत है, यानी कि केन्द्र सरकार 100 रुपये ले रही है तो महाराष्ट्र को 29 रुपये दे रही है । कर्नाटक में केन्द्र सरकार 100 रुपये ले रही है तो 40 रुपये वापस दे रही है । पूरे देश के 29 प्रदेशों में आज हरियाणा ही एक प्रदेश है, जहां सबसे कम 15 प्रतिशत फंड ही केन्द्र सरकार वापस दे रही है । अगर हम नेट डेवलूशन की बात करें कि केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाए और अगर इसे प्रति व्यक्ति में देखें तो मैंने कैलकुलेट किया है कि 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष हरियाणा को 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए, यानी कि प्रति व्यक्ति 6 हजार 938 रुपये दिए गए । यह भी 29 राज्यों में सबसे कम है, जो हरियाणा को दिया जा रहा है ।

हम बाकी राज्यों को देखते हैं तो गोवा में 40 हजार रुपये दिए जा रहे हैं । अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1 लाख 40 हजार रुपये दिए जा रहे हैं । तेलंगाना में केन्द्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 25 हजार रुपये की राशि दी जा रही है, लेकिन हरियाणा में मात्र 6 हजार रुपये की राशि प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष दी जा रही है । यह पिछले पांच साल से दी जा रही है, यानी कि 15 वें फाइनेंस कमीशन में एक प्रतिशत डेवलूशन का जो फॉर्मूला हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया था, चूँकि यहां पर खट्टर साहब भी बैठे हैं, उन्होंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा । उस समय नीचे भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की सरकार थी । ? (व्यवधान) अभी सबसे कम राशि हरियाणा को दी जा रही है । ? (व्यवधान) खट्टर साहब, आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दे दीजिएगा । ? (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल): सभापति महोदया, मेरा नाम लेकर कहा जा रहा है इसलिए मैं बताना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि मैं बजट के आँकड़ों के ऊपर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि दिल्ली के आसपास होने के नाते हरियाणा को काफी लाभ हुआ है, वह चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या बाकी चीजों में हो । इनका सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए उकसाने का काम है । मैं यहां पर बैठा हूँ इसलिए ये बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर इनको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है । ? (व्यवधान) दिल्ली-अलवर की लाइन हरियाणा से होकर निकलती है । दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस यहां से होकर निकलती है । ? (व्यवधान) दिल्ली-कटरा रोड हरियाणा से होकर निकलती है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदया, ये सारे प्रोजेक्ट्स हरियाणा के हैं । ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । हरियाणा का क्या कसूर है? हमारी आबादी देश में 2.1 प्रतिशत है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश के क्षेत्रफल में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.34 प्रतिशत का है । आज देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 4 प्रतिशत का है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश के जीएसटी कलेक्शन में 7 प्रतिशत हरियाणा का योगदान है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश के खाद्यान्न और अन्न भंडारण में हरियाणा का किसान 33 प्रतिशत दे रहा है तो क्या हमारा यह कसूर है? देश की आर्म्ड फोर्स में 11 प्रतिशत हरियाणा से आर्म्ड फोर्स का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा तो क्या यह कसूर है? देश के लिए 50 प्रतिशत मेडल्स हरियाणा से आ रहे हैं, क्या यह कसूर है? इसके बाद देश के 29 प्रदेशों में से हरियाणा को केन्द्र सरकार द्वारा केवल एक प्रतिशत की राशि मिल रही है । बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया । मुझे इस बात का दुख है ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कंक्लूड कीजिए ।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदया, मैं कनक्लूड की तरफ जा रहा हूँ । आप ?खेलो इंडिया? का बजट देखिए । आज देश के लिए तीन मेडल्स आए, जिसमें से दो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए हैं । ?खेलो इंडिया? का बजट 2200 करोड़ रुपये रखा गया है, उसमें से मात्र 60 करोड़ रुपये हरियाणा को दिए गए हैं, यानी कि खेल बजट का सिर्फ दो प्रतिशत दिया गया है । गुजरात में 500 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है । यह खेलो इंडिया के बजट का 20 प्रतिशत है । वहां से एक मेडल भी नहीं आया है । मैं समझता हूँ कि यह अन्याय है ।

मैं कनक्लूड करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को केन्द्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ एक भी परियोजना नहीं मिली है, अपितु यूपीए के समय में हमारी जो मंजूरशुदा केन्द्र सरकार की परियोजनाएं थीं, वे 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं थीं । चाहे वह हमारा महम में एयरपोर्ट हो, जो कि जेवर चला गया । वह 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा था । चाहे हरियाणा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री हो, जो बनारस में चली गई । चाहे तीन रेल लाइन्स का काम हो, यमुनानगर-चंडीगढ़ रेल लाइन परियोजना पर एक इंच लाइन भी नहीं बिछी । चाहे हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, न्यू अलवर तक रेलवे लाइन काम हो, चाहे बाडसा के अंदर एम्स हो । हमारे 9 मेडिकल के प्रोजेक्ट्स थे । केन्द्र सरकार ने 10 साल में एक भी प्रोजेक्ट हरियाणा को नहीं दिया, जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने हरियाणा सरकार को देने का काम किया था । आपने उन प्रोजेक्ट्स को भी खत्म कर दिया ।? (व्यवधान) मैडम, हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बजट देने में हरियाणा को भूल गई है, उसी तरह हरियाणा भी वोट देने में बीजेपी को भूल जाएगा । हम यह विश्वास दिलाते हैं ।? (व्यवधान)

**SHRI BASAVARAJ BOMMAI (HAVERI):** Madam, I thank the hon. Chair for giving me the opportunity. This is my maiden speech in this House.

I was just observing the entire discussion on the Finance Bill. Very little has been spoken on the Finance Bill. More lies have been spoken on the respective positions which are political. Of course, politics plays an important role in finance also



because political science is the science of all the sciences. How the politics shape up depends on the person who is there because man is a political animal. So, we are talking about a man. A lot has been said about that man and a lot has been discussed about that man. He is discussed globally also. He is a man who has changed the destiny of this country for the last ten years. For a second, if you think that our hon. Prime Minister Narendra Modi ji had not been a Prime Minister, what would have happened to this country? The whole country would have been in such a confused and chaotic state economically, politically and socially.

I am really wondering when a lot of people speak about poverty, the farmer and the women. It has become a fashion to speak about the farmers and the farmers? causes. We are using the name of the farmer time and again. But one should remember that the farmer does not belong to any political party, but all the political parties belong to the farmer. However, we forget that. We know that the life of the farmer is very uncertain. It has been known for the last 75 years, and it is still going on. I wish somebody really took a serious note of it. We discussed about a lot of problems of the farmers, but nobody discusses about the solutions for the farmers. अपोजिशन वालों ने बहुत बड़ी बात की है । वे समस्या उठाते हैं, लेकिन उनकी समस्या के हल के बारे में बात करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वे हल नहीं चाहते हैं । समस्या ज्यादा होने पर समस्या का हल होना चाहिए । ऐसी राजनीति बहुत दिनों से चल रही है । इसलिए किसानों की हालत वहीं की वहीं है ।

I just want to say a few words. I stand before you to reflect the remarkable journey of our nation undertaken under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. He has defined poverty as the foremost enemy.

Madam Chairperson, before Independence, we had only one enemy, and that was the Britishers. Today, we have गरीबी, अशिक्षिता, बेरोजगारी और बीमारी । We have these enemies. We have to tackle them with a population of 140 crores. Madam, I want to say one thing to the entire House. Disraeli said, ?There is no magic in economy, only results?. There is no magic. हम भी समस्या के ऊपर बात कर सकते हैं ।

महुआ मोइत्रा जी बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थीं । मैं सुन रहा था । फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफरेंट सेक्टर्स पर जो एलोकेशन किया है, she wants to compare that with the inflation. मैं पूछ रहा हूँ कि आज तक चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, which budget allocation has been done according to inflation. And if that is to be done, then we need four to five times the budget size of what we have today. Is it possible? Will our revenues allow this? You run away from the reality. You want to make your own point. Come to the solutions. This is not the way the country should be run. We have to understand the issues and tackle the problems in the most scientific way and not in a political way. I know that

the Opposition has a political say. But this is not the way. The real issues are lying somewhere else. I just want to highlight a few of them.

Prime Minister Shri Narendra Modi ji transformed our population into a demographic dividend. एक जमाना था, जब हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी चुनौती थी । But here is one Prime Minister who has converted calamity into opportunity. And he said that our demographic dividends are through our population and we have to skill them up. I am telling you on record that no Prime Minister has talked about skill in the way Shri Narendra Modi did it.

The former Finance Minister was saying that we have taken a leaf from the Congress manifesto. In 2016, an Act was passed in this very House about entrepreneurship and skill development. Madam, we brought reforms in GST and banking. We also brought reforms with regard to revitalising the manufacturing sector and digital economy. जीएसटी के बारे में बहुत कुछ बातें हुई हैं । The people who introduced GST Bill are disowning it now. अपने बच्चे को डिसऑन क्यों कर रहे हैं? Why is it so? It is because you are now on the other side of the fence. Kindly look at the figures with regard to the growth of taxes through GST. In the pre-GST regime, -- if you take five years, that is, from 2012 to 2017 -- it was Rs. 38,52,000. But in the last five years of GST, -- I am not talking about 2022 and 2024, but I am talking about 2017-22 -- it was Rs. 57.5 lakh. This is the growth of taxation. The tax base has increased. The number of people who are involved in businesses is more into the tax net. This is the revenue to the country. Once a revenue comes, then we can talk about development. Therefore, the year-on-year increase is almost 12 per cent. In the last month, that is, in the month of July, GST collected was Rs. 1.8 lakh crore.

Therefore, GST was just an impossible thing because consciousness was not there. It was the leadership of Shri Narendra Modi Ji who brought consciousness in making GST. The great poet Tiruvalluvar of Tamil literature had said, 'In between concept and creation, there lies the shadow?'. There was a concept and to create that concept, we need to remove that shadow and Narendra Modi Ji Government removed the shadow in GST. That is why, it is the reality today. It has to be acknowledged and this is one thing which will take the country to new heights. History will remember Narendra Modi Ji for doing this.

Secondly, Madam, the greatest thing what he did was the digital economy. The digital economy through DBT eliminated middlemen and also eliminated corruption between *janta* and the *sarkar* and it was achieved through DBT. It ensured that the benefits reach the people directly and efficiently and it has saved

Rs. 3.48 crore. Otherwise, it would have gone to the middlemen. This is what the honesty of this Government speaks as far as taxation is concerned and sharing the benefits with the people are concerned.

I just want to say that here is a leader, here is a party with the true spirit. We do not wait for things to happen. We do not wait for destiny to create growth for us. We create growth and through that growth, the destiny of this nation is written. That is what Mr. Narendra Modi ji stands for. We are racing against all the international and developed countries, not only are we racing against them but we are also racing against time.

This is the Government where time and management has been done in the right direction with the right speech which was otherwise lacking in all the previous regimes.

Madam, taxation has got four pillars: taxes should be purposeful; taxes should be affordable; taxes should be equitable; and taxes should be accountable. I am very proud and happy to say that all these three pillars and the policies have been adhered to for the last ten years. All taxes are purposeful and they have been affordable, equitable and accountable. This has led to a sustainable growth and fiscal consolidation. Fiscal consolidation is very important aspect for our growth trajectory. Therefore, our principled tax policy has posted a favourable environment resulting in increased tax payer numbers and enhanced tax affordability. This reflects our success in balancing both equitable tax and ensuring resilient and thriving economy.

Madam, I just want to tell you that people are talking about only one or two successful businessmen where they have become the subject of position. Madam, the number of people who filed income tax in 2014 was 3.65 crore. In 2023, it was 8.18 crore. This is almost three times. Year on year, the increase is nine per cent. This is very interesting.

In 2014, the number of people who earned more than Rs.1 crore and filed tax returns was just 48,417. In 2023, nearly 2,16,000 people are earning more than Rs.1 crore. So, we are creating people who are capable of earning more. Now, more than two lakh people are earning more than Rs.1 crore.

So, it is not just one or two companies which are driving this country. It is these people who have gone through the policy of this Government. They are driving this country. The per capita income of the common man in 2013-14 was Rs. 89,000. In

2022-23, it was Rs.1,94,879. It is almost double. In 10 years, the per capita income has been doubled. This what it means; this is what this Budget, this tax policy means.

We should really look into these aspects so that we can get a better vision to build this country, not in a dejected way just to find faults only. Yes, no system is hundred per cent perfect. That is why, I said that there is no magic wand in economics. The problems cannot be solved in one day. But the important thing is in what direction we are going. That is why, our Prime Minister has said that we will achieve the target of Viksit Bharat in 2047.

Madam, I greatly honour Shrimati Supriya Sule ji. She was saying that she might not be there in 2047. We do not work only for ourselves. Our elders and ancestors worked hard and we are having the fruits of their hard work. अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रॉंग फाउंडेशन, ?आत्मनिर्भर भारत? से लेकर ?विकसित भारत? तक का संकल्प अभी लिया है और उसे वर्ष 2047 में हम हासिल कर लेते हैं, तो हम रहें या न रहें, यह देश तो रहेगा । ? (व्यवधान) हमारे देश के देशवासी तो रहेंगे, हमारे बच्चे तो रहेंगे, हमारी अगली पीढ़ी तो रहेगी । उनके लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे? क्या एजाम्पल छोड़कर जाएंगे? क्या उनके लिए खाली भंडार छोड़कर जाएंगे? ? (व्यवधान)

हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक निर्णय ?विकसित भारत? की ओर है और हम इसे करके दिखाएंगे । ? (व्यवधान) यह हमारा हौसला है । ? (व्यवधान) चाहे आपका हौसला हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता है । ? (व्यवधान)

इनकम टैक्स के बारे में बहुत बातें हुई हैं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ । यह तो आप सबको मालूम है कि ग्रेजुअली इनकम टैक्स में बदलाव आ रहा है, छः महीनों में एब्स्ल्यूट बदलाव लाने का वित्त मंत्री जी का इरादा है । उन्होंने अभी जो किया है that Standard Deduction of salaried individuals and pensioners are proposed to be increased from Rs.50,000 to Rs.75,000. इससे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को यह दिखता नहीं है । Secondly, deduction from family pension is also proposed to be increased from Rs.15,000 to Rs.25,000 and pension contributions from the employer will be up to 14 per cent. Earlier, it was 10 per cent. यह सब इंडीविजुअल, सैलरीड पर्सन्स के फायदे के लिए हमारी वित्त मंत्री महोदया ने किया है । हमें इसे देखना चाहिए ।

Equalisation of levy of two per cent of the proceeds received by non-resident e-commerce operators for supply of goods and services will not be applicable from 1<sup>st</sup> August. वह दो परसेंट निकाल दिया गया है ।

एंजल टैक्स के बारे में सब लोगों ने बताया है । Angel Tax is imposed on the companies for receiving funds in excess of face value of their shares. This provision will cease to apply.

अभी रियल एंजल हो गया है । अभी तक तो एंजल नहीं था, अभी रियल एंजल हो गया है । There is immunity to benami transactions. बेनामी एक्ट बहुत दिन से है, लेकिन बेनामी एसेट जिसके नाम पर है, अगर अभी वह अप्रूवर बन गया तो, the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 makes the benamidar and the beneficial owner equally culpable. In order to encourage a benamidar to turn approver, provision is being made to provide immunity. इससे बेनामी एसेट बाहर आती है । This is the honesty of our leader Narendra Modiji, ?न खाएंगे, न खाने देंगे ।?

A lot has been said about capital gains tax where it is being said that indexation is a little bit confusing. However, as the time goes, they will realise that it is better than the previous one. I need not explain the whole thing because the hon. Finance Minister has already explained the whole thing. There are certain examples which I do not want to quote here.

There is also a reduction in customs duty on certain precious metals like gold and silver; it has been reduced from 15 per cent to 6 per cent. The same is the case with platinum which goes to automotive industries. There are a lot of such sensitive decisions taken this time which were ignored by the previous Governments. There is an increase in tariff of certain things because the Government has to support the local industries. Hence, it is a very well-balanced tax system. For example, the tax on three cancer drugs has totally been reduced to zero per cent on humanitarian grounds. There is growth in all the sectors. The overall value-added growth in health and social sector is 244 per cent in the last ten years. This is the economic stimulus which this Government has given. Similarly, there is growth in all the sectors with value addition.

A special care has been taken in steel and copper sector where the import duty has been reduced. Same is the case with the electronic sector, textile sector, and leather sector. I just want to highlight some points and conclude my speech. The present Budget is in the right direction.

As far as COVID-19 is concerned, we have to see the economy in two parts ? pre-COVID-19 and post-COVID-19. This pandemic has not only made dent on the lives of the people but also on the economy. But, it is the Narendra Modiji's Government which has handled COVID-19 and saved lakhs and lakhs of lives. He, once again, took it as a challenge and converted it into an opportunity. The growth of our economy is astonishing the whole world. That is what our friend Nishikantji was trying to say. On the one hand the growth in some developed countries is not more than 2 per cent or 3 per cent, on the other hand our growth is 6 per cent to 7 per

cent. We are going to have a double-digit growth very shortly. Our expenditure has been increased by 8.5 per cent in this Budget. Our receipts have increased by 14 per cent in this Budget. Therefore, our fiscal deficit has been reduced from 6.4 per cent in 2022-23 to 4.9 per cent this year. Likewise, the revenue deficit has been reduced from 3.9 per cent to 1.8 per cent and primary deficit has been reduced from 3 per cent to 1.4 per cent. Therefore, this Budget is in the right direction.

Madam, I just want to say that this Government has got a vision and a will to do. The things, which were impossible till yesterday, have been made possible today by Shri Narendra Modi ji and his Government. As I said, population was just a stumbling block in the development but he converted it into a human asset. Secondly, it was said that poverty cannot be removed. But he waged a war on poverty, and 25 crore people have come out of poverty. How did they come out of poverty? They were given houses, electricity, gas, water, food, etc. The next step is for improvement in their economic systems.

Thirdly, it was impossible to remove corruption. But he removed it. And, the best example is DBT, where Rs. 3,48,000 crores have been saved. This DBT benefit is for 38,00,000 crore people.

Madam, a leader should have two qualities. They are credibility and acceptability, which our leader has. If we talk about the credibility of Shri Narendra Modi ji, after Shri Lal Bahadur Shastri, the former Prime Minister and a great leader, it is only Shri Narendra Modi ji who has won the hearts of the people. Shri Lal Bahadur Shastri asked to give one meal for the sake of the country, and the whole country was ready to give it. No other Prime Minister had that kind of morality, leadership quality, and the confidence of the people. ? (*Interruptions*)

Shri Narendra Modi ji asked people to give up their LPG benefits, and more than six crore people gave up the LPG gas benefits. No other Prime Minister had done it. It requires a lot of guts to do it. And, that is what Shri Narendra Modi ji did through his honest personality.

Madam, I have last two points to make. A lot has been said about the Constitution that the changes in Constitution will happen. In fact, most of the amendments made during the last 10 years by Narendra Modi ji only consolidated the Constitution. The fear was put in the minds of the people from SC/ST community that the reservation will be removed. How can one remove the reservation? It is Shri Narendra Modi ji who extended 10 years of SC/ST reservation. It is Shri

Narendra Modi ji who gave the Constitutional Status to the National Commission for Backward Classes. It was Shri Narendra Modi ji who revoked Article 370, and gave the opportunity to SC/ST in Jammu and Kashmir. It was not there for 75 years. It was Shri Narendra Modi ji who had given the opportunity to all the SC/ST community people and poor people for their economic entrepreneurship through MUDRA loans.

Lastly, madam, I just want to tell this House that a lot of criticism has made against on our Leader. I am really not worried about it because अच्छे लोगों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, जो है नाम वाला वही बदनाम है ।

Our Prime Minister is like a Neelkantha. He will swallow whatever they say. But he will only give *Amrut*. That vision of Amrit Kaal is only due to him, and it will be achieved. And God willing, in 2047, our children will remember our great Leader, Shri Narendra Modi ji, his strategy, his decisions, his administration, and also the great Budget presented by our hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji. Thank you.

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, सरकार भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी बता रही है । इसके बावजूद वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में आगाह किया है कि भारत की ग्रोथ के सामने ब्रेकर का खतरा बरकरार है ।

महोदया, यह बड़ी गम्भीर बात है । हालांकि, यह बजट अपने आप में अपने दायरे में महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन बिहार की विशिष्ट चुनौतियों और संभावनाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से असफल है । सरकार के विभिन्न वादों, योजनाओं और राज्य में ?डबल इंजन? की सरकार के होते हुए भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना बिहार के प्रति इस ?डबल इंजन? की सरकार की नीति को दर्शाता है कि यह ?डबल इंजन? की सरकार बिहार के विकास के प्रति कितनी गम्भीर है, जबकि बिहार की बदौलत ही आज केन्द्र की यह सरकार चल रही है ।

महोदया, यह सरकार भावनाओं को जगा कर कैसे राज करती है, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ । गरीबों से वोट लेकर और फिर उनको और पीछे ढकेल कर, 150 करोड़ की जनसंख्या में आधी आबादी गरीब है, और ये गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले 75 से 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम अनाज फ्री दे रही है और ये गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं ।

महोदया, हम आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहेंगे कि आप जिन 80 करोड़ आबादी को, जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, उन्हें आप 5 किलोग्राम फ्री अनाज दे रहे हैं और उसके बदले में उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई जी.एस.टी. के रूप में आप उनसे वसूल रहे हैं । यह कहां का न्याय है? सरकार गरीबों के साथ किस तरह का न्याय कर रही है?

महोदया, हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये छात्रों की बात करते हैं, उनसे वोट लेते हैं, पर एडुकेशन बजट दिन-प्रति-दिन कम करते जाते हैं। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, इस पर सरकार की स्पष्ट नीति इस बजट में नहीं दिखती है। जो कमरतोड़ महंगाई है, उस महंगाई को यह सरकार कैसे कम करेगी, उस पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

महोदया, दक्षिण बिहार में सुखाड़ वाले क्षेत्र के किसानों को ये उससे कैसे निजात दिलाएंगे, इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि ये गरीबी उन्मूलन की जो बात करते हैं, तो हमारे भारत में जातियों का एक समूह है और इन जातियों को तभी लाभ हो सकता है, जब जनगणना जाति आधारित होगी और 65 प्रतिशत आरक्षण देकर उसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह सरकार गरीबी की बात करती है, पर गरीबों के कल्याण के लिए हम महंगाई को कैसे दूर करेंगे, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है।

महोदया, हम औरंगाबाद, बिहार से आते हैं। औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद का अधिकांश इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग - 2 पर बसा हुआ है। औरंगाबाद से गया की दूरी तकरीबन 112-114 किलोमीटर है। वहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, लेकिन औरंगाबाद में किसी प्रकार के कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि औरंगाबाद में एन.एच. की काफी लम्बी दूरी है, इसलिए वहां एक ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण किया जाए। औरंगाबाद के देव प्रखण्ड में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हुई है, उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का विचार सरकार करे।

सभापति महोदया, आपने हमें इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, एक युवा महिला सांसद होने के नाते मैं यह अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से फाइनेंस बिल, 2024 पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। मैडम, हम आम बजट के बाद पहली बार बोल रहे हैं, इसीलिए हम अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देंगे कि उन्होंने सातवीं बार सफलतापूर्वक एक बजट पेश किया है और इस बात से एक चीज़ तो ज़रूर साबित होती है कि बजट घर का हो या देश का, अगर वह किसी महिला के हाथ में है तो परफॉर्मंस और प्रॉस्पेक्टिटी दोनों की गारंटी है। इस सदन में हम उन दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं यानि युवा और महिला।

महोदया, जब देश में चुनाव होता है तो लोकतंत्र अपना एक जनादेश देता है और हम बहुत गर्व के साथ यह बता रहे हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लक्ष्य के साथ तीसरी बार जनता ने हमें अपना मतदान रूपी आशीर्वाद दे कर सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश दिया है।

आज 11 जून, 1964 का वह दिन याद आता है, जब तब के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने देश को पहला संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ?There comes a time in the life of every nation when it stands at the crossroads of history and must choose which way to go.? 140 करोड़ देशवासियों ने इस चुनाव में हमें अपना निर्णय दे कर एक स्टेबल सरकार को चुना है। वर्ष 2004 से 2014 का जो दस साल का हमारे देश का पीरियड था, उसको उन्होंने चुनौती दी है, जब देश को सिर्फ घोटालों और देश विरोधी गतिविधियों से जाना जाता था। मैम, जब हम यूपीए सरकार को याद करते हैं तब उसको श्री-सी की सरकार से याद करते हैं ? करप्शन, कम्यूनलिज़्म एण्ड कनफ्यूज़न। परंतु जब हम एनडीए की सरकार को याद करते हैं तो हम उसको श्री-डी सरकार के नाम से याद करते हैं, जो है डेवल्पमेंट, डेडिकेशन एण्ड



डिलीवरी। डेडिकेशन, हर वर्ग को सुरक्षा और विकास देने की है। हमारा डेवलपमेंट का विज़न है और हम यह भी प्रयास करते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, वे हरेक व्यक्ति तक टाइमबाउंड डिलीवरी सिस्टम से पहुंचें। हमारे वादे, चाहे वह राम मंदिर का हो, आर्टिकल-370 का हो, जीएसटी का हो या सीएए का हो, हमने जितने भी वादे किए हैं, उनको लागू करने का पूरा प्रयास किया है।

मैडम, हम गर्व के साथ कहते हैं कि जनता ने श्री सी नहीं श्री डी की सरकार को चुना है। इस सदन में अक्सर हमारे तब के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से लाभार्थी को अगर सौ रुपये भेजे जाते हैं, तो लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपये ही पहुंच पाते हैं और 85 रुपये भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। हम आज गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली से सौ रुपये जाते हैं तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक सौ रुपये पहुंचते हैं और कोई भी नागरिक एक रुपया टैक्स भरता है तो उसको योजनाओं से दस रुपये का लाभ होता है। अगर इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो एनडीए सरकार का रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। मैडम, अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो वर्ष 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब उनको मज़बूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो हमारे तब के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो अच्छे काम किए गए थे, उसकी वजह से था। वह हमारे देश को एक सुपर पावर बनाने का एक सुनहरा अवसर था, पर इन लोगों ने मिल कर हमारे देश को 50 साल और पीछे ले जाने का काम किया। तब भारत का करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस ऑफ 0.5 पर्सेंट जीडीपी पर था। डेफिसिट वर्ष 2009 से 2014 तक 3.3 पर्सेंट हो गया। आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद भी करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.7 पर्सेंट पर है।

विपक्ष के लोग हमेशा सरकार को मंहगाई पर घेरते हैं। हमेशा कहते हैं कि इस सरकार में मंहगाई बहुत ज्यादा है तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का एवरेज वाजपेयी जी के समय 4.1 पर्सेंट था, जो वर्ष 2004 से 2009 में बढ़ कर 5.8 पर्सेंट हो गया और वर्ष 2009 से 2014 में तो यह 10.4 पर्सेंट हो गया। हमारे कार्यकाल में यह वर्ष 2014 से 2019 तक 4.45 पर्सेंट था और आज जब कोरोना की महामारी के बावजूद वर्ष 2019 से 2024 के बीच कंज्यूमर इन्फ्लेशन प्राइस 5.69 पर्सेंट है।

उसके बावजूद हमारे देश का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5.69 पर्सेंट पर है। यह हमने तब करके दिखाया, जब हमें एक कमजोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। आज जब हम इन्वेस्टर्स से पूछते हैं कि ?How is the investment?? तो वे कहते हैं कि ?High, Sir.? भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर राज्य में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज कश्मीर में यूई का एम्मार ग्रुप जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, वह 500 करोड़ रुपये का निवेश करके मॉल और आईटी टॉवर बनाने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि इनके कार्यकाल में कश्मीर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या होता था।

महोदया, आज जब बजट आया है और हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, तब विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि यह बजट पार्शियल है, यह बजट सिर्फ बिहार का बजट है। उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9.7 लाख करोड़ हैं, जो पिछले वर्ष से 13 पर्सेंट ज्यादा है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक 214 मिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक भारत में रिकॉर्ड 70 बिलियन डॉलर एफडीआई आया है, जो वर्ष 2013-14 में सिर्फ 36 बिलियन डॉलर थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार की इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बिहार की इकोनॉमी एस्पायरिंग इकोनॉमी है। जब भी केंद्र सरकार ने बिहार को सहयोग किया है, तब बिहार और मजबूती से खड़ा हुआ है।

महोदया, मैं बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बजट के लिए इतनी अच्छी घोषणाएं बिहार के लिए की है। अगर जॉन एफ. कैनेडी की बात कहें तो वह कहते थे कि American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good.? मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन सारे शब्दों के लिए बिहार का उदाहरण दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बिहार को लगातार विकास की ओर लेकर जाएगी। सरकार ने बिहार को हाइवे डेवलपमेंट के लिए 26 हजार करोड़ रुपये दिये हैं, जिसमें पटना-पूर्विका एक्सप्रेसवे है, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे है। इससे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बल मिलेगा तथा रोजगार क्रिएट होगा।

महोदया, इतनी सारी योजनाएं, 48 लाख करोड़ रुपये का बजट, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, हर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब सिर्फ इन्हीं दस सालों में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था तो वही है और अधिकारी भी वही है, लेकिन जो बदला है, वह सिर्फ हमारा काम करने का ढंग, क्योंकि हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है और हमारे पास देश का सेवा करने का नियत भी है।

आज जो फाइनेंस बिल आया है, वह हमारे देश के लिए एक नयी ग्रोथ स्टोरी लिखेगा। क्योंकि आज हम टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर फाइनेंस बिल और टैक्सेशन की बात करें तो हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वह इस पर निर्भर करती है। पिछले दस वर्षों में टैक्स बेस्ड रिफॉर्म्स किए गए हैं। हमारा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, वह पिछले वर्ष 34,64,792 करोड़ रुपये था। इस वर्ष 38,40,170 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विपक्ष वाले हमेशा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उनकी सहायता नहीं करती है। मैं उनको बता दूँ कि इस 48 लाख करोड़ रुपये में से 30 प्रतिशत जो 12,47,211 करोड़ रुपये राज्यों को दी जाएगी। हमारी सरकार की नीतियों के कारण हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू वर्ष 2014 में नौ लाख करोड़ रुपये था। वह आज बढ़ कर 25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिकॉर्ड 11.8 प्रतिशत पर है। हमारी सरकार ने जीएसटी लगा कर पिछले 70 वर्षों में जो सबसे बड़ा सुधार है, उसे किया है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में दो लाख करोड़ रुपये का स्तर पार किया है। जीएसटी काउंसिल की गठन के बाद हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बल दिया है। उसने एक नयी मीनिंग और डेफिनेशन दिया है।

महोदया, फाइनेंस बिल बहुत ही आवश्यक बिल होता है, क्योंकि हर सेक्टर को इसमें इंसेंटिव देने का काम किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी जब बजट का भाषण सुनता है तो सबसे ज्यादा अगर वह गौर से सुनता है तो वह हमारे टैक्सेशन प्रोजेक्ट्स को सुनता है। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने उन्हें निराश नहीं किया है और न्यू टैक्स रिजिम रेट स्ट्रक्चर को रिवाइज करके एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम लाया है, जिसने सैलरीड एम्प्लॉई हर साल 17,500 रुपये का इनकम टैक्स सेविंग कर पाएगा। इसका लाभ मध्यम वर्ग के लोगों और निम्न वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा होगा। सरकार द्वारा Standard deduction for salaried employees को 50 हजार रुपये से बढ़ा कर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। Deduction on family pension for pensioners को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है।

इन प्रावधानों से मिडल क्लास को लाभ होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिलेगा। हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है, उसको पूरा किया जाएगा। आज भारत स्टार्ट-अप के क्षेत्र में पूरे विश्व

में प्रसिद्ध है और हम यह बता देना चाहते हैं कि आज भारत थर्ड लार्जस्ट स्टार्ट-अप हब है, जिनकी संख्या 1.25 लाख है और 110 यूनीकानर्स हैं ।

मैं एक बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट सदन के सामने रखना चाहती हूं । ये जो रेकग्नाइज्ड स्टार्ट-अप्स हैं, उनका 45 पर्सेंट टायर टू, टायर थ्री सिटीज़ में है । इसका यह मतलब होता है कि सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि हमारे बिहार के बक्सर या भागलपुर में कोई बैठे हुए हों तो वे भी आज लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वे अपने स्टार्ट-अप के माध्यम से हमारे प्रदेश का विकास कर रहे हैं । इन स्टार्ट-अप्स को और बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स को एबॉलिश करने की घोषणा की गई है । इससे अर्ली स्टेट स्टार्ट-अप को फंडिंग देने में आसानी होगी और लिटिगेशन कम करेगा । जब लिटिगेशन कम होगा तो फोकस इनोवेशन और ग्रोथ पर होगा ।

हमारे जो छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, जैसे मेरा क्षेत्र समस्तीपुर है, ऐसी सारी जगहों पर भी जोमैटो, स्विगी, अमेज़ान जैसी कंपनीज़ ऑपरेट करेंगी और वहां युवाओं को रोजगार मिलेगा । ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए delays in TDS payments up to the due date of filing the TDS statement is proposed to be decriminalised. एक और आंकड़ा रख रहे हैं । टैक्सेशन में सबसे बड़ा हिन्ड्रेंस लिटिगेशन होता है । हमारी इकोनॉमी के 12 ट्रिलियन रुपये अभी भी टैक्स डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, जो जीडीपी का ऑलमोस्ट 6 प्रतिशत है । इस बजट में विवाद से विश्वास स्कीम की घोषणा की गई है, जिससे ये सारे जो पेंडिंग इंकम टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा । To reduce the litigation in international taxation and enhance certainty, the Government proposes to expand the scope of safe harbour rules and streamline the transfer pricing assessment process. यह फाइनेंस बिल एक तरह का स्टेटमेंट है । जनता की मेहनत का जो पैसा है, उसे सरकार वापस इनवेस्ट करती है । हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं । हम उन 9 प्राथमिकताओं को जरूर एचीव करेंगे और विकसित भारत, विकसित बिहार का एक नया प्रमाण देंगे । यह देश पिछले 10 वर्षों से रिफॉर्म में है और सकारात्मक बदलाव देख रहा है । हमारा देश आज फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमीज़ से टॉप 5 इकोनॉमीज़ की तरफ बढ़ रहा है और जी-20 के माध्यम से आज हमारा देश एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया है । हमने अपने देश के नागरिकों के सपनों को पूरा होते हुए देखा है, चाहे चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो, धारा 370 हो या हमारे प्रभू श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा हो ।

आज हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं । हमारे सामने जो चुनौती है, वह तो है । हमारे पास अवसर भी है और एक विजन भी है । अपनी वाणी को विराम देने के पहले हम धन्यवाद देंगे हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके लगातार प्रयासों की वजह से आज हमारे प्रधान मंत्री जी का जो सपना है, उसको बिहार में धरातल पर हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं । ? (व्यवधान) विपक्ष के लोग हमेशा हमारी नीयत को कोसते हैं, हमारी नीति को कोसते हैं, हमेशा हमें कोसते रहते हैं । हम रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से आते हैं । हम इनके लिए सिर्फ दो पंक्तियां पढ़ेंगे ।

?सच है विपत्ति जब आती है,

कायर को ही दहलाती है,

सूरमा नहीं विचलित होते,

सैनिक नहीं धीरज खोते,

विघ्नों को गले लगाते हैं,

कांटों में राह बनाते हैं ।?

जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर ।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदया, धन्यवाद । जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है । सरकार की, उस पक्ष की बातों को सुना जाए, तो सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है । धन प्रबंधन एक बड़ा विषय है । मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से बहुत कम समय में कुछ कहना चाहता हूँ । केवल एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा । ऐसा धन प्रबंधन है कि हम सांसदों को 5 करोड़ रुपये सांसद निधि मिलती है । यह जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है, लेकिन, इसमें 4 करोड़ 90 लाख रुपये ही मिलते हैं । जब आप जिले पर धन लिखेंगे तो 2 पर्सेंट स्टेशरी चार्ज कटेगा और 18 पर्सेंट जीएसटी कटेगा तो आप 3 करोड़ 90 लाख रुपए का ही बमुश्किल काम करा सकते हैं । यह सरकार का धन प्रबंधन है ।

अगर इससे अधिक सत्ता पक्ष के साथी पाएंगे तो हमें बताएंगे । जो धन प्रबंधन है, उस दिन वित्त मंत्री जी का भाषण सुनकर बड़ा अच्छा लगा था कि सात लाख रुपये तक हम टैक्स नहीं लेंगे, जो तीस लाख रुपये कमाएगा उससे इतना लेंगे, अस्सी करोड़ रुपये कमाएगा, उससे इतना लेंगे । लेकिन यह नहीं बताया गया कि जो डायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट कर से जनता मारी जा रही है । डायरेक्ट कर वालों को कितना लाख रुपये उनके बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जो अधिक करदाता हैं, उनका कर्ज माफ होता है और उनका धन बट्टा खाता में डाल दिया जाता है और कम कर देने वाले मतदाता पम्पिंग सेट का ऋण भी माफ नहीं होता है । अगर दस हजार रुपये कर्ज लिया है तो वह भी माफी नहीं होता है ।

मैं सत्ता पक्ष से कहूंगा, सब चंगा है । जब रेड सिग्नल पर आपकी गाड़ी का शीशा पोंछते हुए कोई बेटी या बेटा न मिले । जब पैसे के अभाव में किसी बेटी की शादी रुकती है तब पीड़ा होती है । आज तक यह सरकार कहती है, हमको बड़ा भ्रम होता है - विकसित भारत, विकसित भारत । विकसित भारत की कल्पना में मैं भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को साधुवाद देता हूँ कि सदन में भाजपा का नाम लेना बंद कर दिया है । मोदी जी के नाम से भाषण शुरू होता है और उन्हीं के नाम पर खत्म होता है । विकसित भारत में थाने का चौकीदार आज भी रोज चार सौ रुपये नहीं पाता है, गरीबों की सेवा की करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, सहायिका, आशा बहू, शिक्षा मित्र और मनरेगा के मजदूर को भी चार सौ रुपये रोज नहीं दे पाएँ और 400 पार का नारा दे रहे थे ।

आपने बहुत सारे शौचालय बनाएँ, कितने का शौचालय बनाया - बारह हजार रुपये का । फाइव स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा बारह हजार रुपये है । मैं लाख रुपये वाले होटल में नहीं गया । आप जल नल से फ्री में पानी दे रहे हैं तो छाती पीटा जा रहा है । यह भी देखिए कि एक लीटर पानी बोतल एक हजार रुपये में और पचास रुपये में एक लीटर दूध मिल रहा है ।

डायरेक्ट टैक्स किस तरह से आता है, सभी सांसद महोदय यहां बैठे हैं । अगर सरकार के लोग बड़ी गाड़ियों से न जा रहे हों तो हर शहर में लेबर बाजार देखने को मिलेगा, वहां चार सौ, पाँच सौ और एक हजार लेबर खड़े रहते हैं । कोरोना के बाद आपकी व्यवस्थाओं की वजह से लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, ट्रेन्स थीं, लेकिन लोगों को पैदल चलना पड़ा, लोग मरे । सारे रोजगार बंद हुए, वे लोग लेबर हैं । काम के अभाव में इतने महंगे सीमेंट और छड़ हो गए हैं कि लोगों ने घर बनाने बंद कर दिए हैं । आप शराब पर सबसे अधिक टैक्स लेते हैं

और वह लेबर भी शराब पीकर आपको टैक्स देता है, धन प्रबंधन में आपकी मदद करता है। क्या आपने उसके बच्चे का पढ़ने का इंतजाम किया? जब समय आता है तो कॉपी-किताब पर जीएसटी लगाते हैं।

### **17.00 hrs**

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे दल के साथी को बोलना है। जब इन्वेस्ट करने की बात होती है, इन्वेस्ट के नाम पर उत्तर प्रदेश में करीब सात साल से जब से यह सरकार बनी है, रोज इन्वेस्टर्स बुलाए जाते हैं कि आएं, इन्वेस्ट करेंगे, हमारा विकास होगा और धन बढ़ेगा। इन्वेस्ट करने पर कितने करोड़ रुपये खर्च हुए? इस पर जितने करोड़ रुपये खर्च हुए, उतना निवेश हमारे प्रदेश में नहीं हुआ। आप निवेश ठीक करेंगे नहीं, आप उधार देंगे लेकिन उधार लेंगे नहीं, आप बाजार को देखेंगे नहीं। आपने माल संस्कृति ला दी। आप भूल गए कि छोटा व्यापारी, जो एक हजार रुपये में किराए की दुकान लेता है, 500 रुपये या एक हजार रुपये उस दुकान का भाड़ा देता है। उसने छोटी दुकान खोली थी और आपने बढ़ावा दे दिया कि अब नैट से मार्केटिंग हो रही है। लोग फोन करते हैं, मार्केटिंग शुरू हो गई, मॉल वालों का माल तो घर आ रहा है। मॉल वालों से किरयाने का सामान फोन करने से घर आ जाता है। मॉल वालों के जूते, चप्पल, कपड़े और सौंदर्य सामग्री, सब्जी आदि केवल फोन करने से घर तक पहुंच रही है, लेकिन जो गरीब दुकानदार है, व्यापारी है, ज़रा उसकी दशा पूछें, वह अपनी दुकान का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है, किराया तक नहीं दे पा रहा है।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो व्यवस्था दी है, इन व्यवस्थाओं की बदौलत आप विकसित हो सकते हैं, लेकिन देश का गरीब विकसित नहीं हो सकता, देश की झोंपड़ी विकसित नहीं सकता। आप 1 लाख 20 हजार रुपये में आवास बना रहे हैं। क्या 1 लाख 20 हजार रुपये में आवास बनेगा? धन्यवाद।

**SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to speak on Finance Bill, 2024 on behalf of Congress Party. I thank the brothers and sisters of Karur parliamentary constituency who have elected me as a Member of Parliament for the second term with lots of support and affection. Hon Finance Minister usually cites a couplet from Tirukkural or a quote from Sangam literature in the Union Budget. This time she has forgotten Tirukkural, Sangam literature and also Tamil Nadu. The funds that are rightful share to Tamil Nadu are also not provided. Hon Finance Minister has provided the Halwa (sweet dish) to Tamil Nadu and the opposition ruled States of the country. I wish to remind them the Tirukkural which they forgot to quote. ?Iyatralum Eettalum Kaathalum, Kaaththa Vakuthalum Vallathu arasu?. A King or a Government should look for the ways of generating income. After collection of such resources, he should protect those resources. Once it is stored, it should be distributed evenly among the subjects. There are several ways to earn money. Important way is taxation. How much and from whom the tax is collected matters a lot. How the collected money is spent and how much it is spent also do matter. Through these aspects one can come to a conclusion how the governance is taking place. You can get more tax from big industrialists and foreign industrial companies. The Government should

levy more tax from the richest persons. If industries are set-up and employment is generated, you will get more tax collection as revenue. Particularly for States like Tamil Nadu where you have more Industrial growth, if more funds are allocated, tax collection will also increase resulting in income generation. This was done by the UPA led by Congress. But what are you doing now? You lease aside the big business magnates and the foreign companies. You give tax rebates to them. Whereas you snatch away from the poor and lower strata people as a heartless robber by hitting them and collecting heavy taxes from them. Good example of this is the Diesel, Petrol and cooking gas. You always make a comparison of UPA and NDA Governments. I also make a comparison. When Congress Government

was in power, one litre petrol was sold for Rs 73 and 18 Paise; 1 litre diesel for Rs 40 and 90 Paise; and cooking gas Rs 450 per cylinder. Now whether diesel or petrol both sold at Rs100 per litre. Cooking gas is Rs 1200 per cylinder. Thanks to election. The excise duty on petrol and diesel has been increased to 250 per cent. For one litre of petrol, it has been increased from Rs 1 and 48 Paise to Rs 32 and 98 Paise. The excise duty on diesel increased 800 percent. For one litre of diesel, it has been increased from Rs 3 and 56 Paise to Rs 39 and 81 Paise. During the UPA regime led by Congress, tax revenues stood at Rs. 90,000 crores. During the Amrit Kaal, Ache Din Golden regime of the BJP it stands at Rs 2.7 lakh Crore. Tax revenues have increased upto 176 per cent. This is just a testimony. What can we say other than the day loot? Next issue is GST. During July 2024, the collection of GST increased by 10.3 percent. It stands at 1.82 trillion. Mostly from the domestic transaction. All essential commodities are levied GST from 5 per cent to 18 per cent to 25 per cent. It is 5 per cent GST for cooking oil, sugar, spices, tea, coffee, toffee, and lifesaving drugs. It is 18 per cent GST for hair oil and toothpaste. It is 18 % for luxury items such as small cars, AC and Refrigerators. If you live in a middle-class family in the urban areas, you will come to know what a luxury item is and what is not. On the top of it, there is 15 per cent GST on life insurance and health insurance policies. But the GST on coal has been reduced from 11.69 per cent to 5 per cent. Why is it so? I read something interesting on a website. I quote, "India's first private mining company who pioneered concept of mind developing MDO just about a decade, is our inception we became one of our largest developers and operators of Coal mines in the country?". Unquote. No price for guessing it. It's Adani. Sorry I can't quote. It is A1. As soon as the BJP came to power in the year 2019, the Corporate Tax was reduced from 30 to 22 per cent. But as a result of this, there was a revenue loss of Rs. 1.45 lakh crore. Now the tax for foreign companies has been reduced from 40 to 35 per cent. E-commerce. Amazon and Flipkart are the big companies

which were paying 2 percent tax. This was reduced to zero per cent. These companies are poor companies. Can the Government ask tax from them? There are poor and middle-class people for paying tax. This is just a trailer. If you see the whole film, as told by Mahakavi Bharathi, 'Our hearts will not tolerate?'. What have you done after snatching so many things from the poor and middle-class people? You have created unemployment unprecedented in this country for the last 45 years. ILO report says Indian youth account for 83% of unemployment population in 2022. If 83 per cent of a country's youth is unemployed, not only their future, the future of that country will also go to darkness. But you are not bothered about that.

Manufacturing Sector. Manufacturing sector was in second place as regards employment generation and now it has gone to fourth place. I come from Karur. India's fourth largest exporting city. Our city which gave employment to 2 lakh persons is now struggling to provide employment for 50,000 persons. Thanks to your GST. Make in India had ambitious target of 12 per cent to 14 per cent of manufacturing growth per annum. But what is the outcome? Average 5.8 per cent growth is achieved since April 2014. Why? Micro Small Medium Enterprises MSMEs are facing severe problems during the BJP regime. Government is selling all its resources to its friends A1 and A2. Those who do not get jobs in industries are turning into labourers. You are also affecting the 100 days' work guarantee Scheme. If 100 days of work should be given to all 6 Crore registered persons, you have to allot 2.72 Crores. But you have allocated only Rs 86,000 crores. Due to less allocation, it becomes unable to release payments of wages for 3 to 4 months to the people who worked under this Scheme. Next issue is Agriculture. You said you will double the income of farmers by 2022. But in the year 2019-20, the Budget for Agriculture was 4.97 per cent i.e. almost 5 per cent. But now it has been reduced to 2.6 per cent. Between 2018 and 2023, the Agriculture Ministry has returned Rs. 1 lakh crore an unspent balance. You could have waived off farm loans from this amount. You could have built a better infrastructure. But you won't do it. In every one hour, a farmer or a farming labourer is committing suicide in this country. Under this Government, loans of 50 per cent farmers have doubled. Similarly, the Budget outlay for Department of School Education and literacy program was reduced from 3.16 per cent in 2013-2014 to just 1.53 per cent in 2024-25. You are not concerned about the education of our students. You want to impose your New Educational Policy on us. But just remember that Tamil Nadu will never accept you New Educational Policy. Tamil Nadu is a pioneer to India in public health. Hon *Perunthalaivar* Kamarajar?.

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude.

**SUSHRI S. JOTHIMANI:** Madam, just one minute. I am going to wind up. *Perunthalaivar* Kamarajar brought the midday meal Scheme 50 years ago. Congress Government implemented this Scheme throughout the country. Hon Chief Minister of Tamil Nadu Annan Thiru Stalin is providing breakfast for children in schools of Tamil Nadu. It is nowhere implemented in the country. You should come forward to implement such Schemes. There are so many issues in the country. But for you, the caste is important. Looking at our Leader, you are asking the caste of our Hon Leader of Opposition. This reference is expunged from the proceedings of the House. Hon. Prime Minister discloses the disrespectful conversation along with the expunged portion in the public domain. Are you not ashamed of this?

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude.

**SUSHRI S. JOTHIMANI:** Madam just give me 30 seconds. Are you not ashamed? Whether caste is your identity? If caste is your identity; then for us the social justice is our identity. If hatred is your identity, then for us love is the identity. If divisive politics is your identity; then unity is our identity. If the 'Code of Manu' is your identity, then democracy is our identity. The Constitution which upholds democracy is our identity. One day or other the 'Code of Manu' will be buried inside this land. Thanks. Our flag of social justice will fly so high. We will conduct the Caste based socio economic census in this country. We will uphold social justice. We will create India as peaceful and prosperous. To whom you have asked for disclosing his caste. To whom you are afraid of. Today's Hon Leader of Opposition will be the Prime Minister of Tomorrow. Our leader Shri Rahul Gandhi will lead and complete this noble task. INDIA will win that day. Thank you.

**SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL):** Thank you, Madam Chairperson.

While speaking on the Union Budget earlier, as far as possible, I had dealt with every aspect of the provisions that were made in the Budget, which was presented by the hon. Finance Minister. I had also spoken on the Demands for Grants under the control of the various Ministries and Departments. The Appropriation Bill was passed by the House.

Today, on the Finance Bill, I will specifically go about the peculiar aspects which are there in the employment sector, which is affecting public sector in particular, and people and employees in general. Madam Chairperson, the Union Government has



asked the public sector insurance companies especially, the National Insurance Company Limited, United India Insurance Company and Oriental Insurance Company about the same. The Government has not only asked them, but also, a caution or notice has been given to them to move away from their core business, that is, stop the lines, as it has been spelt that way. And this has been done by the Department of Financial Services (DFS). Their core business includes, motor insurance and health sector, which are the main revenue-earning arms of the insurance companies. Since inception, -- even in the monopoly sector, which prevailed till 1990s, and in 1999, when the entire insurance sector was opened up for the private players -- these public sector insurance companies have been doing extremely well. All along, they have been paying handsome dividends to the Central exchequer, and as far as their functioning was concerned, it had no complaints all over. It was also entrusted with employment by the Government, and they did take the responsibility of putting up with thousands of employee force, which worked under the public sector. But today, what is the situation? They are being asked to go away or to look at some other avenues to mop up insurance revenue by stopping their motor insurance business and health sector, the reason being that whatever revenue is earned, the claim payment is much more than the revenue and, therefore, they are being incurring losses.

Then came the issue of infusion of capital which the Government of India did in the financial year of 2020-21 in two tranches and some Rs. 17,500 crores were infused. Recapitalisation was done in these three companies. After the same, the turnaround is very evident. If we go by the figures, the United India Insurance Company has made a remarkable turnaround, reducing its losses from Rs. 5000 crores in the financial year 2022-2023 to a profit of Rs. 19 crores in the financial year 2023-24.

National Insurance Company has significantly narrowed its losses from Rs. 3800 crores in 2023 to Rs. 187 crores. Similarly, Oriental Insurance Company has also done its bit where they are cutting down the losses and they are moving towards profit making economy for their organisations.

There are four insurance companies. Out of them, New India Assurance Company is doing extremely well. They have done Rs. 1000 crore profit in the last year. This time, it is Rs. 1100 crore. But these things which are being pushed on them and what kind of level playing field is being given by the Government and ensured by the Government to see that private players who have entered the industry some 30

years back, now they have taken over or are in the race to take over the public sector companies. The level playing field, I am referring to because social sector schemes, are driven by the public sector companies. These private players never venture into obviously because they are not profit-making schemes. Rural insurance is also taken up by the Public Sector which they are doing diligently but at no reward or no award or no appreciation rather.

But when you come to restrict these public sector insurance companies, the Government seems to be very harsh and this should not be done as public sector banks have seen that over the years when their NPAs grew, over the years, for a decade or so. ? (*Interruptions*)

Give me 2-3 minutes. This is very important. If you do not want to know the ground realities, I will sit down. I have no issues.

So, against this backdrop, how are we going to match? The public sector companies are doing well. Piyush Ji is here. He has seen these companies over the years. If we do not give them the kind of impetus or kind of incentive which is needed at this stage, the things will not be in the interest of the Indian economy and it will be suffering like any other thing.

Today, what is the scenario? For last more than 5-7 years in the general insurance industry, all four companies have not seen wage revision. LIC is doing well. LIC got its way but what about other companies. Why are employees being restricted? Why are employees being deprived of their constitutional right? They have been putting in every effort to see that the company does well. So, my request would be to look at the private players and look at the scenario in the public sector. The DFS has also accepted the fact that there are no recruitments in the public sector which owns the responsibility to shoulder to see the unemployment aspect is addressed in a big way, which is not happening. So, employment needs to be opened up in public sector companies and wage revision needs to take place and with this. On mediclaim which is needed by the people at large, Nitin Gadkari Ji has written to Finance Minister to reduce GST. Time and again, Arvind Sawant Ji and myself have been crying at the top of our voices. We have been making for the people that 18 per cent which is being levied on GST on the health policies and LIC policies is beyond affordability. This needs to be addressed.

Madam, I have a last point. Hon. Finance Minister has come out with the schemes which are really needed. Employment schemes with employment linked incentives

have come. These are the schemes that have come up. Three schemes have been spelt out. But what is the reality? Do the manufacturers and private entrepreneurs from MSME come ahead to hire them up? Are they really willing to infuse their own capital or private capital? Otherwise, these schemes which are really looking good on paper will not come into practicality any more. If that is to be stopped, unemployment really is to be answered or it has to be addressed. These are the things which are right in front of you. Otherwise, schemes after schemes will be spelt out but absolutely unemployment will be the biggest problem for the country.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदया, आपने मुझे फाइनेंस बिल, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह फाइनेंस बिल, 2024 एक विकसित भारत की ऐसी आधारशिला है, जो एक आर्थिक यात्रा का ऐतिहासिक कदम है। मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। यह बिल कोई राजकोषीय नीतियों का संग्रह नहीं है, लेकिन यह फाइनेंस बिल, 2024 विकास को बढ़ावा देने के लिए है, यह बिल निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है और यह बिल पारदर्शिता तथा दक्षता को सुनिश्चित करने का है। इसमें कर ढांचे को सरल बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर मैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पर जाऊँ तो यह उचित होगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि ?किसी राज्य को असभ्यता से लेकर सबसे अधिक समृद्धि तक ले जाने के लिए शांति, आसान कर और न्याय का सहनीय प्रशासन ही सबसे जरूरी है। यह बिल सारी जरूरतों और कंडीशंस को पूरा करता है।

महोदया, इस फाइनेंस बिल का उद्देश्य देश में ऐसा वातावरण बनाना है, जिससे व्यवसाय और निवेश फल-फूल सकें और आर्थिक समृद्धि का आम नागरिकों को फायदा हो सके। जब मैं आम नागरिकों की बात करता हूँ तो प्रधान मंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और सोच तथा उनके नेतृत्व में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने यह फाइनेंस बिल और बजट रखा है, क्योंकि कुछ बातें दोनों पर ओवरलैपिंग आ सकती हैं। एंपावरमेंट ऑफ द टैक्स पेयर, सतत आर्थिक विकास करना, प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना, इस फाइनेंस बिल का इंटेंट है, मोटो है और ऑब्जेक्टिव है। यह मानना है कि जब तक छोटे करदाताओं के हाथ में पैसा नहीं होगा और अगर उनको हम सशक्त नहीं बनाएंगे तो जितना उनके हाथों में पैसा होगा, वे अधिक खर्च करेंगे। अगर वे अधिक खर्च करेंगे तो वह पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा आने की वजह से ही भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, वह उसी वजह से बनेगी। अगर हम इसकी पूरी स्पिरिट देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ही एडेक्वेट है, उच्चतम स्तर का है। वर्ष 2023-24 में टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें तो 11.6 परसेंट है और डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 6.6 परसेंट है, जो यह दर्शाता है कि जब टैक्स का सिंपलीफिकेशन होता है, तब ही यह अचीव होता है। इसका परपज़ है कि मोर पीपल्स इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, मोर कॉर्पोरेट्स पार्टिसिपेट करें और मोर पीपल्स टैक्स पे करें।

सभापति महोदया, अभी हमारे विपक्ष के कई साथियों ने कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन फॉरेन कंपनी पर ऐतराज जताया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रिवीलिंग फैक्ट्स हैं, जिनसे यह पता लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था इनके समय में कमजोर क्यों थी, हमारी मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ कमजोर क्यों थी? आप देखेंगे कि फॉरेन कंपनीज पर जो कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन हुआ है, वह बहुत जरूरी था। उसको 40 से 35 परसेंट किया गया है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टैक्ट को देखें, टाइमिंग को देखें तो पोस्ट कोविड के बाद कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्होंने चाइना प्लस वन पॉलिसी अडॉप्ट की। चाइना प्लस वन पॉलिसी का मतलब यह होता है कि वह चीन से बाहर आना चाहते हैं और ऐसा मैनुफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हब ढूंढना चाहते हैं, जिसमें उनके लिए टैक्स भी कम हो, कंड्यूसिव

हो, पीसफुल हो और इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक हो तथा उनको लेबर भी मिल जाए । ये कंपनियां अभी अल्टरनेटिव मैनुफैक्चरिंग बियॉड चाइना देख रही हैं, जिसमें अगर इंडिया के लिए कंपटीशन है तो वियतनाम कंट्री है, थाईलैंड है, टर्की है । इन कंट्रीज़ से है ।

फॉरेन कम्पनीज़ के लिए 40 परसेंट से 35 परसेंट टैक्स किया गया है । उसका इफैक्ट यह होगा कि It will attract more foreign companies to invest in India. जो कि पहले नहीं होता था । हमारी मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत कम थी । It will increase FDI. It will position India as a global manufacturing hub. इसकी वजह से जॉब्स क्रीएट होंगी । Goods-related sectors like logistics creating further employment in logistics, इससे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट बढ़ेगा । हमें उन कम्पनीज़ की इंकम पर टैक्स भी मिलेगा । लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा । इसमें इंडिया की सक्सैस स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो एप्पल इंडिया का एक साल में टोटल प्रोडक्शन 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का हुआ है । उसका एक्सपोर्ट 85 हजार करोड़ रुपये का हुआ है । 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का अगर प्रोडक्शन होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इंकम टैक्स भी मिलता है और 35 परसेंट टैक्स भी मिलता है । 40 से 35 परसेंट टैक्स करके हमने एक कम्पनी को अट्रैक्ट किया है । This is the highest achievement achieved by any company in a single year. यूपीए के टाइम में वर्ष 2014 तक मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ 5.3 परसेंट थी । यह डिप्लोरेबल है । एनडीए के टाइम में वर्ष 2023-24 की मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ 9.9 परसेंट है । इनकी टैक्स पॉलिसी प्रूडेंट नहीं होने की वजह से मैनुफैक्चरिंग कम्पनीज़ को इन्होंने नेग्लैक्ट किया । इससे मैनुफैक्चरिंग बहुत कम पर आ गयी । 40 से 35 परसेंट टैक्स करने से Potential increase in overall tax collection despite lower rate. You will attract more FDI by lower rates in India. They will earn more. They will pay tax to the country. They will generate more and more jobs. माननीय सदस्य महोदय मोइत्रा ने अपनी स्पीच में कहा कि हमें फॉर्मल जॉब्स ज्यादा क्रीएट करनी चाहिए । मैं भी यही कह रहा हूँ कि फॉर्मल जॉब्स क्रीएट करने का यही तरीका है । मैं प्रधान मंत्री जी को उनके विज़न के लिए धन्यवाद देता हूँ । सीतारमण जी को भी 40 से 35 परसेंट टैक्स करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इससे हमारे देश में ज्यादा एफडीआई आएगी । इससे हमारा जीएसटी कलेक्शन भी इंक्रीज़ होगा due to increase in the economic activities. अगर 85 हजार करोड़ रूपयों के प्रोडक्ट बिकेंगे तो उससे मिलने वाला जीएसटी भी हमें मिलेगा । Positive impact on India's trade balance और हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी । 40 से 35 परसेंट टैक्स करने से हमारी इकोनॉमी में कॉन्सीक्वेंश्ल इफैक्ट आता है । वह हमें देखना चाहिए । इसका लॉन्ग टर्म इफैक्ट क्या होगा? It will enhance India's competitiveness in global manufacturing. India will be treated as a hub of the manufacturing and it supports Make-in-India. प्रधान मंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं । मेक इन इंडिया डोमेस्टिक इवेस्टर्स करें या फॉरेन इवेस्टर्स करें, इससे इंडिया में जॉब्स क्रीएट होंगी, टैक्स इंडिया को मिलेगा और जीएसटी इंडिया को मिलेगा तभी हम पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे । इसीलिए प्रधान मंत्री जी कहते हैं- ?यही समय है, सही समय है ।? यह डिसेज़न सही समय पर लिया गया है जो कि एप्रिसिएबल है । जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात है तो वर्ष 2023-24 में टैक्स कलेक्शन करीब 11 लाख करोड़ रुपये का हुआ है । It is due to lower tax rates, 30 per cent and 25 per cent, for manufacturing.

आपकी टैक्स पॉलिसी में हमेशा प्रिंसिपल रहा ? ?higher the tax?. Higher the tax, lower the income. So, lower the tax means there will be more income for the Government.

यही कारण है कि वर्ष 2024 में 11 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। वर्ष 2014 में यूपीए के समय सिर्फ 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। एक तरफ 11 लाख करोड़ रुपये का हुआ और एक तरफ 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का हुआ और यह इसलिए हुआ, क्योंकि इनकी जो टैक्स पॉलिसी थी, वह प्रूडेंट नहीं थी। उसकी वजह से देश ने सफर किया और लगातार सफर किया। वर्ष 2014 में मोदी जी के आने के बाद उनकी दूरदृष्टि और विजन की वजह से यह संभव हो पाया।

हम देखते हैं कि हम डोमेस्टिक कंपनीज़ को कैसे कम्पीट करें। इन्होंने यह कभी नहीं सोचा। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को लेते हैं तो यूके में डोमेस्टिक कंपनीज़ पर 25 परसेंट टैक्स है। यूएसए में 21 परसेंट है और चाइना में 25 परसेंट है। अगर हम इस स्लैब को बढ़ाते हैं तो हमारे डोमेस्टिक इनवेस्टर्स भी दूसरी कंट्रीज में जाकर इनवेस्ट करने लग जाएंगे। हमें ग्लोबली सोचना पड़ता है और कंट्री के हित में सोचकर ही यह डिसेजन लिया गया है।

इसके बाद बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ तो आप देखेंगे कि ईज ऑफ़ डूइंग और ईज ऑफ़ बिजनेस की वजह से लगभग रिकॉर्ड ब्रेकिंग about 1,85,000 new companies were incorporated in 2023-24. यह इसलिए हुआ, क्योंकि एक एटमॉस्फ़ेर मिला। चाहे फॉरेन कंपनी हो या चाहे इंडियन कंपनी हो, यह उसकी वजह से ही हुआ। मैं इस प्रिंसिपल के पीछे टैक्स रिडक्शन को मानता हूँ।

What is the principle? What is the object? What is the spirit? Why is this reduction? The reason is, lower rates lead to higher compliance. Once you reduce the tax, everybody will pay it. Once you increase the tax, there will be evasion. So, lower rates lead to higher compliance, more economic activity, and more jobs. This is the reason कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी अचीव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट यह हुआ कि हायर एग्रीगेट टैक्स कलेक्शन हुआ, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। Consequently, it provides the Government with more resources for the welfare schemes. This is more important. अदरवाइज अगर यह रिसोर्स नहीं होता तो कोई वेलफेयर स्कीम नहीं होती। मैं जीएसटी की भी बात करता हूँ। वर्ष 2023-24 में करीब 20 लाख 18 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी which does not include other indirect taxes, or the number would be higher. उसके साथ-साथ मैं जब यूपीए की बात करता हूँ तो इनका डोमेस्टिक कंपनीज़ पर टैक्स 25 परसेंट नहीं था, 30 परसेंट नहीं था, उस समय टैक्स 43 परसेंट था और 34 परसेंट था, जिससे कि प्रोडक्शन और एक्सपेंशन में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा टैक्स होने से रिजल्ट क्या हुआ? Lower tax rate collection limits the Government's ability to implementing welfare schemes.

यही कारण था कि उस समय हमारी वेलफेयर स्कीम्स होती नहीं थीं। अगर आप देखें कि इस टैक्स पॉलिसी से कंसीक्वेंशियसली इफैक्ट और फायदा सबसे पहले फार्मर्स को हुआ। 11 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर?पीएम किसान निधि? के तहत मिला। लगभग 3 लाख 11 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों को मिली। क्या आप सोच सकते हैं कि पिछले पांच सालों में इतना पैसा किसानों को मिला। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह गहनता से सोचने की बात है।

मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं फिगर्स बता रहा हूँ। 3 लाख 11 हजार करोड़ रुपये पीएम किसान निधि के तहत प्रधान मंत्री जी ने करीब 12 करोड़ किसानों के खातों में भेजा। अगर एक परिवार में चार व्यक्ति हैं तो उससे 50 करोड़ लोग बेनिफिट हुए। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि गरीबों के लिए भी करीब

3 करोड़ 31 लाख रूरल हाउसेज के लिए पैसा इसी टैक्स पॉलिसी से आया । वर्ष 2016 से करीब 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए, वह राशि चाहे महिला एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे यूथ के लिए हो । मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर यह पैसा इस टैक्स से नहीं आता और टैक्स पॉलिसी प्रूडेंट नहीं होती तो यह वेलफेयर स्कीम नहीं होती । आप जल जीवन मिशन को ही देखिए । यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है ।

आप ?जल जीवन मिशन योजना? को देखिए । यह अपने-आप में विश्व की सबसे बड़ी योजना है । ?जल जीवन मिशन योजना? के तहत हर घर को टैप से पानी देने का लक्ष्य है । इससे लगभग 15 करोड़ हाउसहोल्ड्स, लगभग 60 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा । इसका कारण क्या है? The lower tax is leading to higher collection, and more comprehensive welfare initiatives. What is the long-term vision? The long-term vision is, creating a virtuous cycle of lower taxes, higher compliances, increased revenue and enhanced welfare. All these are mixed together. This happened just because of the prudent tax policy of the Government.

मैं आपको एक छोटा-सा चार्ट बताना चाहता हूँ । ये टैक्स एग्जम्पशन की बात करते हैं । इनके समय में वर्ष 2014 तक डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन दो लाख रुपए थे, लेकिन अब वे सात लाख, 75 हजार रुपए हैं ।

इनके समय में वर्ष 2009 से वर्ष 2014 पांच सालों में इंफ्रा स्पेंडिंग एक लाख, 57 हजार करोड़ रुपए थे । ये वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच में 44 लाख, 30 हजार करोड़ रुपए थे । आप इसमें यह फर्क देखिए - एक लाख, 57 हजार करोड़ रुपए और मोदी जी के समय में 44 लाख करोड़ रुपए । इन्होंने वर्ष 2014 में 13 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट की और पिछले पांच सालों में 320 लाख रुपए वेल्थ क्रिएट हुई है और फॉरेक्स एडीशन 50 बिलियन । पिछले पांच सालों में 350 बिलियन, जीडीपी रैंक 10 से पांच हो गई है ।

हम कई बार एंजेल टैक्स के कॉन्सेक्वेंशियल इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं । एंजेल टैक्स इन्होंने लगाया, यह समझ के बाहर की बात है । इनके बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर थे । हमारे स्टार्टअप्स इनोवेशन करते हैं । वैसे ही हमारे देश में बहुत समय से इनोवेशन बहुत पुअर था, लेकिन यह मोदी जी की सोच थी कि जब तक हमारे यहां इनोवेशन नहीं होगा, हमारे स्टार्टअप्स डेवेलप नहीं होंगे तो हम रिसर्च बाहर से लाएंगे । इसलिए एंजेल टैक्स मतलब कोई फरिश्ता आकर यह इनवेस्टमेंट लगता है । हमारे यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है । उदाहरण के तौर पर अगर हमारा स्टार्टअप एक करोड़ रुपए लगता है और कोई इन्वेस्टर उसमें दो करोड़ रुपए लगाता है, तो क्या होता है कि कंपनी एक करोड़ रुपए की है और आपने दो करोड़ रुपए लगाए, तो आपका डिफरेंस एमाउंट एक करोड़ रुपए है, उस पर आप 30 प्रतिशत टैक्स दीजिए यानी उस स्टार्टअप को 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, तो वह क्या रिसर्च करेगा, क्या इनोवेशन करेगा? इसी वजह से एंजेल टैक्स को खत्म करना, यह प्रधान मंत्री जी के विजन और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी का बहुत बड़ा स्टेप है । उस एक्सट्रा एमाउंट से स्टार्टअप अपना काम कर सकता है । अंडर सेक्शन 56 ऑफ दी इनकम टैक्स एबोलिशन ऑफ एंजेल टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ा, प्रिवियस सिचुएशन क्या थी? The Angel Tax previously discouraged investment in Start-Ups. Secondly, it created a barrier for early-stage funding in innovative companies.

Then, what is the reason for changing this tax policy? The purpose of change in the tax policy was to push investment in Start-Ups and foster innovation, and align it

with the Government's vision of making India a global Start-Up hub. This is what has happened.

What are the positive impacts of it? The positive impacts are that the flow of capital increased into new business. It became easier for the Start-Ups to secure funding without tax complication. It enhanced attractiveness of Indian Start-Ups for domestic and foreign investors. More innovative ideas ? now we do not require to get it from outside ? have been funded and brought to the market. Finally, it grew the potential of significant job creation in the Start-Up sector.

सभापति महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि it was such a small sector, and it happened within a short span of 2016 to 2019. The other data is not available, कितने जॉब्स क्रिएट की गई? सिर्फ स्टार्टअप्स ने सात लाख, 50 हजार जॉब्स क्रिएट की । प्रधान मंत्री जी के सिर्फ इस विजन से सात लाख, 50 हजार जॉब्स क्रिएट हुई । पहले टैक्स था, तो आपको क्या मिला? इन्वेस्टर्स टैक्स के कारण इन्वेस्ट नहीं करते थे । आपने उसको फ्री कर दिया, तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए और सात लाख, 50 हजार जॉब्स क्रिएट हुआ ।

उसकी सक्सेस स्टोरी क्या हुई? It promoted the Indian startup ecosystem. As a result, 114 Indian unicorns have raised more than Rs. 8.3 lakh crore to date and the combined valuation of these unicorns exceeds Rs. 35 lakh crore. यूपीए को यह कभी ध्यान नहीं आया, जो चीज ध्यान में आनी चाहिए थी । इसलिए मैं डेटा से बात कर रहा हूँ । मैं डायरेक्ट कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ । आप इसको रिस्पॉंड करिये । इनके पास में क्या जवाब है? आज देश, जो दस साल में बढ़ा है, उसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा । उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा । पीएम साहब के दिमाग में क्या है? मैं इसे चार पॉइंट्स में बता रहा हूँ ।

It supports India's target of having 280 unicorns by 2030. आप देखें कि 114 unicorns में इतनी जॉब्स का क्रिएशन होता है, इतनी वेल्थ का क्रिएशन होता है तो वर्ष 2030 तक कितनी होगी? लेकिन मेरा मानना है कि वह टारगेट उससे भी पहले अचीव हो जाएगा । The next one is to position India as a leading global innovation hub. The third one is to align with Digital India and Startup India initiatives. The fourth one is to curb brain drain from India and help brain gain. It will curb brain drain क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं । These are the visions of our hon. Prime Minister. Now, they are not required to go outside. Earlier, it was brain drain and now, it is brain gain. It has been possible only on account of this innovative idea of the abolition of angel tax of 30 per cent on the startups.

Now, we have to see the economic benefits out of it. It will accelerate growth of the startup ecosystem and increase innovation across various sectors, not in one sector, covering the entire country. It will give a boost to India's patent and intellectual property creation and funding for R&D. जो कि हम इसमें बहुत पीछे थे । The Government is promoting funding for R&D now not by the Government alone but

by the investor also. This is a good idea. This is the vision of the Prime Minister. That is why, we are talking about the 'Viksit Bharat' by 2047. This is the foundation laid down by the hon. Prime Minister by way of this year's Budget and the Finance Bill. Further, it will enhance global competitiveness of the Indian companies in new technologies.

सभापति महोदया, कई बार हमारे विपक्ष के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि टैक्स के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट का पहले टाइम लिमिट था, पांच साल तक कभी भी कर लो। वह कहां से डॉक्युमेंट लाएगा, क्या करेगा? उसे परेशानी होती थी। लेकिन वे लोग, जो कमजोर हैं, साधारण हैं, जैसे सर्विस वाले हैं, जिनकी 50 लाख रुपये से कम इवेजन है, उनका पहले पांच साल में रीअसेसमेंट ओपन होता था, अब तीन साल के बाद उनका ओपन नहीं हो सकता है। अगर 50 लाख रुपये के ऊपर इवेजन है, तो उनका पांच साल तक ओपन हो सकता है। इसका इफैक्ट क्या हुआ? इसका इफैक्ट हुआ, पहले क्या प्रॉब्लम थी, एक टैक्स अनसर्टेनिटी थी, एक हार्डशिप थी, उसको खत्म किया। उसका फर्क क्या पड़ा? The reasons for the change are to simplify the provisions for reopening and assessment, reduce tax uncertainty and disputes, and decrease the number of litigations. That is more important because that is a consequential effect. The positive impacts are greater clarity for tax-payers on the finality of their tax assessments - and he is not in doldrums all the time as his tax assessment reaches finality - reduced hardship for tax-payers in dealing with old cases, potential decrease in tax-related stress and anxiety for individuals and businesses, potential for improved tax compliance due to reduced fear of long-term reopening of cases and, finally, ease of doing business, जो कि प्रधान मंत्री जी हमेशा चाहते हैं। जब तक हमारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस का एटमॉस्फियर नहीं होगा, तब तक यह नहीं होगा। Who are the key beneficiaries? The key beneficiaries are over 12 crore salaried employees and the micro and small businesses with moderate income.

महोदया, मैं फाइनली बताना चाहूंगा that now, there are increased monetary thresholds for tax appeals and the introduction of Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme. उससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है, जो फ्रीविलस लिटिगेशन था, जैसे कई छोटे एमाउंट्स का था, आप पहले 20 लाख रुपये के मामले पर टैक्स ट्रिब्यूनल में चले जाते थे, अब उसको 60 लाख रुपये कर दिया है। आप हाई कोर्ट में पहले एक करोड़ रुपये के मामले पर चले जाते थे, अब उसको दो करोड़ रुपये कर दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट में पहले दो करोड़ रुपये के मामले पर चले जाते थे, अब उसको 5 करोड़ रुपये कर दिया है।

इससे जो फ्रीविलस लिटिगेशंस हैं, उनको रोकने में मदद मिलेगी। दूसरे जो इम्पोर्टेंट केसेज हैं, उनको तय करने में उनको मदद मिलेगी। ?विवाद से विश्वास स्कीम?, 2024 है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन स्कीम है, अगर उनका इंटेस्ट और पेनल्टी वेवर हो जाता है, अगर वे एमाउंट पे करते हैं। प्रिवियस सिचुएशन क्या थी? प्रिवियस सिचुएशन थ्रेसहोल्ड की थी, वह खत्म हो गई। अभी जो केसेज आईटी ट्रिब्यूनल्स में हैं, वे लगभग 50 हजार हैं। इससे टैक्स रेवेन्यू रुका हुआ है। अब उसको मिलने में जल्दी होगी।



सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिम्पलीफिकेशन से क्या हुआ? अगर मैं एनडीए सरकार की बात करूँ, a record of over 8.18 crore इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किये गये, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में जबकि यूपीए के एरा में सिर्फ़ 3 करोड़ 36 लाख रिटर्न फाइल किये गये। दोनों में यह फर्क है।

मेरा लास्ट पॉइंट है। There is revision and simplification of long-term capital gains tax at 12.5 per cent for all asset classes. इस पर बहुत ऑब्जेक्शंस हुए। मैंने सुना कि राज्य सभा की स्पीच में भी ऑब्जेक्शन हुआ। यहाँ पर भी लांग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बातें कही गईं। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, for which there is no leg to stand, और एक गलत धारणा बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बहुत अच्छा किया। कई बार लोग कहते हैं कि एक यूनिफार्म टैक्स होना चाहिए। जब 20 परसेंट टैक्स था, 10 परसेंट टैक्स था, अगर हम उसको यूनिफॉर्म करते हैं, क्योंकि इससे इंडेक्सेशन टैक्स का बेस था। That was very, very complicated. That led to discrimination as well as arbitrariness in the hands of the authorities. दूसरा क्या किया गया? Reduction of long-term capital gains tax on immovable property 20 परसेंट से 12.5 परसेंट किया गया। पहले इम्यूवेबल प्रॉपर्टीज पर 20 परसेंट टैक्स था, उसको 12.5 परसेंट किया। इससे कैपिटल गेन कम हुआ, जो 10 परसेंट था, उसको 12.5 परसेंट किया गया।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बीच में टोका-टोकी नहीं कीजिए। आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : प्रिवियस सिचुएशन क्या थी? Previously, there were different long-term capital gains rates for different asset classes. मूवेबल प्रॉपर्टी में सारे की थी। It was having a confusion. Secondly, there is 20 per cent long-term capital gain on immovable properties. There are different slabs for movable properties. Coming to complicated indexation process leading to tax inaccuracies and litigation for common man, अब अगर हम इसका ग्लोबल कांटेक्ट देखें, as we have to learn so many things from other countries, आप देखें कि आपका टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ग्लोबली देखिए। आप एडवांस्ड कंट्रीज में देखिए, डेवलपड नेशंस में देखिए, अंडर डेवलपड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा पैसे चाहिए। अगर आप ग्लोबल कांटेक्ट में देखें, तो चाइना का टैक्स 20 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, यूएसए का 20 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, जर्मनी का 26.83 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, टर्की का 40 परसेंट है, हमारा 12.5 परसेंट है, फ्रांस का 30 परसेंट है, ब्राजील का 22.5 परसेंट, स्पेन का 28 परसेंट और इज़रायल का 25 परसेंट है। इस तरह से, सबसे कम टैक्स इंडिया में है, जो 12.5 परसेंट है। इसके लिए इन्होंने बहुत ही लम्बा-चौड़ा ऑब्जेक्शन किया।

इन्होंने कहा कि यूरोप-लाइक टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया है। ऐसा अपॉजिशन के हमारे कई नेताओं ने कहा। अगर यूरोप-लाइक स्ट्रक्चर होता, तो टर्की में 40 परसेंट था, हम 12.5 परसेंट नहीं रखते। यहाँ का भी 40 परसेंट जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि lower the tax, and more the gain to the Government. Those amounts to be utilised for the welfare schemes, for the poor, farmers, women, youth, and infrastructure of the country. आप रीजन देखिए। इसका बेसिक रीजन यह था कि simplify tax calculation process. इंडेक्सेशन का बहुत ही कांफ्लिकेटेड था, अलग-अलग जगहों पर डिफरेंट था। इससे किसी को फायदा होता, किसी को नुकसान होता। Next is, ?

promote longer holding periods for home buyers and middle-class and align taxation across asset classes?. अब अगर आप रीयल स्टेट मार्केट कांटेक्स्ट में देखें, तो Income Tax Department assumes 12-16 per cent compound annual growth rate on real estate returns over 15-20 years, which is common. Most major cities like Bengaluru, Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata, etc., show growth rates between 12 and 16 per cent over 15 years.

इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? There will be lower tax burden for long-term property investor and encouragement for holding properties for longer periods.

I am completing within 15 seconds. Now, there is stability in the real estate market due to longer holding period. अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे सबको समझ में आ जाएगा । ओल्ड रेट 20 परसेंट था, जो कि टैक्स-विद-इंडेक्सेशन था । अब न्यू रेट 12.5 परसेंट टैक्स है, जो कि विदाउट इंडेक्सेशन है । अगर दोनों में प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ 27 लाख रुपए है, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स कोस्ट 1 करोड़ 50 लाख रुपए बनता है और टैक्सेबल-गेन से 4 करोड़ 77 लाख रुपए बनता है । टैक्स-गेन कितना हुआ? अगर 20 परसेंट वाले से बताएं, तो 3 करोड़ 77 लाख रुपए पर हुआ । अगर हम टैक्स-एट 12.5 परसेंट गिनें, 20 परसेंट से गिने हैं, तो उसका करीब 75 लाख रुपए टैक्स बनेगा और 12.5 परसेंट से गिनें, तो 59 लाख रुपए टैक्स बनेगा । 12.5 परसेंट टैक्स होने की वजह से टैक्स-पेयर को नेट-सेविंग 15 लाख 80 हजार रुपए की सेविंग होगी । अगर वैल्यू 5 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी है और अगर 20 परसेंट टैक्स होता, जो कि ओरिजनल था, वह कम नहीं होता, तो उसमें टैक्स-पेयर के 15 लाख 80 हजार रुपए ज्यादा लगते । अब 12.5 परसेंट टैक्स होने से, टैक्स-पेयर के 15 लाख 80 हजार रुपए कम लगेंगे ।

With these words, मैं फाइनेंस बिल को सपोर्ट करता हूँ । मैं सभी मेंबर्स से निवेदन करता हूँ कि वे भी इसको सपोर्ट करें ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**SHRI K. E. PRAKASH (ERODE):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. Thank you for this opportunity for allowing me to speak on Finance Bill for the year 2024-25. I am a farmer's son and I could become the member of this august House. I thank Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Annan* Thiru M.K. Stalin, Hon Minister of Youth Welfare and Sports Affairs in Tamil Nadu and the Youth Wing Secretary of DMK, Thiru Udhayanidhi Stalin and the voters of Erode parliamentary constituency, which is the birthplace of *PakuthaRivu Pakalavan* Thanthai Periyar. I begin my maiden speech by bowing before Perarignar Anna, *Muthamizh Arignar* Dr Kalaignar and Thiru Murasoli Maran the conscience of Dr. Kalaignar. The Budget of 2024-25 of this minority Union Government is very much disappointing. This Budget, I should say, is completely against the interests of the people of Tamil Nadu. This Budget is presented to appease the coalition parties of the ruling BJP Government. This

Budget lacks farsighted vision and clarity. Hon Finance Minister usually cites a Tirukkural while presenting the Budget. But that is missing this time. Tamil Nadu is not even having a mention in this Budget. India is facing unemployment problem in an unprecedented manner never seen in the last 45 years. Prime Minister calls himself as the child of God. He has created the worst unemployment situation in the country which was unseen in the last 45 years. Hon Modi gave so many electoral promises before 10 years. Make in India, Amrit Kaal, depositing Rs 15 lakh in the bank accounts of every Indian citizen are some of those promises. But the data says that only the Swiss Bank accounts are flooded with money more than before. BJP Government has waived off several lakhs of Crores to the Corporate Companies. I have not seen this Government making any initiative to waive off the educational loans of students or farm loans availed by farmers. Many farmers have committed suicides last year. Hon Prime Minister announced in the year 2016 that the income of farmers would be doubled. The achievement of this Government is the deaths of farmers. Union Government has not fixed the remunerative price or the MSP for the agricultural produce. As usual the Union Government has not allocated money to Tamil Nadu under Sarva Shiksha Abhyan. Union Government is adamant and threatening with the condition that only when National Educational Policy is implemented, there will release of funds for the state of Tamil Nadu. GST has already snatched away the taxation rights of the State Government. GST paid by the people of Tamil Nadu is being utilized throughout the country. If we pay Rs. 100, only 29 Paise is given back to Tamil Nadu. The rest of the amount is being distributed with other states of the country. If you give all that money to us, we could provide a good governance in the State of Tamil Nadu. As mentioned by my brother Shri Arun Nehru, the Chennai Metro Rail Scheme has been kept pending for the last 3 years. Hon Union Home Minister came for the inaugural function. But till now you have not given any fund allocation to this Scheme. You have not even made any announcement regarding any new metro rail project for the State of Tamil Nadu. Under the able Government run by Hon Chief Minister of Tamil Nadu, besides financial crunches, after 3 years of rule, has provided Rs. 4000 to each of the 2 crore families as corona relief assistance. It was to the tune of Rs. 8000 crores. Every month the head of the family i.e. a woman is provided Rs.1000 per family as monthly financial assistance called the 'Women Rights grant' or the Makalir Urimaith Thogai. Free bus rides, has provided today approximately bus rides to 500 crore women of Tamil Nadu. This free bus ride for women is one of the pioneering programmes of the Government of Tamil Nadu. Morning Breakfast is being provided to approximately 20 lakh students and children during morning by the

hon. Chief Minister. *Naan Muthalvan Scheme, Tamizh Muthalvan Scheme, Kalaignarin Kanavau Illam*, are some of the Schemes which benefit every poor family of Tamil Nadu. Under the Kalaignar Dream House Scheme, houses at the cost of Rs. 3 lakhs are provided to each of the poor families of Tamil Nadu. Immediately after coming to power, he made the first announcement of building a Multi Super Speciality Hospital in Chennai of Tamil Nadu. At a cost of Rs. 250 crores this Super Speciality Hospital was set up within in one year. AIIMS is kept pending in Madurai for the last 10 years. For other States of the country, you completed the setting up of AIIMS was on priority basis done by you. Only a brick was there in Madurai, Tamil Nadu. Other than this, no action has been taken by the Union Government. Hon Chief Minister of Tamil Nadu has done the best to attract the industrial investments to the tune of Rs. 7 lakh crore. Even at times of financial distress faced by the State Government, Tamil Nadu government is excelling in all fields. When Tamil Nadu was affected by floods, you the BJP Government has not done any help to the people of Tamil Nadu whereas our Chief Minister of Tamil Nadu Annan Thiru M.K. Stalin has provided Rs. 6000 each to the affected families of Chennai, Thoothukkudi, and other areas of Tamil Nadu. Similarly, during the regime of *Muthamizh Arignar Dr, Kalaignar*, the free electricity Scheme announced for the farmers was implemented besides financial crisis and this Scheme has been implemented for the farmers till today for the last 35 years. Even this year hon. Chief Minister of Tamil Nadu has provided free electricity to 2 lakh farmers even between the financial crunches faced by the State of Tamil Nadu. Similarly, the Union Government has reduced the allocation for farmers to 2.75 per cent from 5 per cent. Union Government is aimed at blocking the development of agriculture and farming. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu is heading a democratic government for the welfare of the voters who voted him to power and those who did not vote for him. But you are running a Government which is anti-people. When Tamil Nadu asked for Rs. 37,000 crores as disaster relief fund, you have released an amount which is just Rs. 500 Crore. You did not provide Rs. 37,000 crores which was the demand for disaster relief. Without consulting the States, the announcement for reducing Stamp Paper duty was made by you which hampered the rights of the States. You have snatched away the rights of States. You have not provided Rs. 20,000 Crore as GST compensation. But who gave the Union Government the right to restructure the tax system? You said that the last 10 years of your rule was just a trailer and the main film is yet to come

**HON. CHAIRPERSON:** Please wait for a minute. The House is extended for an hour with the consent of the members.

**SHRI K.E. PRAKASH :** The people of Tamil Nadu have not given victory in a single seat to BJP. BJP faced defeat in almost all 40 constituencies of Tamil Nadu and Puducherry. Do not ever imagine to destroy the opponents. There is a proverb in Tamil which says we should not live in a place where there is no enemy. But when you want to grow you need enemies. For a nation to prosper, you should fully recognise the opposition parties. This is the old proverb of ancestors of Tamil Nadu. Erode is my parliamentary constituency. There is no new Scheme that was announced for Erode in this Budget. I condemn and express concern on behalf of the people of my Erode constituency for not announcing anything for Erode in this Budget. ?This country is ours and all 40 seats are ours? is the motto claimed by our Hon Chief Minister of Tamil Nadu who is spearheading the Dravidian Model of Governance in Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu gave a historic mandate in Tamil Nadu giving all 40 seats to the Dravidian Model of Governance. But the Union Government has not treated all the States as equal. Everything is for everyone is the motto of our Dravidian Model Government and it is treating all the people as equals.

Finally, I want to say one this. This Budget 2024 may protect your Government in power. But it will not protect the country. Let the Government to function on its own way. Do not act in such a vengeance attitude against those States which defeated you in the just concluded elections. This was the warning given by hon. Chief Minister of Tamil Nadu. I wish to remind his words and conclude my speech. The Second freedom struggle against you by the INDIA Alliance has just begun. Tamil Nadu is celebrating a single brick which is raised against you. But you are holding the *Sengol*, the sceptre and ruling in anarchical way. Thank you.

**18.00 hrs**

(Shri P.C. Mohan *in the Chair*)

**SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA):** Sir, thank you for this opportunity. While our country is soon becoming the third largest economy, we, the representatives of the House of the People, should observe that 77 per cent of the total national wealth is with 10 per cent population, and only 23 per cent of the wealth is with the remaining 90 per cent population. The issue of inequality between the rich and the poor has to be addressed. Necessary steps have to be taken to ensure that poor

people grow wealthier in our country, and only then becoming the third largest economy soon will have some meaning and sanctity.

Coming to income tax, the share of individual income tax payer in GDP has increased from 2.5 per cent in 2017-18 to 3.64 per cent in 2024-25. A comparison with the other BRICS economies shows that effective personal income tax rate in India is among the highest. Section 80D of the Income Tax Act allows tax deductions of up to Rs. 25,000 every financial year on health insurance premiums. This deduction limit has remained the same for the last 10 years. While on the other side, the medical expenses of every individual are growing in a very big way for the last 10 years. So, to address this issue, necessary steps have to be taken to enhance this deduction limit up to Rs. 1,00,000 per financial year on health insurance premiums keeping in view the increased medical expenditure.

The new tax regime curtails several important tax deductions leaving people disincentivised for switching from the old regime. Deductions under Sections 80C, 80D and 80E and various other deductions are not permitted under the new tax regime leaving the middle-class people and the poor people dissatisfied and in financial stress and strain.

Coming to indirect taxes and GST, indirect tax collections are increasing year by year. The Government has been seeing required GST collections with a significant increase in July, 2024 totalling an amount of Rs.1,82,075 crore marking a 10.3 per cent rise compared to July 2023 which was Rs.1,65,000 crores. Given these high collections, now the Government should come forward and consider reducing or exempting GST rates on certain basic goods and services which are commonly consumed by the poor and the middle class. On behalf of the weavers, I request the Government to exempt five per cent GST on the raw material used by the weavers. The fishermen are making a request for a long time for GST exemption on components used for making fishing nets including nylon towing ropes and floats.

As you very well know, the farming community is in severe distress. We have to address the issues of the farming community. A new Act has to be introduced in this House fixing MSP for all the crops produced by the farmers in this country. More importantly, to promote farm mechanisation and to support farmers, GST should be exempted for all farm supplements.

More importantly, 18 per cent GST is collected on health insurance premium and life insurance premium. We strongly request the Government to withdraw GST on life insurance premium and health insurance premium.

Coming to our State, Andhra Pradesh, our former Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu requested the hon. Prime Minister several times to grant special category status to Andhra Pradesh as was promised in this House by the then Prime Minister Shri Manmohan Singh ji. We strongly urge upon the Government to grant special category status to Andhra Pradesh and fulfil the promise made in this House. In the AP Reorganisation Act, establishment of a steel plant at Kadapa was promised to us. We strongly urge upon the Government to establish the steel plant at Kadapa. In the same AP Reorganisation Act, a railway zone at Visakhapatnam was assured to us. We urge upon the Government to implement its promise.

More importantly, we request the Government to withdraw its plan to privatise Vizag Steel Plant.

Once again, thank you for giving me this opportunity.

**SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL):** My salutations to this august House including the hon. Chairperson. I wish to say my views on the Finance Bill on behalf of the Communist Party of India (Marxist). The fund mobilization programme of this Government is not in the interest of the people or the nation at large. This seems to be in the interest of the corporates. During the 1950s and 1960s, the corporate tax occupied the predominant place in the tax collection followed by income-tax and then by indirect taxes. Later, the indirect taxes, which were in third place, climbed up the ladder to occupy the first place. During the last 10 years of Shri Narendra Modi-led Government, the corporate tax collection declined and went to the third position and the credit for this goes to the hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman. As regards GST, 10 percent of the rich persons pays a GST of three per cent whereas 50 per cent of the poor pays a GST of 66 per cent. I wish to bring to your notice that the poor and the common people constitute most of the taxpayer base of the GST in India. Concessions were given for those who join the new tax regime. It means the old tax regime will be gradually closed. Giving up the old tax regime means giving up the savings and the encouragement extended to save. Just this encouragement helped to have more domestic savings in the country. This helped in boosting the domestic industrial growth. As much as Rs.11 lakh crore has been provided for the industrial growth. But the old tax regime,

which encouraged savings in the country, is not given any new concessions. This will hamper our domestic savings as well as the industrial growth. Not only have the MPs urged upon you to give up the GST on Life Insurance and Medical Insurance policies, but also the senior-most Minister in your Cabinet Shri Nitin Gadkari has also written a letter in this regard. You have not taken into consideration the views of the people of this country. You have not accepted the views of 235 MPs in this House. But you have not even accepted the viewpoint of a senior Minister of your own party. For whom are you running this Government? There is a demand throughout the world for imposing wealth tax. In the G20 nations too, there is a consensus on taxing the super-rich. In France the inheritance tax is 60 per cent. In Japan it is 55 per cent. In Germany, the inheritance tax is 50 per cent. In Britain it is 40 per cent. I wish to say that in India not even one per cent inheritance tax is levied and the Government is not intended to levy this inheritance tax. You have reduced the corporate tax from 40 per cent to 35 per cent. You have disclosed who your boss is. I urge that the corporate tax should be increased. The ways and means to levy inheritance tax should also be considered. You should ponder over taxing the super-rich. You should give concessions to those in the old tax regime and encourage domestic savings in the country. The GST on Life Insurance and Health Insurance policies should be withdrawn.

I will just explain a story and conclude my speech. A farmer who was in distress wanted to meet his family astrologer. After seeing his horoscope, that astrologer came to know that the farmer will die at 8 pm on the same day. But without saying this to the farmer, the astrologer wanted him to meet the next day. While returning, there was heavy rain and cyclone, the farmer had to enter a temple of Lord Shiva to save himself from nature's fury. Since he was inside the temple, he did not die. He was saved by God. Like the heavy rains and cyclones, the Telugu Desam Party and the Janata Dal United have brought this Government to this temple of democracy, the Parliament. This is temporary. Your days are numbered. If your policies are not changed for doing all good to poor, if this BJP Government continues to take a stand favouring the corporates, the people of this country will not forgive you. I wish to register here that your regime will come to an end very soon. As regards this Finance Bill, there is no fund mobilisation policy or announcements for the poor. Therefore, all the Opposition Parties in this House have urged that there should be announcements benefitting the poor. But this Government is not paying attention to such demands. Many MPs said here that if Prime Minister Modi does not return to power, there is no one to save our country. I must say only the corporates were saved during the last 10 years of Modi



Government. I urge upon this Union Government that this Budget should be aimed at protecting the welfare of the poor people of our country. This is a Budget which is anti-labourers, anti-poor and anti-people. The objective of this Budget should be changed. The tax system should be changed. Poor-centric programmes should be implemented. In States like Tamil Nadu, several schemes are implemented for the welfare of the poor people. Many schemes, including the Morning Breakfast Scheme, are being implemented in Tamil Nadu. I urge that the Union Government should also implement similar programmes throughout the country taking cue from Tamil Nadu. There should be adequate importance given to education. This Government should try to bring several programmes for the welfare of poor people in the country. Our general insurance ? (*Interruptions*)

Three companies are looking after the general insurance in the country. I urge that these three companies should be merged as one. GST exemption should be given for Life Insurance and Health Insurance Policies. I want you to rethink and reconsider withdrawing the taxation of the base and raw material for agriculture and farm products. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

श्री तनुज पुनिया (बाराबंकी) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया और वह भी इस अहम फाइनेंस बिल, 2024 पर बोलने का मौका दिया। यह बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं देवा-महादेवा की पावन धरती बाराबंकी से आता हूँ। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के वोटर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया है।

महोदय, उत्तर प्रदेश को हम लोग राम जन्मभूमि के नाम से बुलाया करते हैं। लेकिन, हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह भगवान श्रीकृष्ण की भी जन्मभूमि है। भगवान श्रीकृष्ण गायों के बीच में खेला करते थे। वह मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे। आज इस युग में अगर वह दोबारा प्रकट हो जाएं तो शायद मक्खन न खा पाएं, क्योंकि मक्खन पर 12 परसेंट का टैक्स इस सरकार ने लगाने का काम किया है। दूध के जितने भी आइटम्स हैं, उनके ऊपर 5 परसेंट से लेकर 12 परसेंट तक का टैक्स लगाया गया है। आम आदमी अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहता है, पनीर खिलाना चाहता है, वह अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है, वह बहुत ही निंदनीय है। आप नई टैक्स रिजीम लेकर आए हैं। साथ-साथ पुरानी टैक्स रिजीम भी चल रही है। इसमें बड़ा कंप्यूजन है कि पुरानी में जाएं या नई में जाएं। उसमें अलग कंप्यूजन है कि आप एक बार बदल लीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए। उसके बाद दोबारा आप उसमें चले जाइए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रोक लगी है, नहीं रोक लगी है, यह बड़ा कंप्यूजन सा है। अगर आपको टैक्स रिजीम रखनी ही है तो कंप्यूजन हटाकर एक ही रखें।

महोदय, यह जो नई टैक्स रिजीम है, इसमें जो सेविंग्स हैं, उसको आपने इंसेंटीवाइज करने का काम नहीं किया है। उसको बिल्कुल आम आदमी के भरोसे छोड़ दिया है कि आपको जो सेव करना है, वह आपकी जिम्मेदारी है। वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पुरानी टैक्स रिजीम में इनके इंसेंटीव्स दिए जाते थे। देश में बचत दर बढ़ रही थी, बचत हो रही थी, लेकिन क्या सरकार ने सोचा है कि जो आम आदमी है, मिडल क्लास है, वह बचत करना कम कर देगा तो उससे हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, अगर मैं डोमेस्टिक

सेविंग्स की बात करूं तो हमारे प्राइवेट लोगों की भी और सरकार की भी जो वित्तीय आवश्यकता है, उन सबको यह पूरा करता है। सरकार का जो ऋण है, वह 95 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय मुद्रा में है। अगर यह सेविंग्स कम होती चली गई तो फिर इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है?

महोदय, इस बार जो टैक्स स्लैब दिया गया है, उसमें बहुत ही मामूली राहत मिडल क्लास को दी गई है। मिडल क्लास यह सोच कर बैठा था कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी। बहुत सालों से उसकी आस थी, लेकिन हर बार उसको झुनझुना पकड़ाने का काम सरकार ने किया है। इस बार तो खास तौर से उन्होंने जो मामूली बदलाव किया है, उससे कोई ज्यादा फायदा मिडल क्लास तक नहीं पहुंचा है। इसके साथ-साथ हमारे जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो शायद टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं आते हैं, पिछले छह सालों में उनकी आमदनी जो प्लैट हो चुकी है, उसमें कोई बढ़ावा नहीं हुआ है। उसके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात ही नहीं की है। उनकी आमदनी को बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई है। क्या हमारे देश का मजदूर इसी तरह से मायूस होता रहेगा? हमारे देश में कई सालों से, खासतौर से वर्ष 2018 या 2019 से कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में भारी छूट दी गई। वह 30 परसेंट था, 25 परसेंट हो गया, कुछ सेक्टरों में 22 परसेंट हो गया। उनका कर्जा भी माफ किया गया। लेकिन हमारे किसानों, मिडल क्लास और मजदूरों से ऐसी कौन सी गलती हो गई, जो उनके बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया? बहुत ही मामूली सी राहत देते हैं, वह एक तरह से झुनझुना पकड़ाने का ही काम है। इंडेक्सेशन के बारे में कई बातें हुईं। हमारे जो आम आदमी हैं, खासतौर से जो किसान वर्ग है, वह एक प्रॉपटी लेता है। वह सोचता है कि आगे अगर कोई वित्तीय संकट हमारे ऊपर आया तो हम इसको बेच करके उससे बाहर निकलेंगे।

अगर हमारे घर में बेटे-बेटी की शादी हुई, तो पैसा कहां से आएगा? इसके लिए वह प्रॉपर्टी रखता है। इंडेक्सेशन को हटाकर एक बहुत बड़ा प्रहार हमारे किसानों और मिडल क्लास के ऊपर किया गया है।? (व्यवधान) अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ा फासला आज के समय हो गया है। जो गरीब है, वह गरीब होता चला रहा है और जो अमीर है, वह अमीर होता चला जा रहा है। पूरे देश की जो सम्पत्ति है, पूरे देश का जो पैसा है, वह चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। अमीरों को, बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स को, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीतियां बन रही हैं। उनके टैक्स को बार-बार कम किया जा रहा है। गौर फरमाने की यह बात है कि किसान से किस तरह की वसूली आज हो रही है। किसान की खेती-बाड़ी के जो उपकरण हैं, ट्रैक्टर और उसके पुर्जे हैं, फर्टिलाइजर है, इन सबके ऊपर भारी जीएसटी लगा हुआ है, भारी टैक्स लगा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। वसूली कर रहे हैं, लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं।

मैं खाद के ऊपर अगर बात करूं तो केवल 5 परसेंट जीएसटी है। लेकिन, उसके रॉ मैटेरियल्स की तरफ किसी ने देखा, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे रॉ मैटेरियल्स के ऊपर 18 परसेंट तक का जीएसटी लगा है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने यह रिकमेंड किया कि इससे जीएसटी हटना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में भी प्रपोजल गया कि यह टैक्स हटना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बार भी हमारे किसानों को मायूस होना पड़ेगा। किसान की आय क्या ऐसे दो गुनी होगी? आप बार-बार किसान की आय दो गुनी करने की बात करते हैं। अगर किसान की आय दो गुनी हो भी गई तो खर्च चार गुने बढ़ जायेंगे।

चूंकि किसानों की बात हो रही है तो मैं बाराबंकी की बात कर लूं। बाराबंकी में एक फसल मेंथा होती है। यह फसल बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है। इससे पिपरमेंट का तेल, मेंथा का तेल निकलता है। वह तेल टूथपेस्ट्स में, चॉकलेट्स में, दवाइयों में, फार्मास्युटिकल्स में हर जगह इस्तेमाल होता है। हमारा जो किसान मर्द,

जून, जुलाई की कड़कती गर्मी में इस फसल को पैदा करता है, उसकी फसल पर 12 पर्सेंट जीएसटी लगाते हैं। टैक्स लगाने से हमारे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सिंथेटिक मेंथा, जो विदेश से आता है, खास तौर से चीन से आता है, उस पर भी 12 पर्सेंट जीएसटी है और हमारे किसानों के ऊपर भी 12 पर्सेंट जीएसटी है। इसके बारे में कई बार बहुत सारे माध्यमों से अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो बुनकर भाई हैं, उनके सूत के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, उनके धागे के ऊपर टैक्स लगा हुआ है और हैंडलूम के ऊपर पहली बार इस सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज हकीकत यह है कि चाइना से पुर्जे उठाकर यहाँ लाये जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर उनको जोड़कर, असेंबल करके, उनके ऊपर मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बेचा जा रहा है। हमारे देश में आज मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर असेंबलिंग हो रही है। हमारे देश में जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो छोटे उद्योग का काम करना चाहते हैं, उन सबका क्या होगा? क्या वे सिर्फ असेंबल करते रह जाएंगे? ई-कॉमर्स के बारे में मैंने अभी आपके विधेयक में देखा, जो इक्वेलाइजेशन लेवी जो 2 परसेंट की लगी थी, वह हटा दी गई है। यानी कि जो नॉन रेजीडेंट यहाँ पर हमारे ई-कॉमर्स की कंपनी खोलना चाहते हैं, उनके ऊपर अब लेवी नहीं लगेगी। हमारे डोमेस्टिक जो ई-कॉमर्स करने वाले हैं, उनको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं।

एक्साइज ड्यूटी की बात करूँ तो पेट्रोल, डीजल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मुख्य रूप से मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस बार जो यह बिल आया है, उसमें पुराने वर्षों से कोई ऐसी नई बात नहीं दिखी। आम आदमी के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है। केवल बड़े-बड़े जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं, उन्हीं को फायदा पहुँचाने के लिए यह फाइनेंस बिल आया है। हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को, हमारे किसानों को बहुत सारी उम्मीदें थीं। उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, इसलिए निराशा भी बहुत बड़ी है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिन्द।

**DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM):** Vanakkam. Thank you for allowing me to speak on this Budget. This Finance Bill specifies how the funds will be distributed among the States of the country. The Finance Commission decided on the devolution of funds to each of the States. It was decided at the 13<sup>th</sup> Finance Commission that 32 per cent will be the devolution of funds to the State. The same was 42 per cent during the 14<sup>th</sup> Finance Commission. But out of which only 41.5 per cent was provided. Now in the 15<sup>th</sup> Finance Commission it was decided to give 41 per cent to the States of the country. Till now only 40.1 per cent has been distributed among the States. Through this, an amount of Rs.1,20,000 crores, which were to be distributed among the States by the Union, is left out. During the period of the 16<sup>th</sup> Finance Commission, I urge that the left-out amount should be included in the devolution of funds to the States. Then, while calculating the amount of funds to be distributed to the States, the Cess and Surcharge are not included. As per the decision taken during the year 2000, this practice is in place since last 20 years or more. Now this volume has grown up. During 2014-15, when the BJP came to power for the first time in the country, the collection of this Cess and Surcharge

started increasing year after year. During 2014-15 through cess and surcharge, an additional tax to the tune of Rs.1,19,000 crores was collected. During 2023-24, in the last Budget, under the Revised Estimates, Cess and Surcharge collected stood at Rs. 5,10,000 crores. Out of the total tax receipt, this collection of cess and surcharge has risen up to 14.8 per cent. This is a tactic used to dechannelize the funds that are otherwise to be distributed to the States. These Cess and Surcharge are collected in the name of education, health as well as GST compensation. But the tax for which it was collected is not utilized for that purpose. The cess or surcharge collected for education or health is spent on some other fields. Therefore, in the days to come, while deciding the amount to be distributed to the States by the 16<sup>th</sup> Finance Commission, I request that the Union Government should take a call in giving the share to the States on the cess and surcharge collected by the Union Government. Only when the devolution of funds is done in a proper manner, the States can be ruled by the respective Governments with better fiscal prudence. In the case of Mineral Authority of India Vs Others, the hon. Supreme Court on 25<sup>th</sup> July 2024 has given an important verdict. This verdict explains in detail about the fiscal federalism. The Union Government should take this into consideration. Only by protecting the fiscal federalism, you can protect the unity of our country; you can protect the integrity of our country. You have to learn lessons from the neighbouring country. If the people in the States are deprived of so many things, and if their voices rise up, it will be dangerous to the integrity of India. Therefore, you should properly uphold fiscal federalism. There is an important issue which I expected from this Budget as it was mentioned in the Interim Budget presented by this Government before the elections. Our Indian women die in large numbers due to cervical cancer; probably their death rate is higher when compared to other nations of the world. This is not a pride for India. We are losing at least 1 lakh women due to cervical cancer every year in our country. I raised a question in this regard during the 17<sup>th</sup> Lok Sabha and got a reply from the Government. Every year this number is on the rise. Earlier there was no vaccine for this. But now HPV Vaccine is found to be effective. The Serum Institute of India headed by Poonawalla has launched HPV Vaccine in India for controlling the cervical cancer. They were the one who manufactured vaccines during the COVID-19 pandemic. This vaccine at a lower cost can be included in the Universal Immunization Programme. I have stressed about this even during the 17<sup>th</sup> Lok Sabha. During the Interim Budget presented by the previous Government before the elections, there was a mention about the consideration of my demand. I was expecting an announcement about this in the current Budget. But no such announcement was made. The HPV Vaccine

meant for preventing cervical cancer should be included without fail in the Universal Immunization Programme because one lakh women are dying every year due to this type of cervical cancer. I urge that the Union Government should come forward to prevent such deaths. This is a demand pertaining to my constituency. The hon. Finance Minister is very well aware of Viluppuram Constituency as she had her primary education in Villuppuram. That is why, the hon. Finance Minister is very much affectionate about Viluppuram. When I became an MP in 2019 for the first time, I placed a demand before her. The labourers, who are engaged in jewellery making, are in large numbers in my Viluppuram Parliamentary Constituency. Viluppuram stands at number two as far as jewellery making in Tamil Nadu is concerned. I demanded for setting up of a Jewellery Park in Viluppuram. The hon. Finance Minister had assured to look into this demand. Now five years have passed. Through you, I request the hon. Finance Minister to kindly consider setting up of a Jewellery Park at least this time in Viluppuarm. Thank you. Vanakkam.

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । सरकार हमसे खजाने की चाबी मांग रही है कि खर्च करने के लिए खजाने का पैसा दिया जाए । क्या इसलिए खजाने की चाबी दी जाए ताकि आम जनों के हित में, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनमें भारी कटौती करके दोनों हाथों से अपने कॉरपोरेट मित्रों पर धन की वर्षा कर सकें । इसके लिए तो चाबी नहीं दी जाएगी ।

इस देश में करोड़ों दलित, आदिवासी, भूमिहीन, जमीन के अभाव में समुद्र, नहर, सड़क, पोखर के किनारे झोंपड़ी बनाकर, पोलीथीन तानकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम रॉकेट की गति से विकास कर रहे हैं । जिन लोगों का इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारी योगदान है, वे खेतों में काम करके अनाज पैदा करते हैं और देश का पेट भरते हैं । वे बड़े-बड़े कल-कारखानों की चिमनियों से धुंआं निकालकर उत्पादन में सहयोग देते हैं । वे मेहनत करके सुंदर सड़कें बनाते हैं और ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं । वे पूरे देश को अपने श्रम से स्वर्ण बना रहे हैं, लेकिन उनको रहने के लिए नर्क में जगह मिली है । उस नर्क में भी उनको शांति से रहने का अधिकार नहीं है । विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर हमेशा उनकी झोंपड़ियों पर बुल्डोजर चलाया जाता है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देश में भूमि सुधार कानून लागू करे ।

बिहार में वर्ष 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था । जिस आयोग ने कहा कि 21 लाख 85 हजार एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल जमीन है, सरकारी जमीन है, जिस जमीन पर भू-माफियाओं का रायफल-बंदूक के बल पर कब्जा है । इस जमीन को भूमिहीनों में बांटना चाहिए । आयोग की यह भी सिफारिश थी कि बटाईदारी पर ज्यादा खेती हो रही है, इसलिए इसी बजट का लाभ दिलाने के लिए बटाईदार किसानों को पहचान-पत्र दिया जाए । यह केवल बिहार की बात है, पूरे देश में करोड़ों एकड़ ऐसी सरकारी जमीन और सीलिंग जमीनें होंगी । मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि देश में भूमि सुधार लागू किया जाए और भूमिहीनों को खेती लायक जमीन दी जाए ।

महोदय, दूसरी बात, 11 करोड़ निवेशकों के ढाई लाख करोड़ रुपये सहारा इंडिया में जमा है। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई। यह गरीबों का पैसा है, देश के मध्यम वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपनी बहन-बेटियों की शादी के लिए, बाल-बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने संकट के दिनों के लिए वह पैसा जमा किया था। ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। यह दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी-डोहनी करने वाली महिलाएं हैं, शहरों में जो झाड़ू पोंछा का काम करती हैं, रिक्शा, टैम्पो, ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वे सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वे गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, जो सहारा इंडिया का है और जिसके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि यह पैसा एजेंटों के मार्फत निवेशकों को दिलवाया जाए। उनके पेट पर लात पड़ रही है। उनकी रूह कुढ़ती है, जब वे हमसे कहते हैं। तीसरी बात, हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतनी पैदा होती है, तो यह कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो एक हफ्ते में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने की वजह से कितने गरीबों की मौत हो गई। जबरदस्ती गांव की लाइन काटने का दबाव डालकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अभी बराखरौनी, शाहपुर में एक गांव है, वहां यह प्रयोग चला। स्मार्ट मीटर लोगों का खून चूस रहा है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जनता पर दबाव न दिया जाए। भारी बिजली का बिल आ रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा महंगी दर पर बिजली मिल रही है। इस पर रोक लगाई जाए और हमारे यहां लोग कह रहे हैं कि पावर मिनिस्टर क्या हारे, जिले की पावर चली गई। इस पर रोक लगाई जाए।

महोदय, अंत में कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। यह ठेका प्रथा खत्म की जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी ठेके पर चलने लगेगी। अगर ठेका प्रथा पर रोक नहीं लगाई गई, तो सरकार भी ठेके पर चलेगी, इसलिए इस पर रोक लगाएं। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जितने स्कीम वर्कर्स हैं, उनको सरकार स्थायी करे, उनका वेतनमान तय करे और जो चार श्रम कोड मजदूरों के खिलाफ लाए गए हैं, उनको सरकार रद्द करे। आरा में आधुनिक सुविधाओं से हेली एम्बुलेंस सहित एक ट्रामा सेंटर का इंतजाम किया जाए और माननीय प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि डालमिया नगर में जो कारखाना बंद हो गया है, वहां रेल फैक्ट्री लगाई जाएगी। उसे लगाया जाए। इंदुपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण और नहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। नवीनगर की इकाइयों के सीआरएस फंड को स्थानीय विकास में इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद।

**SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM):** Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on the Finance Bill of 2024-25. The BJP is not following justice while doing the allocation of funds. There is partiality being shown in the allocation of funds. There is partiality in announcing Special Schemes. There is partiality in passing legislations. There is partiality as regards languages, religion and race. This BJP is a Government full of partiality. It was seen during the last 10 years as a Government engaged in partisan approach. It is being continued now with no difference in their behaviour. It was never a Government for all. India is the biggest democracy of the world and the Parliament, which is the lifeline of our country, has a historical importance on its own. World famous leaders, administrators have

been our Prime Ministers, Union Ministers, and MPs in the past and this is the House where they participated in the constructive discussions. The hon. Prime Minister and other Ministers used to hear what others speak in this august House. But we see nowadays not even the MPs of the ruling party were aware of when the hon. Prime Minister will come to Parliament. Only one solace to this matter is that as the people of this country have given a specific mandate for a strong presence of opposition parties, the hon. Prime Minister comes to this House for at least replying to the views of the hon. Leader of the Opposition. The BJP Government is just providing answers to the issues or questions raised by the hon. Members of Parliament in this House. We do not only expect replies. We want concrete actions. I want to know for how many demands raised in this august House, the BJP Government has taken actions. Whether any one of the demands raised by the Opposition was accepted by the BJP Government? The BJP Government should try to differentiate between governance and politics separately. The BJP should stop using this Union Government for its political mileage. Rameswaram is in my Ramanathapuram Parliamentary Constituency where we have the world-famous temple. Lakhs and lakhs of pilgrims visit this place every year. Our Prime Minister, Union Ministers and other dignitaries come to this place more often. This place should be upgraded as a tourist destination. I have placed this demand several times for consideration by the Government during the last five

years. In the Budget presented by our hon. Finance Minister, it was informed that importance will be given to upgrade the tourist centres in our country. They have allocated special funds for upgrading the holy places of Bihar in this Budget. They call this as development of tourism. You are able to see the holy places of Bihar. Rameswaram is a place of tourist importance which you often use for political reasons. Are you not able to see Rameswaram? The Prime Minister and the Ministers frequently visit Rameswaram. But they are not concerned about the development of this place as it is not visible to them. You give importance to our Rameswaram only for political and election gains and nothing else. What is the action taken by you for the development of Ramanathapuram District? So many districts of the country have been identified as aspirational districts. It means these are the districts which are mainly to be taken up for development. Ramanathapuram District in my Ramanathapuram Parliamentary Constituency and Virudhunagar District are in the list of backward districts of the country. But these districts remain identified for name's sake. No special fund or assistance was provided for developing these backward districts. I want to ask this Government how they will develop these backward districts without allocating any money. I

have time and again demanded that a fertiliser factory, palm tree and coconut tree related industries, industries relating to sea products have to set up in this area for providing employment. But nothing has been done by this Government. It has not fulfilled anything. I also placed my demands with the Ministers of Departments concerned. But it was in vain, nothing could take place. They should not only give replies but they should act accordingly. The Union Government should distribute 41 per cent of its tax revenue to the States as per the 15<sup>th</sup> Finance Commission. But the Union Government distributes only 32 per cent to the States. Tamil Nadu remains a State which is earning more revenue to the Union Government. For every rupee given by Tamil Nadu, the Union Government gives back only 29 paise. But Uttar Pradesh Government, if it pays Rs 1, gets back Rs. 2 and 23 paise. Bihar gets Rs.7 and 6 paise as against every one rupee given to this Union Government by the State. This is what is called as biased devolution of funds. There are demands for increasing the limit set for spending under the Rural and Urban Housing Schemes. This was not considered in this Budget. The contribution by the State Government is more in the PM Housing Scheme. Without allocating funds under this Scheme, the number of houses to be built under the scheme is increased by the Union Government. The State Government has to bear an additional burden due to this. For a scheme where the State Government allocates more funds, but is it apt that the Scheme is named after the Prime Minister? In the Budget the capital gain tax on shares has been increased. If one sells the finance and non-finance related assets, and if he gets the profit, then that is called the capital gain tax. In the 2024-25 Budget, short-term capital gain tax for the shares has been raised from 15 per cent to 20 per cent. The long-term capital gain tax has been increased from 10 per cent to 12.5 per cent. This will definitely affect the middle-class people very much. Therefore, the Union Government should take back this announcement. Similarly, the long-term capital gain tax on properties was reduced from 20 per cent to 12.5 per cent. If such properties like plots and houses, including loan bonds, are purchased during 2001-02 or after, the scheme of indexation is removed. If you now try to sell a property purchased by you long back, the procurement price of the investment is corrected as reflective of inflation, accordingly.

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude your speech.

**SHRI NAVASKANI K.:** Ok Sir. I want to raise another important issue in this august House. Our Tamil fishermen are attacked by the Sri Lankan Navy time and again. I have demanded here that this issue needed immediate intervention and



permanent long-lasting solution. We have placed this demand long ago. But without finding a permanent solution, our fishermen are arrested frequently by the Sri Lankan Navy; their fishing boats are confiscated; resulting in loss to lives and property to fishermen. Near the Delft Island (Neduntheevu) on 1<sup>st</sup> August 2024 four fishermen of Ramanathapuram, who went on sea for fishing, were attacked by the Sri Lankan Navy's patrolling party. The motor boat got capsized and a fisherman named Ramasamy died. The dead body of another fisherman is being searched as he seems to be missing. Two other fishermen were arrested and released later. Our Tamil fishermen lose their lives due to such attacks. Is it not visible to this Union Government? On 3<sup>rd</sup> August 2024, four fishermen belonging to Jegathappattinam were arrested along with a motor boat in the Ramanathapuram Parliamentary Constituency. In the Ramanathapuram Constituency, as many as 25 fishermen of Pamban area were arrested by the Sri Lankan Navy with their four country boats on 1<sup>st</sup> July 2024. Out of which, only 14 persons were released so far. Nine fishermen and two boats are to be released. On the evening of 22<sup>nd</sup> July 2024, Sri Lanka has taken into their custody another nine Indian fishermen along with three motorised boats. I have raised this issue several times in this august House. No action has been taken by the Union Government. Talks between the fishermen of the two countries should take place immediately. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has provided a compensation of Rs.10 lakhs from the Chief Minister's Relief Fund to each of the fishermen who were arrested earlier by the Sri Lankan Navy and later died. The hon. Chief Minister *Annan* Thiru M.K. Stalin has also provided Rs. 6 lakhs each to the confiscated and unrecoverable boats and Rs.2 lakhs for the unrecoverable country boats. But the Union Government has not given a single rupee to the affected fishermen and their families. It should, therefore, give compensation fund to the victims. This Government is against the welfare of minorities and passing legislation against the minorities. In all the BJP-ruled States, there is a situation prevailing that the minorities are not safe. The State Government of Uttar Pradesh has issued an order for closure of the unapproved *Madarsas*.

**18.49 hrs**

(Hon. Speaker *in the Chair*)

-

It has also stated that those who studied in *Madarsas* cannot continue pursuing their general education in other schools. This Union Government and the

Governments in the BJP-ruled States are deceiving the minorities in a continuous manner. Our External Affairs Minister while making a Statement on Bangladesh today in Lok Sabha said that the safety and security of the minorities living in Bangladesh will be protected. This Government is so much concerned about the safety and security of minorities living in a neighbouring country. Similarly, this Government should also ensure the safety and security of minorities living in the country by allowing them to protect their rights. Thank you.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (जयपुर ग्रामीण) : महोदय, इस संसार के सार में मनुष्य का जो स्वरूप है, उसको अभिव्यक्त करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी का यह शिरोधार्य मंच है। मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को सूक्ष्म की सार्थक परिणाम तक सीमित रखता हुआ अपने विवेचन को आर्थिक व्यवस्था की उस स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो ये सूक्ष्म क्षण आपने मुझे प्रदान किए हैं।

आदरणीय, मैं आपका ध्यान उस वक्तव्य की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जिस वक्त हम 8 वीं कक्षा के छात्र थे और अर्थशास्त्र की प्रारम्भिक परिभाषा पढ़ रहे थे। किसी गुरु ने हमें यह बताया था कि जिस मुद्रा को आप लोग आदान-प्रदान के रूप में प्राप्त करते हैं, उसकी सूक्ष्म परिभाषा यह है कि : ?money is a matter of four functions - a medium, a measure, a standard and a store?. आज सुबह से अभी तक जितने भी वक्तव्य आए हैं, वे इन्हीं चार के दायरे में सीमित हैं। मैं आपका ध्यान उस व्यवस्था की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके इस आसन के ठीक पास में न्याय के मूर्त रूप में एक ऐसी चीज विद्यमान है, जिसको हम न्याय कहते हैं। न्याय कानून से परे है। हम पाश्चात्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जो सीमित आदर्श लेते हैं, उसका मूल मंत्र यह है कि प्रतिस्पर्धा के अंतिम परिणाम में - survival of the fittest होगा. सनातन धर्म की व्यवस्था जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शुरू होती है, उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटटेस्ट का कोई ज्ञान नहीं है। हमें वह यह व्यवस्था देनी है कि आप अपनी व्यवस्था में यह न्याय करें कि जो अपने से पीड़ित है, अपने से कमजोर है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था पैदा करें कि वह भी जीवन, स्वावलंबन, स्वाभिमानपूर्वक परिव्यक्त कर सके। इसी परिवल्लित और परिपक्व शासन व्यवस्था का नाम भारत की सरकार का है, जो आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रही है।

मैं व्यवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस व्यवस्था की धुरी पर आज पूरा का पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आपको प्रतिमान की प्रथम पंक्तियों में प्रतिस्पादित करने की प्रतिस्पद्धा में श्रीगणेश कर रहा है, आज वहीं इस सदन के अंदर ऐसा भी पक्ष है, जो इसको नकारना चाहता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करुणा जनित सहानुभूति का उद्देश्य एक सरकार का परम धर्म है। परदुःखकातरता और परोपकार के कार्य में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन है। जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब कुछ पवित्र मनोभावों से प्रभावित, प्रचालित और संचालित होकर आज महापुरुष संघबद्ध होते हैं, तब इस सदन का स्वरूप प्राप्त होता है। इस सदन के माध्यम से समाज के संताप के परिहार की योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं का श्रीगणेश करने के लिए आप और हम यहां एकत्रित हुए हैं।

मैं उन घोषणाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। आपसे चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद के स्वरूप में जो समय मिला है उसका सूत्रपात में अपना अंकेश प्रस्तुत कर सकूं।

हमारे इस सदन में अनेक प्रकार के वक्तव्य आए हैं, लेकिन मैं एक वक्तव्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नौ मूल विचारधाराओं पर आश्रित हमारा यह बजट है। पहली विचारधारा के आधार पर उन्होंने कहा- किसान और कृषि के कल्याण हेतु नवाचार। इस भारत की धरा पर 5104 क्यूबिक किलोमीटर की बरसात होती है। आप इसमें से केवल 10 प्रतिशत पानी का ही संग्रह कर सकते हैं, शेष पानी सागर में चला जाता है। अगर आपको इस अर्थव्यवस्था में किसान को लाभ पहुंचाना है तो आपको नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी होगी। आज इस अर्थशास्त्र की व्यवस्था में जो वित्त विलेखे हैं, उनमें किसान के प्रति संवेदनशीलता और मर्यादित उपक्रम के माध्यम से नवाचार का जो प्रचार किया गया है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने की व्यवस्था है। इन अभिलेखों के माध्यम से किसान के घर, और आम आदमी के घर तक पीने का पानी पहुंचे और किसान के खेत को सिंचाई का पानी मिले, यह हमारी आज की अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता है।

मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमने अर्थव्यवस्था के बारे में कर लगने और कर न लगने के बारे में हर प्रकार की बहस की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पहली बार इस बात का आभास हो रहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतरिक्ष में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। चंद्रयान के मायने से अगर हम साउथ पोल पर गए तो वह विज्ञान का कीर्तिमान था। अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की शुरुआत कर रहे हैं तो यह भी विज्ञान का कीर्तिमान है। हम स्पेस को कॉमर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वर्ष 2023 में स्पेस नीति लेकर आए। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो हॉलीवुड में मूवी बनाने में जितना पैसा लगता है, उतने में तो भारत एक सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकता है। यह इकोनॉमिक फोरम का वह मानचित्र है जो पूरे संसार को अचंभित कर देता है। सौ रुपये में कोई काम होता है तो वह दस प्रतिशत पर मानव संपदा के आधार पर प्रतिपादित हो सकता है। मैं इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्पेस और टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी में इसरो का 15 अगस्त, 1969 को जन्म हुआ तब से अब तक हम 124 स्पेसक्राफ्ट मिशन पूरा कर चुके हैं। 432 फॉरेन सेटेलाइट्स स्थापित कर चुके हैं और 98 लॉन्च की स्थिति में हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब से हमने अपनी अर्थव्यवस्था में स्पेस के लिए नीति बनायी है, हमारे डीपीआईआईटी में 124 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज इस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए आपको वैज्ञानिक परिदृश्य के अंदर उस पूरी अर्थव्यवस्था का मापदंड की पूर्ति करने का एक मानचित्र चाहिए था। आज इसी मानचित्र के आधार पर यह बजट अग्रसर करता है। मैं यह नहीं कहता कि सम्पूर्ण मानचित्र का ब्लू प्रिंट रातों-रात बन गया। सभी वर्गों का और सभी सरकारों का इसमें समय-समय पर योगदान रहा है, लेकिन यह दृष्टि और विज्ञान वर्तमान सरकार का है। इसीलिए इसका परिणाम और पारितोषिक भी इसी सरकार को जाता है।? (व्यवधान) I cannot hear you. Can you speak loudly?

मैं इसके लिए सरकार का आभारी हूँ। इस सदन का भी मैं आभारी हूँ कि मेरा पहली बार इस सदन में आने का सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, मैं उसका नतमस्तक होकर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।

महोदय, मैं सदन से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आप और हम संसार के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं, उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस चरित्र को प्रतिपादित करने की भी क्षमता होनी चाहिए जो दुर्लभ परिस्थितियां हैं, उनको सुलभ बनाने का हमारे पास क्या मानचित्र है? आज हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। आज इस दस्तावेज के आधार पर यह बात मालूम पड़ती है कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम छोटे प्रकार के न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहे हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें प्राइवेट लोग भी निवेश करना चाहेंगे। ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन यह बात आपको और सदन को ध्यान में होनी चाहिए कि वर्ष 1962 एटॉमिक एनर्जी के एक एक्ट के उपरांत वर्ष 1981 में मेकॉनी कमेटी ने यह कहा

कि एक इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर होना चाहिए तो एईआरबी के नाम से आपने रेग्युलेटर पैदा किया, लेकिन वह रेग्युलेटर सैक्शन 27 के माध्यम से आता है। 16,17 और 23 जो एटॉमिक एनर्जी का एक्ट है, वह उसे स्वायत्तता प्रदान नहीं करता है।

अधिकार तो प्रदान करता है इसलिए अगर न्युक्लियर एनर्जी को व्यवस्थित करना है, चूँकि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और अगर न्युक्लियर सिविल लाइबिलिटी के अंदर कोई भी विवाद होगा और अगर आपके इस रेग्युलेटर के पास स्टैच्युटेरी अथॉरिटी नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी व्यक्ति उस पर प्रश्नचिह्न लगा देगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सात बज रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, अगर आप कहेंगे तो मैं कनक्लूड कर दूंगा। I do not disobey any sort of order from anywhere. मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। यहां पर बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की गईं कि अर्थव्यवस्था की इस व्यवस्था के अंदर हमारे पास बाहर से निवेश नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूँ कि जब से भारत सरकार की सिक्वोरिटीज़ को जेपी मॉर्गन के एक इमर्जेंट बॉन्ड इडेक्स में स्थान मिला है, तब से आज की तारीख में 25 बिलियन डॉलर का निवेश आ गया है और लिस्टिंग होने के समय सिर्फ एक हफ्ते के अंदर-अंदर 10 बिलियन डॉलर का निवेश आ गया था। बाहर के बैठे हुए व्यक्ति को आज भी भारत में निवेश करने की पूरी जिज्ञासा है और यहां का प्रतिपक्ष यह बात कहता है कि यहां की अर्थव्यवस्था सही नहीं है। इससे बड़ा और क्या सत्य हो सकता है कि बाहर का व्यक्ति भारत में पैसा लगाने के लिए तैयार है। भारत की अर्थव्यवस्था में मूल रूप से वर्तमान सरकार का जो अपना विजन है, उसको हमने ही नहीं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संसार ने स्वीकार किया है। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।